kanwhizztimes
@kanwhizztimes lucknow
@kanwhizztimes
www.kanwhizztimes.com

कैनविज टाइम्स

सिर्फ सच

❒ वर्ष-15 ❒ अंक-155 ❒ रविवार, 05 जुलाई 2026 ❒ नगर संस्करण ❒ लखनऊ से प्रकाशित एवं दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड में प्रसारित ❒ मूल्य- ₹ 3.00 ❒ पृष्ठ-12

सहकारिता भारत की मूल आत्मा है। यह हमारी सामाजिक चेतना में रची-बसी वह जीवन-दृष्टि है, जो सामूहिक उत्तरदायित्व से आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करते हुए 'अंत्योदय' के संकल्प को साकार करती है। योगी आदित्यनाथ

ममता की फटकार के बाद चंद्रिमा ने बंगाल प्रमुख का पद छोड़ा 11

मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का लोकार्पण व मुनक नहर का किया निरीक्षण 12

टेलीग्राम पायरेसी रोकने के लिए 15 दिन में कार्रवाई करे : सरकार

एजेंसी

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने 'टेलीग्राम' ऐप को नोटिस जारी कर उसके मंच के जरिये 'पायरेटेड' (कॉपीराइट धारक की अनुमति के बिना अवैध रूप से इस्तेमाल कर साझा की गई) फिल्मों, ओटीटी ('ओवर-द-टॉप') सामग्री और अन्य दृश्य-श्रव्य सामग्री के ''बड़े पैमाने पर प्रसार'' पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। सरकारी अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम से इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिन के भीतर देने को कहा है। अधिकारियों ने कहा कि सरकार का यह रुख 'पायरेटेड' सामग्री को टुकड़ों में

हटाने के बजाय ''मंच की जवाबदेही'' तय करने की दिशा में बदलाव को दर्शाता है। ऐसा बताया जा रहा है कि मंत्रालय ने टेलीग्राम से कहा है कि कॉपीराइट का उल्लंघन केवल दीवानी उल्लंघन नहीं, बल्कि कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत फौजदारी अपराध भी है। टेलीग्राम को जून में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की पुनर्परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र लीक को रोकने के लिए भारत में अस्थायी रूप से एहतियातन 'ब्लॉक' (प्रतिबंधित) कर दिया गया था। अधिकारियों ने कहा, ''मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि टेलीग्राम केवल इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि सरकार कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले प्रत्येक चैनल की एक-एक करके पहचान करे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत अपेक्षित समुचित सावधानी बरतने की बात को साबित करने के लिए केवल शिकायत मिलने पर एक-एक चैनल को हटाने का तरीका पर्याप्त नहीं हो सकता। टेलीग्राम को यह नोटिस केंद्र द्वारा हाल में ● शेष पेज 11 पर

शासकीय भूमि से जुड़ा विवाद तीन सदस्यीय विशेष पीठ करेगी सुनवाई

कैनविज टाइम्स ब्यूरो

❒ सीएम योगी के निर्देश पर तत्काल लागू की गई नई व्यवस्था, लखनऊ और प्रयागराज में गठित हुई विशेष बेंच

❒ हर बुधवार को होगी सुनवाई, लंबित और नए सभी वाद होंगे सूचीबद्ध

लखनऊ। योगी सरकार प्रदेश में राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण सुधार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद ने सार्वजनिक महत्व की भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति (यदि कोई हो) से संबंधित सभी वादों की सुनवाई तीन सदस्यीय विशेष पीठ (थ्री मेंबर बेंच) द्वारा की जाएगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

राजस्व परिषद की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने, भूमि विवादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने तथा राजस्व न्याय प्रणाली को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने पर विशेष बल देते रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गयी है। इसका उद्देश्य इन संवेदनशील मामलों के निस्तारण में पारदर्शिता, न्यायिक गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। यह व्यवस्था तत्काल लागू कर दी गई है, जिसके तहत लखनऊ एवं प्रयागराज स्थित राजस्व परिषद न्यायालयों में इन श्रेणी के सभी लंबित और नए वाद अब विशेष रूप से गठित तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। नई व्यवस्था के अनुसार आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति से जुड़े मामलों की सुनवाई अब परिषद की एकल पीठ अथवा सर्किट कोर्ट द्वारा नहीं की जाएगी। इन मामलों पर विशेष रूप से गठित तीन सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। इससे महत्वपूर्ण मामलों में विभिन्न न्यायिक दृष्टिकोणों का समावेश होगा और निर्णय प्रक्रिया अधिक मजबूत, निष्पक्ष तथा न्यायसंगत बन सकेगी।

परिषद की अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग-अलग तीन सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। इससे सरकारी और सार्वजनिक भूमि से जुड़े संवेदनशील प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण संभव होगा, साथ ही पूरे प्रदेश में निर्णय प्रक्रिया में एकरूपता भी स्थापित होगी। वहीं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस श्रेणी के सभी लंबित एवं नए वादों की पहचान कर उन्हें निर्धारित विशेष पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कराया जाए। इससे नई व्यवस्था का प्रभावी ● शेष पेज 11 पर

संक्षेप

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक

नयी दिल्ली। संसद का मानसून सत्र आगामी 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा और इस दौरान करीब 19 बैठकें होनी की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेण रिजिजू ने शनिवार को यह जानकारी दी। श्री रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से बुलाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संसद के दोनों सदनों का मानसून सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। यह सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे। करीब चार सप्ताह तक चलने वाले इस सत्र के दौरान 19 बैठकें होने की संभावना है।

कल होगी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की अहम बैठक

लखनऊ/अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की न्यासी बैठक छह जुलाई (सोमवार) को दोपहर 3:00 बजे अयोध्या धाम स्थित मणि राम दास छावनी में आयोजित होगी। यह बैठक न्यास के अध्यक्ष की अनुमति से कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि द्वारा अत्यावश्यक विषयों पर विचार-विमर्श एवं निर्णय के लिए अल्प सूचना पर बुलाई गई है। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा न्यास के महामंत्री श्री चंपत राय तथा न्यासी डॉ. अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए त्यागपत्रों पर विचार करना है। इसके अलावा न्यास के दान-पात्रों से प्राप्त राशि की गणना के संबंध में गठित एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट भी न्यासियों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। बैठक में आगामी मंदिर प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा होगी। साथ ही वित्त वर्ष 2025-26 के अलेखापरीक्षित आय-व्यय पत्रक, तुलनपत्र एवं अन्य वित्तीय विवरणों की जानकारी प्रस्तुत कर उनकी स्वीकृति पर विचार किया जाएगा। कार्यसूची में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य आवश्यक विषयों को भी शामिल किए जाने का प्रावधान रखा गया है।

संतों ने चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार न करने की मांग की

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या के हजारा मंदिर में आयोजित संत मंडल की बैठक में संतों ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार न करने की मांग की। साथ ही सरकार से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और एसआईटी की रिपोर्ट आने तक किसी निष्कर्ष पर न पहुंचने की अपील की। महंत राघवेश दास वेदांती ने कहा कि दान राशि में कथित गड़बड़ी के आरोपों की सच्चाई एसआईटी जांच के बाद ही सामने आएगी। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने से पहले चंपत राय को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए और उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से भी आय-व्यय का पूरा लेखा-जोखा सार्वजनिक करने की मांग करते हुए कहा कि यदि लोगों के मन में सवाल हैं तो ट्रस्ट को पारदर्शिता के साथ उनका जवाब देना चाहिए।

'संकट की घड़ी में भी संभला रहा भारत'

इच्छाशक्ति, कूटनीति और रिफाइनिंग क्षमता से भारत ऊर्ज़ा संकट से उबरा : प्रधानमंत्री

एजेंसी

बालोतरा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण 21वीं सदी का सबसे बड़ा ऊर्ज़ा संकट पैदा हुआ लेकिन नए भारत की इच्छाशक्ति, समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी रणनीति, संसाधनों के संतुलित उपयोग और कूटनीतिक ताकत के दम पर देश इस संकट से सफलतापूर्वक बाहर निकल आया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई देश ईंधन संकट और बढ़ती कीमतों से जूझ रहे थे, तब भारत ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता तथा कीमतों को नियंत्रित रखा।

राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सार्वजनिक तौर पर कुछ लोग अफवाहें और आशंकाएं फैला रहे थे, तब सरकार दिन-रात हालात संभालने, नीतिगत और कूटनीतिक स्तर पर फैसले लेने तथा संकट से देश को बाहर निकालने में जुटी थी। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का इतिहास कभी न कभी जरूर लिखा जाएगा।

मोदी ने कहा कि युद्ध के कारण घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल पर बड़ा संकट खड़ा हो गया था। उन्होंने बताया कि भारत की लगभग 60 प्रतिशत एलपीजी आवश्यकता आयात से पूरी होती थी और उसमें से 90 प्रतिशत आपूर्ति खाड़ी देशों से होर्मुज़ मार्ग के जरिए आती थी, जो युद्ध जैसे हालात के कारण लगभग रुक गई। इसके बाद सरकार ने रिफाइनरियों की क्षमता का बेहतर उपयोग करने का फैसला किया। जिन रिफाइनरियों में पहले अन्य उत्पाद बनाए जाते थे, उन्हें एलपीजी उत्पादन के निर्देश दिए गए और सात दिनों के भीतर घरेलू एलपीजी उत्पादन 35 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गया। जिन रिफाइनरियों ने पहले कभी एलपीजी का उत्पादन नहीं किया था, उन्हें भी इसके लिए तैयार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि रसोई गैस की पूरी मांग का बोझ केवल एलपीजी पर न पड़े। इसके लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन बढ़ाने का अभियान चलाया गया और बहुत कम समय में 11 लाख से अधिक घरों को पीएनजी से जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार संकट के दौरान घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत दो हजार रुपये तक पहुंच सकती थी लेकिन सरकार ने इसे 950 रुपये से कम कीमत पर उपलब्ध कराया। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर ● शेष पेज 11 पर

रिफाइनिंग क्षमता में वृद्धि

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी तेल शोधन (रिफाइनिंग) क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जबकि कई विकसित देश ऐसा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा, अमेरिका में पिछले 50 वर्षों में एक भी नई रिफाइनरी नहीं बनी। यूरोप की रिफाइनिंग क्षमता लगातार घटी है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनिंग क्षमता वाला देश बन चुका है और यह क्षमता आगे भी बढ़ती रहेगी।

विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा उत्तर प्रदेश: नवीन

कैनविज टाइम्स ब्यूरो

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार को लखनऊ में कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी ताकत से जुटेगी।

लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर में दर्शन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, ल्लयूपी के लोग परिश्रम से जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तम प्रदेश बनाने में लगे हैं। उपमुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम हो रहा है। नितिन नवीन ने कहा कि उत्तर प्रदेश

अब केवल देश का सबसे बड़ा राज्य नहीं, बल्कि देश के विकास को गति देने वाला प्रदेश बनकर उभर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा संगठन और सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में उत्तर प्रदेश अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का पूरा ध्यान संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत करने ● शेष पेज 11 पर

भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू

नयी दिल्ली। भारत और इजरायल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता शनिवार से लागू हो गया। इस समझौते पर दोनों देशों की सरकारों के बीच 08 सितंबर 2025 को नयी दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये थे। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि द्विपक्षीय निवेश समझौता 04 जुलाई 2026 से लागू हो गया है। उसने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा स्थिर निवेश वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि द्विपक्षीय निवेश समझौते से सीमा पार निवेश में वृद्धि होने और भारत तथा इजराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और गहरी होने की उम्मीद है। इस समझौते से व्यापार तथा पारस्परिक निवेश को बढ़ावा मिलने और मध्यस्थता के माध्यम से एक स्वतंत्र विवाद समाधान प्रणाली स्थापित होने ● शेष पेज 11 पर

'स्वदेशी रक्षा प्रणालियों पर दुनिया का भरोसा बढ़ा'

एजेंसी

नयी दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार की 12 वर्षों की यात्रा अभावों से आत्मनिर्भरता की ओर, आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास की ओर और आत्मविश्वास से विकसित भारत के निर्माण की दिशा में प्रगति की रही है।

श्री सिंह ने शनिवार को यहां एक मीडिया संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा, ''पिछले 12 वर्षों में भारत की यात्रा अभावों से आत्मनिर्भरता की ओर, आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास की ओर और आत्मविश्वास से विकसित भारत के निर्माण की ओर प्रगति की रही है।'' उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के

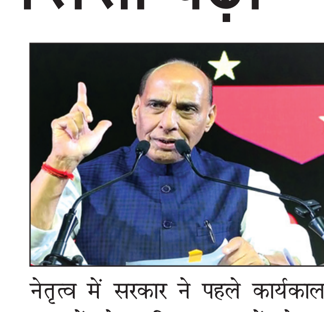

नेतृत्व में सरकार ने पहले कार्यकाल में अभावों को दूर किया, अवसरों को बढ़ाया और कार्य संस्कृति में परिवर्तन किया, दूसरे कार्यकाल में, आकांक्षाओं को उपलब्धियों में परिवर्तित किया और देश को आत्मनिर्भरता के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ाया। तीसरे कार्यकाल में, सरकार ''सुधार, प्रदर्शन, परिवर्तन'' की नीति के माध्यम से ● शेष पेज 11 पर

17 पाकिस्तानी और 6 भारतीय मूल के आतंकवादी घोषित

23 आतंकियों की नई सूची जारी

एजेंसी

नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत पाकिस्तान में सक्रिय 23 व्यक्तियों को 'आतंकवादी' घोषित किया। इनमें लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद के करीबी सहयोगी, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े कई आतंकी शामिल हैं।

सरकारी आदेश के अनुसार, ये आतंकी सुरक्षा बलों पर बड़े हमलों, ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी, सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और आतंकवादी संगठनों में भर्ती कराने जैसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हुए हमलों में शामिल आतंकियों समेत कुल 23 पाकिस्तान स्थित आतंकियों को शनिवार को यूएपीए की अनुसूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही इस सूची में शामिल आतंकवादियों की कुल संख्या 80 हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि ये सभी आतंकी भारत विरोधी गतिविधियों, आतंकी हमलों, आतंक फैलाने, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकी संगठनों की सहायता, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती में शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा, ''आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय ने आज यूएपीए के तहत 23 खूंखार आतंकियों को आतंकवादी घोषित किया है। उन्होंने कहा, '' इन 23 आतंकवादियों में 17 पाकिस्तानी नागरिक और छह भारतीय नागरिक हैं। हालांकि, वर्तमान में सभी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर से आतंकी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। मोदी सरकार भारत और उसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर आतंकी मोड्यूल को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है यूएपीए के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि यदि उसे लगता है कि कोई व्यक्ति आतंकवाद में शामिल है, तो वह उसे आतंकवादी घोषित कर सकती है। इन नामों को सूची में शामिल करने से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को उनके वित्तीय संसाधनों पर रोक लगाने, हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और संपत्तियों को जब्त करने जैसी कार्रवाई करने में मदद मिलती है। लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद के करीबी सहयोगी अब्दुल रऊफ (52) , जो लाहौर में उसके सीधे निर्देश पर काम करता है, तथा राणा इफ्तिखार(54), जो युवाओं को जिहादी गतिविधियों के लिए प्रेरित करता है, को यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। इसके अलावा हाफिज खालिद वलीद, मौलाना सैफुल्लाह खालिद और मौलाना यूसुफ तैबी, जो सईद के संगठन जमात-उद-दावा से जुड़े हैं, को भी सूची में शामिल किया गया है। अशफाक अहमद (52) को बहावलपुर से जैश-ए-मोहम्मद

के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने और धन जुटाने के आरोप में आतंकवादी घोषित किया गया है। संयुक्त सचिव राकेश राठी द्वारा जारी अधिसूचना में मुफ्ती मोहम्मद असगर खान (52) को भी आतंकवादी घोषित किया गया है। उसे पाकिस्तान के अब्बासपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद का 'लॉन्चिंग कमांडर' बताया गया है और 29 नवंबर 2016 को जम्मू के नगरोटा सैन्य शिविर पर हुए आतंकी हमले के प्रमुख साजिशकर्ताओं में माना जाता है। आदेश में कहा गया कि नगरोटा हमले से जुड़े दो अन्य जैश आतंकियों-हाफिज अब्दुल शकूर (56) और अब्दुल्ला जेहादी (47) को भी सूची में शामिल किया गया है। सूची में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों में पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर के पुंछ का मसूद इलियास कश्मीरी (41) और पाकिस्तान के नारोवाल ज़िले के शाकरगढ़ का रहने वाला मोहम्मद मुसादिक (38) शामिल है। मुसादिक 22 अप्रैल, 2022 को जम्मू के सुंजवान में सुरक्षा बलों पर हुए हमले में शामिल था। आदेश के अनुसार, बेंगलुरु का रहने वाला मोहम्मद शहीद फैसल (40) को भी आतंकवादी घोषित किया गया है। वह वर्तमान में रावलपिंडी में छिपा हुआ है और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा तथा आईएसआईएस से जुड़ा बताया जाता है। उस पर सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं की भर्ती, पाकिस्तान में हथियारों का प्रशिक्षण दिलाने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने, 'डेटा एनक्रिप्शन' और फर्जी पहचान का इस्तेमाल सिखाने तथा हथियारों की आपूर्ति और कई आतंकी साजिशों में शामिल रहने का आरोप है। इसके अलावा जैश-ए-मोहम्मद के कई गुटों के प्रमुख इमदाद उल्लाह मक्की, इस्लामाबाद के नजीर अहमद गुज्जर और पंजाब के वसीम नूर जाट को भी सूची में शामिल किया गया है। गुज्जर और जाट पर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में हथियार और गोला-बारूद पहुंचाने तथा युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने के आरोप हैं। लश्कर के आतंकवादी फिरदौस अहमद भट, हारून रशीद गनई, बिलाल अहमद मीर, आबिद कयूम लोन, नजीर अहमद गुज्जर, अब्दुल रऊफ, अशफाक अहमद, हाफिज खालिद वलीद, मौलाना सैफुल्ला खालिद, मोहम्मद याकूब, मोलाना यूसुफ तैबी, ओवैस फरूज, कारी याकूब शेख और राणा इफ्तिखार के नाम भी सूची में जोड़े गए हैं। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''इन व्यक्तियों को औपचारिक रूप से आतंकवादी घोषित करने से उनके ● शेष पेज 11 पर

किसानों की डिजिटल पहचान की ओर तेजी से बढ़ रहा उत्तर प्रदेश

❒ योगी सरकार ने गाजियाबाद और रामपुर में 100 प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया पूर्ण

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से डिजिटल कृषि व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रहा है। किसानों को सरकारी योजनाओं का पारदर्शी और त्वरित लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में चल रही फार्मर रजिस्ट्री अभियान ने अब बड़े स्तर पर परिणाम देना शुरू कर दिया है। यूपी के गाजियाबाद और रामपुर में 100 प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण हो गया है। प्रदेश सरकार की सक्रिय पहल के चलते अब तक 2.38 करोड़ से अधिक किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य का 82.69 प्रतिशत है।प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत 5 नवंबर 2024 से की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए 2,88,70,495 किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वर्तमान प्रगति के अनुसार अब तक 2, 38,72,418 किसानों का नामांकन किया जा चुका है, जबकि लगभग 49,98,007 किसानों का पंजीकरण अभी शेष है। योगी सरकार ने इस अभियान को मिशन मोड में संचालित करते हुए जिला प्रशासन, राजस्व विभाग, कृषि विभाग और स्थानीय स्तर के कर्मचारियों को तेजी से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों का एकीकृत डिजिटल डाटाबेस तैयार करना है, जिससे उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, कृषि अनुदान, ऋण सुविधा और अन्य योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिल सके।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगले 90 दिनों यानी 26 सितंबर 2026 तक लक्ष्य पूरा करना है।प्रदेश सरकार की प्राथमिकता केवल पंजीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि भूमि और किसानों के रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाना भी है। इसी क्रम में ञ्लअंश निर्धारणङ्क का कार्य भी तेजी से चल रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अंश निर्धारण का कार्य 87.53 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। इससे भूमि रिकॉर्ड की शुद्धता बढ़ेगी और भविष्य में विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार फार्मर रजिस्ट्री उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है। इससे सरकार को वास्तविक किसानों की पहचान करने, योजनाओं की मॉनिटरिंग करने और कृषि आधारित नीतियों को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। साथ ही किसानों को सरकारी सहायता प्राप्त करने में भी आसानी होगी। योगी सरकार लगातार तकनीक आधारित प्रशासन को बढ़ावा दे रही है। डिजिटल गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाओं और डेटा आधारित योजना क्रियान्वयन के जरिए उत्तर प्रदेश को आधुनिक और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री अभियान को भी इसी व्यापक परिवर्तन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, जो आने वाले समय में प्रदेश के करोड़ों किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।

जनेश्वर मिश्र की जयंती पर लखनऊ में जुटेंगे प्रदेशभर के प्रबुद्धजन : सांसद सनातन पाण्डेय

कैनविज टाइम्स संवाददाता

प्रयागराज । समाजवादी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र 'छोटे लोहिया' की जयंती के अवसर पर आगामी 5 अगस्त को लखनऊ स्थित ऐतिहासिक जनेश्वर मिश्र पार्क में प्रदेशभर से लाखों समाजवादी कार्यकर्ता और प्रबुद्धजन एकत्रित होंगे। यह जानकारी शनिवार को प्रयागराज शहर में स्थित एक होटल में मीडिया से बात करते हुए बलिया से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद सनातन पाण्डेय ने दी।

उन्होंने कहा कि स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती लोकतंत्र और संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय की स्थापना तथा समाज में आपसी सद्भाव को मजबूत करने के संकल्प के साथ मनाई जाएगी।उन्होंने कहा कि भारत विविध भाषाओं, संस्कृतियों, वेशभूषाओं, खान-पान और जीवन-शैली वाला देश है। ऐसे विविधतापूर्ण राष्ट्र का समग्र विकास समाजवादी विचारधारा के मार्ग पर चलकर ही संभव है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान समय में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर समाज में भ्रम फैलाने, आपसी भाईचारे को कमजोर करने तथा धार्मिक स्थलों और नदियों के नाम पर राजनीति करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। उन्होंने कहा कि देश की ऐतिहासिक परंपरा रही है कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने हमेशा तानाशाही प्रवृत्तियों का लोकतांत्रिक ढंग से विरोध किया है और अब फिर ऐसा करने का समय आ गया है। इससे पूर्व सांसद सनातन पाण्डेय ने जिलेभर से आए प्रबुद्ध समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर 5 अगस्त के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तेखार हुसैन ने की, जबकि संचालन आशुतोष तिवारी ने किया।

घर के अन्दर फंदे से लटका मिला छात्र का शव

प्रयागराज, कैनविज टाइम्स संवाददाता। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित नैनी कोतवाली क्षेत्र के जान्हवी पुरम खरकौनी गांव में शनिवार सुबह घर के अन्दर एक छात्र का शव फंदे से लटका पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है फिर भी मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सहायक पुलिस आयुक्त करछना सुनील कुमार सिंह ने बताया कि नैनी थाना क्षेत्र के जान्हवी पुरम खरकौनी गांव निवासी अनुसुमान सिंह (20) का शव शनिवार को घर के अन्दर फंदे से लटका मिला। परिवार की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए परिवार के लोगों ने बताया कि वह बारहवीं की परीक्षा पास करने के बाद पॉलिटेक्निक करने के लिए बाहर चला गया था, लेकिन एक वर्ष बाद छोड़कर वापस घर लौट आया और स्नातक की पढ़ाई शुरू कर दी थी। लेकिन वह बीते कुछ दिनों से बहुत तनाव में रहता था। आज सुबह घर के अन्दर फंदे से बेटे का शव लटका मिला। पुलिस कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। फिर भी मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

ट्रक की टक्कर से बच्ची की मौत

प्रयागराज, कैनविज टाइम्स संवाददाता। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित उतरांव थाना क्षेत्र के कसिया का पूरा गांव में शनिवार को बेकाबू ट्रक से दबकर पांच वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की।पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि हादसे में प्रयागराज के उतरांव थाना क्षेत्र के कसिया का पूरा गांव निवासी लवकुश की पांच वर्षीय बेटी सुनैना की मौत हुई है। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मृतका के बाबा लालबहादुर ने बताया कि सुनैना शनिवार की सुबह घर के सामने स्थित दुकान से सामान लेकर सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान एक बेकाबू ट्रक ने उसे टक्कर मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गौसंरक्षण नीति को धरातल पर सफल बनाने की दी जनकारी

रायबरेली, कैनविज टाइम्स संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार की गौसंरक्षण नीति को धरातल पर सफल बनाने की दिशा में महराजगंज विकासखंड क्षेत्र की हरदोई ग्राम पंचायत स्थित अस्थायी गौशाला एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सामने आई है। यहां गौवंशों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और प्राकृतिक वातावरण के साथ आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे गौवंश स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहे हैं।आपको बता दें कि, यहां पंजीकृत 370 गौवंशीय के लिए करीब तीन बीघे क्षेत्रफल में फैली इस अस्थायी गौशाला में गौवंशों के लिए गर्मी, सर्दी और बरसात से बचाव हेतु मजबूत शेड बनाए गए हैं। चारा खाने के लिए पर्याप्त संख्या में चरहियां (नांदा) तथा पीने के लिए सीमेंटेड पानी की टंकियों में हर समय स्वच्छ पानी उपलब्ध रहता है। गौवंशों के हरे चारे की व्यवस्था के लिए लगभग 20 बीघा भूमि पर चरी की खेती की गई है, जिससे पशुओं को नियमित रूप से ताजा एवं पौष्टिक हरा चारा मिल सके। गौशाला के संचालन एवं रखरखाव के लिए आठ केयरटेकर तैनात किए गए हैं, जो प्रतिदिन साफ-सफाई, चारा, भूसा, चूनी-चोकर, पशु आहार एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जिम्मा संभालते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से गौशाला के चारों ओर गहरी और ऊंची खाई बनवाई गई है, जिससे कोई भी गौवंश बाहर न निकल सके। गौवंशों के लिए हरा चारा तैयार करने में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। ट्रैक्टर एवं अत्याधुनिक चारा काटने वाली मशीनों से प्रतिदिन ताजा चारा तैयार किया जाता है। इस गौशाला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि, यहां गौवंशों को प्रतिदिन केयरटेकरों द्वारा खुले मैदान में चरने के लिए भी ले जाया जाता है। इससे पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है और वे अधिक सक्रिय एवं स्वस्थ दिखाई देते हैं। जब हमारी टीम ने गौशाला का स्थलीय निरीक्षण किया तो मौके पर लगभग दो ट्रॉली हरा चारा आधुनिक मशीनों से काटा जा रहा था। वहीं स्टोर रूम में पर्याप्त मात्रा में भूसा, लगभग 20 बोरी पशु आहार तथा 12 बोरी चोकर सुरक्षित रूप से उपलब्ध मिला, जिससे गौवंशों के भोजन की समुचित व्यवस्था स्पष्ट रूप से दिखाई दी। गौशाला का संचालन ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुमन चौधरी के नेतृत्व में किया जा रहा है, जबकि अरविंद चौधरी व्यवस्थाओं की निगरानी में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। गौवंशों के स्वास्थ्य की देखरेख पशु चिकित्साधिकारी सुरेश चंद्रा द्वारा की जाती है तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण ग्राम विकास अधिकारी अजीत कुमार के निर्देशन में किया जा रहा है। हरदोई ग्राम पंचायत की यह अस्थायी गौशाला न केवल गौसंरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल है, बल्कि यह भी साबित करती है कि, यदि इच्छाशक्ति, बेहतर प्रबंधन और नियमित निगरानी हो तो गौशालाओं को आदर्श रूप में विकसित किया जा सकता है। यह गौआश्रय स्थल अन्य ग्राम पंचायतों के लिए भी प्रेरणा का केंद्र बनता जा रहा है।

मंडल रेल प्रबंधक, वाराणसी ने मऊ-शाहगंज रेलखंड विंडो का किया निरीक्षण

वाराणसी, कैनविज टाइम्स संवाददाता। यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं गुणवत्तापूर्ण रेल सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंडल रेल प्रबंधक, वाराणसी मंडल, आशीष जैन ने आज 04 जुलाई 2026 को मंडलीय अधिकारियों के साथ मऊ-शाहगंज रेलखंड का विंडो निरीक्षण करते हुए विभिन्न स्टेशनों एवं रेल परिसंपत्तियों का यात्री सुविधा एवं संरक्षा निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने खुरहट-मुहम्मदाबाद के मध्य किमी 16/17-18 पर स्थित एल.एच.एस संख्या-10 का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्षा ऋतु में एलएचएस में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।इसके उपरांत फरियाऽसरायरानी के मध्य स्थित समपार संख्या-40इ का विधिवत संरक्षा निरीक्षण किया गया। इस दौरान समपार पर कार्यरत गेटमैन श्री अनिल राम से संरक्षा संबंधी जानकारी प्राप्त की गई तथा उन्हें सदैव सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। मंडल रेल प्रबंधक ने सरायमीर गुड्स शेड का निरीक्षण करते हुए साफ-सफाई, लोडिंग-अनलोडिंग क्षमता, संरचनात्मक सुरक्षा तथा श्रमिकों के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। इसके बाद फरिहा यार्ड में पॉइंट संख्या-206इ का संरक्षा निरीक्षण करते हुए बोल्ट, नट, क्लिप, फिश प्लेट, गेज, लेवल एवं एलाइनमेंट की जांच की तथा सभी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। फरिहा स्टेशन के निरीक्षण के दौरान स्टेशन परिसर की स्वच्छता, यात्री सुविधाएं, पेयजल व्यवस्था, प्रतीक्षालय, टिकट बुकिंग काउंटर, प्लेटफॉर्म, प्रकाश व्यवस्था, स्टेशन पैनल, रिले रूम, आईपीएस रूम तथा सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया गया।

राजस्व परिषद की नई पहल : न्यायालयों में प्रमाणित स्कैन प्रति से होगी कार्यवाही, मूल अभिलेख रहेंगे सुरक्षित'

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद ने 'राजस्व परिषद के न्यायालयों' में अभिलेखों के सुरक्षित संरक्षण, न्यायिक प्रक्रिया को अधिक दक्ष एवं पारदर्शी बनाने तथा प्रकरणों के त्वरित निस्तारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब राजस्व परिषद के न्यायालयों द्वारा किसी वाद में अभिलेख तलब किए जाने पर सामान्यतः मूल अभिलेखों के स्थान पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई 'प्रमाणित पूर्ण स्कैन प्रति (एद्रन्प्द्धद्वद्वद्ग एधद्वध्यद्गप्द्ग ट्टदथद्बद्वद्गद्ग एधध्भ)' के आधार पर ही न्यायिक कार्यवाही की जाएगी।

'राजस्व परिषद की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल के निर्देशों के क्रम में यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।' इस पहल का उद्देश्य मूल अभिलेखों के सुरक्षित संरक्षण के साथ-साथ न्यायिक कार्यवाही को अधिक दक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाना है। इससे मूल अभिलेखों के बार-बार एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाने की आवश्यकता कम होगी, जिससे उनके क्षतिग्रस्त होने अथवा विलंब से उपलब्ध होने जैसी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

नई व्यवस्था के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रेषित की जाने वाली वाद पत्रावली की स्कैन प्रति में प्रत्येक पृष्ठ, परिशिष्ट, मानचित्र, नोटशीट, आदेश पत्रक एवं अन्य समस्त संलग्न अभिलेख क्रमवार एवं स्पष्ट रूप से सम्मिलित किए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक स्कैन प्रति के साथ संबंधित 'राजस्व रिकॉर्ड कीपर (आरआरके)' द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।

राजस्व परिषद ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी विशेष वाद में 'राजस्व परिषद का न्यायालय' कारण अभिलिखित करते हुए मूल अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश देता है, तभी मूल अभिलेख उपलब्ध कराए जाएंगे। अन्य सभी मामलों में प्रमाणित पूर्ण स्कैन प्रति के आधार पर ही कार्यवाही की जाएगी। व्यवस्था की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी स्तर पर अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा अप्रमाणित स्कैन प्रति प्रेषित की जाती है, तो संबंधित 'राजस्व रिकॉर्ड कीपर (आरआरके)' को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी मानते हुए उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी। विभाग ने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस नई व्यवस्था से तत्काल अवगत कराते हुए इसका प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही राजस्व परिषद के न्यायालयों द्वारा तलब की गई पत्रावलियों की प्रमाणित स्कैन प्रतियां निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। यह पहल 'राजस्व परिषद के न्यायालयों' में डिजिटल अभिलेख प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने, मूल अभिलेखों के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने तथा न्यायिक कार्यप्रणाली को आधुनिक तकनीक के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य में इस पूरी प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन संचालित किए जाने की भी तैयारी की जा रही है, जिससे न्यायिक कार्यवाही और अधिक सुगम, पारदर्शी एवं प्रभावी बन सकेगी।

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

हमीरपुर । उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में विशेष न्यायालय (पोक्सो एक्ट) के अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने शनिवार को एक गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायालय ने नाबालिग लड़की से जबरन दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपित बसन्त वर्मा को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजक एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को शाम बताया कि पीड़िता (16) अपने माता-पिता के साथ ग्राम सुरील स्थित एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने गई थी। वहीं पर आरोपित बसन्त वर्मा (पुत्र गंगाराम, निवासी ग्राम भरखरी, थाना बिंवार, हमीरपुर) भी अपने परिवार के साथ काम करता था। अप्रैल 2021 में आरोपी ने मौका पाकर पीड़िता को अपनी झुग्गी में बुलाया और उसके साथ जबरन गलत काम (दुष्कर्म) किया तथा उसका वीडियो भी बना लिया। इसके बाद आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल करता रहा। नवंबर 2021 में जब पीड़िता अपने गांव वापस आई, तब भी आरोपी ने उसे डरा-धमकाकर पुनः गलत काम किया।

गोल्डी हत्याकांड के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग, 5 जुलाई को विहिप निकालेगा कैंडल मार्च

कैनविज टाइम्स संवाददाता

प्रयागराज। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) 5 जुलाई कैंडल मार्च निकालेगा। ये मार्च गोल्डी हत्याकांड के आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई तथा मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की मांग को लेकर होगी। कैंडल मार्च 5 जुलाई की शाम 6:30 बजे सरस्वती शिशु मंदिर, जारी बाजार से कृषक इंटर कॉलेज, गढ़ैया तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा।

यह जानकारी शनिवार को विश्व हिंदू परिषद, गोरक्षा काशी प्रांत के प्रांत मंत्री लाल मणि तिवारी ने दी। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से बड़ी संख्या में इसमें शामिल होने की अपील की है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कैंडल मार्च की तैयारियों को लेकर शंकरगढ़, बारा, लालापुर, नारीबारी, गौहनिया, मिश्राबांध, जारी बाजार और कौंधियारा सहित विभिन्न क्षेत्रों में बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने पर चर्चा की। श्री तिवारी ने कहा कि संगठन की मांग है कि मामले में सभी आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए तथा दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी स्तर पर पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आती है तो उनके विरुद्ध भी निष्पक्ष विभागीय जांच कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि कैंडल मार्च का उद्देश्य मृतका गोल्डी को श्रद्धांजलि अर्पित करना तथा न्याय की मांग को शांतिपूर्ण तरीके से उठाना है। संगठन का कहना है कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसे मामलों में त्वरित न्याय की आवश्यकता है। इस अभियान की तैयारियों में विश्व हिंदू परिषद के गोरक्षा प्रांत उपाध्यक्ष वीरेंद्र जायसवाल, देवव्रत द्विवेदी, राम कैलाश पांडे, संदीप केसरवानी, गजेंद्र पांडे, मुन्ना बरेटिया, विपिन मिश्रा, शिवाकांत सहित विभिन्न क्षेत्रों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। संगठन ने क्षेत्र के लोगों से अधिक से अधिक संख्या में कैंडल मार्च में शामिल होकर अपनी सहभागिता दर्ज कराने की अपील की है।

वन कानूनों की जानकारी देने गांव-गांव पहुंचेगा वन विभाग, लगेगी ग्रीन चौपाल

मीरजापुर । कैमूर वन्यजीव प्रभाग की प्रभागीय वनाधिकारी आरूषि मिश्रा ने शनिवार को हलिया ब्लाक सभागार में वन क्षेत्र से सटे गांवों के लोगों को वन संरक्षण और वन कानूनों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि वन एवं वन्यजीव देश की अमूल्य धरोहर हैं और इनके संरक्षण में जनसहभागिता बेहद जरूरी है। अनजाने में कानून का उल्लंघन करने से भी लोगों पर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है, इसलिए नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने वन एवं काश्त भूमि के स्पष्ट सीमांकन की मांग उठाई। ग्राम पंचायत कुसियरा के प्रधान सुक्खी सिंह ने बताया कि सीमांकन स्पष्ट नहीं होने से कई बार ग्रामीणों और वन विभाग के बीच विवाद की स्थिति बन जाती है।

नंदी के पुनरप्राप्ति जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर कोरावं में बैठक

कैनविज टाइम्स संवाददाता

कोराव, प्रयागराज। प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' के 12 जुलाई को आयोजित होने वाले पुनर्प्राप्ति जन्मोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शनिवार को कोराव में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मंत्री के प्रतिनिधि अनिल कुमार केसरवानी (झल्लर) और ओमकार केशरी (प्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य) मुख्य रूप से मौजूद रहे। अध्यक्षता निवर्तमान चेयरमैन नरसिंह केशरी ने की। संचालन अधिवक्ता एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष (भाजपा) पंकज केशरी ने किया, जबकि समापन अधिवक्ता एवं प्रधान पद प्रत्याशी (ग्राम पंचायत बड़ोखर) सत्यम केशरी ने किया। बैठक में जन्मोत्सव कार्यक्रम को भव्य एवं सफल बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं तथा अधिक से अधिक जनसहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया।

इस दौरान संजय केसरी (पप्पू भैया), बबलू केसरी जारी, कृष्ण कुमार केसरी (बच्चा), विनीत जायसवाल, सुरेन्द्र केशरी , नीरज केशरी, भागीरथी केशरी सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे।

योगी सरकार की मुफ्त आईएएस-पीसीएस आवासीय कोचिंग योजना बनी युवाओं की उम्मीद

कैनविज टाइम्स संवाददाता

❒ 5 जुलाई को होगी प्रवेश परीक्षा, 1 अगस्त से शुरू होंगी कक्षाएं- 10,175 अभ्यर्थी देंगे प्रवेश परीक्षा, सात आवासीय कोचिंग सेंटरों में मिलेगी मुफ्त सुविधा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब व मेधावी युवाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में संचालित निःशुल्क आईएएस-पीसीएस आवासीय कोचिंग योजना बड़ी राहत बनकर सामने आई है। समाज कल्याण विभाग की इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूरी तरह निःशुल्क कराई जाएगी।

10,175 अभ्यर्थी देंगे प्रवेश परीक्षा

5 जुलाई 2026 को प्रदेश के सभी मंडलों में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में कुल 10,175 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। परीक्षा के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश के विभिन्न आवासीय कोचिंग सेंटरों में प्रवेश दिया जाएगा। नियमित कक्षाएं 1 अगस्त 2026 से प्रारंभ होंगी, जबकि यह शैक्षणिक सत्र 31 मई 2027 तक संचालित किया जाएगा।

सात आवासीय कोचिंग सेंटरों में मिलेगी मुफ्त सुविधा

प्रदेश के सात आवासीय कोचिंग सेंटरों में कुल 865 चयनित छात्र-छात्राओं को निशुल्क आवासीय सुविधा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। इनमें से 25 प्रतिशत सीटें ऐसे छात्र-छात्राओं के लिए आरक्षित हैं जो लेटरल एंट्री के माध्यम से प्री परीक्षा क्वालीफाई कर चुके हैं। चयनित अभ्यर्थियों को रहने, खाने, पुस्तकें, स्टडी मटेरियल और अनुभवी शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन जैसी सभी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का उद्देश्य है कि प्रतिभाशाली छात्र आर्थिक अभाव के कारण अपने सपनों से समझौता न करें।

गरीब और होनहार युवाओं को मिलेगा आगे बढ़ने का अवसर

यह योजना केवल कोचिंग कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने का बड़ा प्रयास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि आर्थिक तंगी किसी भी प्रतिभाशाली छात्र के भविष्य में बाधा न बने। इसी उद्देश्य से सरकार गरीब और होनहार युवाओं को निशुल्क आवासीय कोचिंग उपलब्ध करा रही है, ताकि वे यूपीएससी और यूपीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकें।

गरीबों के बीच पहुंचे विधायक श्याम सुंदर भारती सुनीं समस्याएं, समाधान का दिया भरोसा

कैनविज टाइम्स संवाददाता

रायबरेली। महराजगंज विकास खंड क्षेत्र के अलरगंज मजरे बावन बुजुर्ग बल्ला गांव में बछरावां विधानसभा के विधायक श्याम सुंदर भारती ग्रामीणों का हालचाल जानने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांव का भ्रमण कर लोगों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना।

ग्रामीणों ने विधायक के सामने बिजली व्यवस्था सहित अन्य मूलभूत समस्याएं रखीं। मौके पर स्थिति का जायजा लेने के बाद विधायक श्याम सुंदर भारती ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से तत्काल फोन पर वार्ता कर समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। गांव में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था न होने की समस्या को देखते हुए विधायक ने हाईमास्ट लाइट लगवाने की घोषणा भी की, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने विधायक के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि पहली बार किसी जनप्रतिनिधि ने गांव पहुंचकर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके समाधान के लिए तत्काल पहल की।विधायक श्याम सुंदर भारती ने कहा कि क्षेत्र के प्रत्येक गांव का विकास उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बिजली, सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। विधायक के दौरे और त्वरित कार्रवाई से ग्रामीणों में उत्साह और संतोष का माहौल देखने को मिला। लोगों ने उम्मीद जताई कि गांव की लंबित समस्याओं का जल्द समाधान होगा और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।

विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह के नेतृत्व में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का सरोजनीनगर में भव्य स्वागत

❐ डॉ. राजेश्वर सिंह ने दोहराया राष्ट्रीय अध्यक्ष का विश्वास—2027 में पुनः खिलेगा कमल, उत्तर प्रदेश बनेगा 'उत्तम प्रदेश'

कैनविज टाइम्स संवाददाता।

सरोजनीनगर, लखनऊ। सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह के नेतृत्व में सरोजनीनगर परिवार ने भारतीय जनता पार्टी के दूरदर्शी, कर्मठ एवं ओजस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नबीन जी का सरोजनीनगर की पावन धरती पर भव्य स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व ग्रहण करने के उपरांत यह उनका प्रथम उत्तर प्रदेश आगमन था, जिसने प्रदेशभर के कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह, गौरव और ऊर्जा का संचार किया। इस अवसर पर आयोजित भव्य रोड शो में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं, किसानों एवं आमजन ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुष्पवर्षा से अभिनंदन किया। पूरे मार्ग पर अभूतपूर्व जनसमर्थन, उत्साह और संगठनात्मक एकजुटता का अनुपम दृश्य देखने को मिला। अपने संबोधन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी ने कहा कि पिछली बार लखनऊ आगमन की तुलना में इस बार किसानों एवं जनसामान्य का जो अपार स्नेह, आत्मीयता और विश्वास प्राप्त हुआ है, वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश की धरती पर पुनः कमल खिलेगा तथा उत्तर प्रदेश 'उत्तम प्रदेश' के रूप में विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास, सुशासन और जनकल्याण की नई दिशा प्रदान की है। काशी, अयोध्या और मथुरा सहित संपूर्ण उत्तर प्रदेश आज विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्नदाताओं एवं आमजन में दिखाई दे रहा उत्साह इस बात का प्रमाण है कि वर्ष 2027 के लिए जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ और अधिक सुदृढ़ हुआ है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबोधन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के शब्द केवल एक राजनीतिक वक्तव्य नहीं, बल्कि प्रदेश के अन्नदाताओं, कार्यकर्ताओं और करोड़ों नागरिकों की आकांक्षाओं का सशक्त प्रतिबिंब हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को 'उत्तम प्रदेश' बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की भावना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का दूरदर्शी नेतृत्व इस संकल्प को नई गति प्रदान करेगा।

डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई विकास, सुशासन और जनकल्याण की यात्रा को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी के मार्गदर्शन में संगठनात्मक शक्ति का नया आयाम प्राप्त होगा। उनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का उत्साह, जनसंपर्क और जनसेवा का संकल्प और अधिक सुदृढ़ होगा। उन्होंने कहा कि सेवा ही संगठन की सबसे बड़ी शक्ति है तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर प्रथम आगमन प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए गौरव, प्रेरणा और उत्साह का विषय है। सरोजनीनगर की भूमि सदैव सेवा, संगठन और राष्ट्र निर्माण के संकल्प की साक्षी रही है तथा इस पावन भूमि पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करना समस्त सरोजनीनगर परिवार के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है।

यूपी एटीएस ने बंगाल से जाली नोट तस्कर को किया गिरफ्तार

कैनविज टाइम्स संवाददाता

जाकिर पुत्र आजीद अली

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने भारतीय जाली नोटों की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से गिरफ्तार किया है। उस पर 25 हजार रुपये के इनाम था।

एटीएस ने शनिवार को जारी विज्ञप्ति में बताया कि कुछ दिनों से यह सूचनाएं मिल रही थीं कि बांग्लादेश में छपी भारतीय जाली नोटों की तस्करी पश्चिम बंगाल के रास्ते उत्तर प्रदेश समेत भारत के अन्य राज्यों में की जा रही है। मामले को संज्ञान लेकर एटीएस ने जांच शुरू की और बीते दिनों वाराणसी से सुलेमान अंसारी और इदरीश को दो लाख के जाली नोटों के साथ पकड़ा था। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि बांग्लादेश में छपी भारतीय जाली नोटों को पश्चिम बंगाल में मालदा जिला के रहने वाल जाकिर उन्हें उपलब्ध कराता था। जाकिर तक यह नोट बांग्लादेश निवासी रफीकुल पहुंचाता था। इसके बाद यह भारतीय जाली नोट जाकिर हम लोगों की मदद से उत्तर प्रदेश समेत भारत के अलग-अलग राज्यों में सप्लाई करवाता था।

एटीएस ने शुक्रवार को मालदा पहुंचकर आरोपित जाकिर को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया के तहत वाराणसी लाकर पूछताछ शुरू कर दी है। एटीएस का कहना है कि अभियुक्त के पास से मिली जानकारी के आधार पर अन्य सदस्यों के संबंध में और अधिक जानकारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उपमुख्यमंत्री ने अर्पित की श्रद्धांजलि

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को महान संत, दार्शनिक, राष्ट्रचिंतक एवं युवा प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि (स्मृति दिवस) के अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा, आध्यात्मिक चेतना, मानव कल्याण और युवाओं को आत्मविश्वास एवं चरित्र निर्माण की प्रेरणा देने के लिए समर्पित रहा। उनके विचार आज भी करोड़ों युवाओं के लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरणास्रोत हैं। पमुख्यमंत्री श्री मौर्य ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा और सार्वभौमिक मानवता के संदेश को पूरे विश्व में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा था कि राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा आधार जागरूक, शिक्षित, संस्कारित और आत्मविश्वासी युवा है। आज आवश्यकता है कि प्रत्येक नागरिक, विशेष रूप से युवा वर्ग, उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात कर राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाए। श्री मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार भारत के सभी महापुरुषों, संतों, समाज सुधारकों और राष्ट्रनिर्माताओं के योगदान का सम्मान कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने महापुरुषों के नाम पर राजनीति और सत्ता पाने का काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उचित सम्मान और स्मरण दिया जा रहा है, ताकि नई पीढ़ी उनके आदर्शों और विचारों से प्रेरणा प्राप्त कर सके। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए देश और देशवासी सर्वोपरि हैं।

उनकी सरकार का प्रत्येक निर्णय राष्ट्रहित, जनकल्याण, गरीबों के उत्थान और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प से प्रेरित है। डबल इंजन सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अंत में श्री मौर्य ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रभक्ति, सेवा, समरसता, आत्मानुशासन और मानवता के आदर्शों को अपनाकर विकसित भारत एवं विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यही स्वामी विवेकानंद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम की सख्त कार्रवाई

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखनऊ। नगर निगम लखनऊ ने शहर में बढ़ते अवैध अतिक्रमण और यातायात अवरोध की समस्या को गंभीरता से लेते हुए शनिवार को सघन अभियान चलाया। नगर आयुक्त गौरव कुमार के आदेश पर चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य प्रमुख सड़कों, सार्वजनिक स्थलों, नालों के आसपास और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कर नागरिकों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है।

जोन-3 में जोनल अधिकारी मनोज यादव के निर्देश पर 296 टीम के साथ अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अवैध कब्जों और अस्थायी अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीम ने सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करने वालों को हटाते हुए क्षेत्र को व्यवस्थित कराया।

अभियान के तहत जानकीपुरम थाने के पास स्थित अर्जुन पार्क के दोनों ओर लगने वाली सब्जी मंडी को अन्य स्थान पर शिफ्ट किए जाने के लिए स्थल निरीक्षण किया गया। नगर निगम की टीम ने मौके की स्थिति का जायजा लिया, ताकि सड़क पर लगने वाली भीड़ और यातायात अवरोध की समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके।

नगर निगम की टीम ने हनुमान सेतु से इंदिरा ब्रिज तक व्यापक अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से लगाए गए करीब 25 से 30 ठेले तथा 6 गुमटियां हटाई गईं। इससे मार्ग पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

मसालची टोला क्षेत्र में नाले के बगल में टीन शेड लगाकर किए गए कथित अवैध कब्जे और अतिक्रमण के विरुद्ध भी अभियान चलाया गया। मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई और व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय पुलिस विभाग को पत्र भेज दिया गया है।

दुष्कर्म पीड़िता ने चिनहट में मारपीट और जानलेवा हमले का लगाया आरोप, एफआईआर दर्ज कराने की मांग

चिनहट, लखनऊ, कैनविज टाइम्स संवाददाता। बाराबंकी निवासी एक युवती ने चिनहट थाना क्षेत्र में अपने साथ मारपीट, धमकी और जानलेवा हमले का आरोप लगाते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। पीड़िता का आरोप है कि दुष्कर्म के मामले में नामजद आरोपी और उसके साथियों ने उसे केस वापस लेने का दबाव बनाया तथा विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। शिकायत के अनुसार, पीड़िता ने पहले बाराबंकी के मसौली थाने में आरोपी मो. शोहेल के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेल और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी जेल जाने के बाद जमानत पर रिहा हुआ और लगातार मुकदमा वापस लेने की धमकी देने लगा। पीड़िता का कहना है कि 28 फरवरी 2026 को वह अपनी सहेली के साथ लखनऊ में वकील से मिलने आई थी। वापस लौटते समय कन्ता चौराहे के पास चार लोगों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि आरोपियों ने दोनों के साथ गाली-गलौज करते हुए बेरहमी से मारपीट की, जिसमें पीड़िता बेहोश हो गई। बाद में उसे लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस ने मामले में उचित कार्रवाई नहीं की और शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। अब उसने पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ और अन्य अधिकारियों से आरोपी मो. शोहेल सहित चार लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने, मेडिकल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में शामिल करने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

निर्माणाधीन मकान से गैस सिलेंडर व घरेलू सामान चोरी, मजदूर पर आरोप

चिनहट, लखनऊ, कैनविज टाइम्स संवाददाता। चिनहट थाना क्षेत्र के बदवानी विहार धावा स्थित एक निर्माणाधीन मकान से करीब 40 हजार रुपये मूल्य का घरेलू सामान चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर के अनुसार, आदिल नगर कुर्सी रोड निवासी देवेंद्र प्रताप उपाध्याय का बदवानी विहार में निर्माणाधीन मकान है। मकान की देखरेख के लिए वहां लेबर सुनील उर्फ श्याम सिंह निवासी मल्हावां, हरदोई रह रहा था। आरोप है कि शाम करीब छह बजे आरोपी निर्माणाधीन मकान से दो भरे हुए गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, किचन का सामान, कुर्सियां, स्टील व लकड़ी की मेज, बाल्टी, बर्तन समेत लगभग 40 हजार रुपये का सामान ई-रिक्शा में लादकर चोरी कर ले गया। पीड़ित का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में आरोपी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चोरी का सामान ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। अगले दिन पड़ोसियों से सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचा तो मकान से पूरा सामान गायब मिला। पीड़ित की शिकायत पर चिनहट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

निगोहां में रफ्तार का तांडव: तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, 100 मीटर तक घसीटा, चालक समेत दो गंभीर रूप से घायल

निगोहां, लखनऊ, कैनविज टाइम्स संवाददाता। निगोहां कस्बे में शुक्रवार देर रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने सामने से आ रहे ऑटो में इतनी जोरदार टक्कर मारी कि ऑटो ट्रक के अगले हिस्से में फंस गया और करीब 100 मीटर तक घसीटता चला गया। इस भीषण हादसे में ऑटो चालक समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शुक्रवार देर रात निगोहां कस्बे के मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक सामने से आ रहे ऑटो से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो ट्रक में फंस गया, लेकिन चालक ने वाहन रोकने के बजाय उसे काफी दूर तक घसीट दिया। सड़क पर यह भयावह मंजर देखकर लोगों में दहशत फैल गई। हादसे में ऑटो चालक अंशू चौरसिया तथा ऑटो में सवार मोहम्मद जमील उर्फ बब्लू, दोनों निवासी बैरीसालपुर, मोहनलालगंज, गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही निगोहां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और टोल एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निगोहां पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद परिजन दोनों को बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए, जहां ऑटो चालक अंशू चौरसिया की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना के कारण मुख्य मार्ग पर काफी देर तक यातायात बाधित रहा। पुलिस ने क्रेन बुलाकर क्षतिग्रस्त ऑटो और ट्रक को सड़क से हटवाया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। निगोहां पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दुर्घटना के कारणों की गहन जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया पर अवैध खनन का वीडियो वायरल होते ही प्रशासन का एक्शन

कैनविज टाइम्स संवाददाता

निगोहां, लखनऊ। निगोहां थाना क्षेत्र के इमलियाखेड़ा गांव में सरकारी भूमि पर अवैध खनन का मामला सोशल मीडिया पर वीडियो और खबर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए मोहनलालगंज तहसील प्रशासन की तहरीर पर निगोहां पुलिस ने अर्पित मिश्रा समेत अन्य अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, सरकारी भूमि पर बिना किसी वैध अनुमति के जेसीबी मशीनों से बड़े पैमाने पर मिट्टी का खनन किया जा रहा था। खुदाई की गई मिट्टी को दर्जनों डंपरों के जरिए अन्य स्थानों पर भेजा जा रहा था। इस अवैध खनन से सरकारी भूमि को नुकसान पहुंचने के साथ ही राजस्व विभाग को भी आर्थिक क्षति हुई।

बताया जा रहा है कि कई दिनों से चल रहे इस अवैध खनन का वीडियो और समाचार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। राजस्व विभाग ने मौके की जांच कर पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तैयार की और निगोहां पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। तहरीर के आधार पर निगोहां पुलिस ने अर्पित मिश्रा एवं उनके अन्य अज्ञात साथियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और इस अवैध खनन में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है। थाना प्रभारी निरीक्षक अनुज तिवारी ने बताया कि तहसील प्रशासन से प्राप्त तहरीर के आधार पर अर्पित मिश्रा समेत अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सोशल मीडिया के माध्यम से मामला सामने नहीं आता, तो सरकारी भूमि को और अधिक नुकसान पहुंच सकता था। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

सशक्त महिला ही परिवार, समाज और राष्ट्र की सच्ची शक्ति होती है: शुभांगी सिंह

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखनऊ। भारत विकास परिषद प्रगति शाखा ने रेड रोज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गोमती नगर में ''महिला सशक्तिकरण'' विषय पर एक प्रेरणादायी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक एम. के. दीक्षित ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवध प्रांत के ''विकास रत्न'' से सम्मानित व्यक्तित्व यू.एन. श्रीवास्तव थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में शंकर चरण अस्थाना, अध्यक्ष लोकमान्य शाखा, उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महिला विकास एवं कल्याण अधिकारी, प्रगति शाखा की मुख्य संस्थापिका मंजू सिंह की उपस्थिति रही। संचालन के. सी. पंत ने किया। मुख्य वक्ता सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, महिला विकास कल्याण शुभांगी सिंह ने छात्राओं को संबोधित करते हुए महिला शिक्षा, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, समान अधिकार एवं नेतृत्व क्षमता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षित एवं सशक्त महिला ही परिवार, समाज और राष्ट्र की सच्ची शक्ति होती है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक को भारत विकास परिषद, प्रगति शाखा की ओर से स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। विद्यालय की छात्राओं ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए महिला सशक्तिकरण का संदेश आत्मसात किया। विद्यालय परिवार ने भारत विकास परिषद, प्रगति शाखा तथा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उपस्थित सभी लोगों ने यह संकल्प लिया कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर और सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम का समापन इस प्रेरक संदेश के साथ हुआ–''जब महिलाएँ सशक्त होती हैं, तभी राष्ट्र समृद्ध और प्रगतिशील बनता है।''

एसडीएम के खिलाफ बीकेटी बार का बिगुल, न्यायालय का बहिष्कार शुरू

❐ काली पट्टी बांधकर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन, स्थानांतरण तक न्यायिक कार्य से दूरी का ऐलान

कैनविज टाइम्स संवाददाता

बख्शी का तालाब, लखनऊ। बख्शी का तालाब बार एसोसिएशन ने उपजिलाधिकारी साहिल कुमार की कार्यप्रणाली के विरोध में शनिवार को उनके न्यायालय का बहिष्कार शुरू कर दिया। अधिवक्ताओं ने सामूहिक अवकाश लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि जब तक उपजिलाधिकारी का स्थानांतरण नहीं होगा, तब तक उनके न्यायालय में कोई अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेगा।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह ने बताया कि उपजिलाधिकारी की तैनाती 4 अगस्त 2025 को हुई थी। आरोप है कि तब से न्यायालय में बड़ी संख्या में पत्रावलियां लंबित हैं। मामलों का समयबद्ध निस्तारण नहीं किया जा रहा है और शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण सहित विभिन्न प्रकरणों में भी अनावश्यक विलंब हो रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि इससे वादकारियों और क्षेत्रीय जनता को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।बार एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया कि उपजिलाधिकारी आमजन और अधिवक्ताओं से मिलने से बचते हैं तथा अधिकांश समय चैंबर बंद रखकर कार्य करते हैं। एसोसिएशन का कहना है कि इन समस्याओं को लेकर पहले भी जनप्रतिनिधियों और जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन अब तक न तो कार्यप्रणाली में सुधार हुआ और न ही कोई प्रशासनिक निर्णय लिया गया।आशीष कुमार सिंह ने बताया कि तीन जुलाई को बार एसोसिएशन की आमसभा में सर्वसम्मति से आंदोलन का निर्णय लिया गया था। इसके तहत शनिवार से उपजिलाधिकारी के न्यायालय का बहिष्कार शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र स्थानांतरण नहीं किया गया तो उच्च अधिकारियों से मिलकर पुनः ज्ञापन सौंपा जाएगा और आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में समझौते का दबाव, महिला व उसके पिता से मारपीट का आरोप

चिनहट, लखनऊ। राजधानी लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में समझौता न करने पर महिला और उसके पिता के साथ मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने इस संबंध में बख्शी का तालाब थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके पति मुजम्मिल, ससुर अब्दुल करीम समेत अन्य ससुरालीजनों द्वारा पहले दहेज को लेकर मारपीट की गई थी। इस मामले में न्यायालय के आदेश पर चिनहट थाने में 18 जून 2026 को मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा पीड़िता ने परिवार न्यायालय में गुजारा भत्ता तथा घरेलू हिंसा का वाद भी दाखिल किया है। पीड़िता के अनुसार, 2 जुलाई 2026 की सुबह वह अपने पिता के साथ बाराबंकी जाने के लिए घर से निकली थी। रास्ते में उत्तरधौना गांव के पास उसके पति, ससुर और दो अज्ञात लोगों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि आरोपियों ने मुकदमे में समझौता करने का दबाव बनाया। विरोध करने पर महिला और उसके पिता के साथ मारपीट की गई तथा गाली-गलौज की गई। पीड़िता का कहना है कि शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग निकले।

समर शोकेस-2026: नृत्य-संगीत की शानदार प्रस्तुतियों से सजा मंच, बच्चों और माताओं ने बिखेरा प्रतिभा का रंग

❐ दीपिका बिष्ट ने 'मदर्स रैम्प वॉक' व 'मदर्स रैम्प वॉक विद किड्स' का खिताब जीता, लतिका और अपर्णा रहीं रनरअप

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखनऊ। सिटी स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की ओर से 'समर शोकेस-2026' का भव्य आयोजन गोमतीनगर के विभूतिखंड स्थित ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं ने नृत्य, संगीत एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं 'मदर्स रैम्प वॉक' और 'मदर्स रैम्प वॉक विद किड्स' कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभुनाथ राय ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अभिभावकों का समय और संस्कार सबसे महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की गलतियों पर डांटने के बजाय उन्हें प्रेमपूर्वक समझाना चाहिए, जिससे उनका आत्मविश्वास और बौद्धिक विकास बेहतर होता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने और समाज सेवा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने का भी आह्वान किया। कार्यक्रम की आयोजक दिव्या शुक्ला ने बताया कि समर शोकेस का उद्देश्य बच्चों एवं युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए मंच उपलब्ध कराना और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि इस बार माताओं को भी मंच देकर उनकी छिपी प्रतिभा को सामने लाने का प्रयास किया गया। मदर्स रैम्प वॉक' और 'मदर्स रैम्प वॉक विद किड्स में दीपिका बिष्ट विनर रहीं। तो वहीं फर्स्ट रनरअप लतिका व सेकेंड रनरअप अपर्णा रही। इस अवसर पर राहुल गुप्ता व विवेक बदलानी अति विशिष्ट अतिथि एवं अनुराग श्रीवास्तव, शम्सुर रहमान, अमृत सिन्हा, डॉ. आकांक्षा श्रीवास्तव, रागिनी श्रीवास्तव, चंद्रशेखर (आईएएस), अजय कुमार मिश्रा, अरुण प्रताप सिंह एवं सुनीता भटनागर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। निर्णायक मंडल में कविता सचिन शुक्ला, गुंजन वर्मा और सुनीता राजपूत शामिल रहीं।

इन प्रतिभागियों ने दिखाई प्रतिभा

कार्यक्रम में काव्या गुप्ता, नित्या अवस्थी, वानीश्री सिंह, हिमाची, अनिका, आकृति, सृष्टि, प्रिशा, अनाया, नायशा, शान्वी वर्मा, आध्या गुप्ता, युग, काव्या राणा, श्रावणी, कौशिक, आरिका, संघवी सिंह, नीति, सुविज्ञा, अनुष्का, कनिष्का, दिया, प्रिया, मुस्कान, ओजस्वी रॉय, कनिष्का बिष्ट, मिशिका, वृद्धि, संविधि, अनिका गौर, आराध्या कनक, समृद्धि नारायण पांडेय, वागीशा मिश्रा, स्वास्तिका सिंह, अनन्या कनक, कनिका गुप्ता और दिव्यांश साहू सहित अनेक प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं।

कंदुवापुर में कथित भ्रष्टाचार का जिन्न फिर बाहर

- 3.97 लाख के संदिग्ध भुगतान पर उठे गंभीर सवाल, जिम्मेदारों की चुप्पी पर भड़के ग्रामीण

कैनविज टाइम्स संवाददाता

मछरेहटा, सीतापुर। विकास खंड मछरेहटा की ग्राम पंचायत कंदुवापुर एक बार फिर कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सुर्खियों में है।

सूत्रों की माने तो विकास कार्यों के नाम पर हुए संदिग्ध भुगतानों और कथित फर्जीवाड़े को लेकर विभागीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई न होने से ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कथित भ्रष्टाचार फाइलों में दफन कर पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, जबकि समाचार पत्र में मामला प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा।ग्रामीणों के अनुसार, जून 2026 में मात्र तीन किस्तों में ?3,97,000 का भुगतान किया गया, लेकिन इस भुगतान का स्पष्ट उद्देश्य सरकारी अभिलेखों में दर्ज नहीं है। बिना पारदर्शी प्रक्रिया और स्पष्ट कार्य विवरण के इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किए जाने से पूरे मामले पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में जिन विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन निकाला गया, उनमें कई कार्य या तो धरातल पर अधूरे हैं या फिर निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इसके बावजूद भुगतान प्रक्रिया पूरी कर दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रत्येक भुगतान और उससे जुड़े अभिलेखों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता उजागर हो सकती है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि किसी भी कार्य का नियमानुसार भौतिक सत्यापन और तकनीकी परीक्षण किए बिना भुगतान फाइलों को मंजूरी देना गंभीर लापरवाही का संकेत है। उनका कहना है कि यदि जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन किया होता तो बिना स्पष्ट उद्देश्य के लाखों रुपये का भुगतान संभव नहीं था। ग्रामीणों ने ब्लॉक स्तर के अधिकारियों और तकनीकी कर्मचारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। इससे ग्रामीणों में यह धारणा मजबूत होती जा रही है कि कहीं न कहीं पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन समय रहते कार्रवाई नहीं करता है तो शासन की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है।

ग्रामीणों ने मांग की है कि जून 2026 में हुए ?3.97 लाख के संदिग्ध भुगतान सहित पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए। साथ ही भुगतान प्रक्रिया से जुड़े प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की भूमिका की जांच कर दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कठोर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

क्या बोले जिम्मेदार

इस संबंध में जब खण्ड विकास अधिकारी मछरेहटा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उसको हम दिखवाएंगे अभी थोड़े दिन बैठ लेने दो फिर देखते है।

शाहजहांपुर में सो रहे दंपति पर गिरा फर्राटा पंखा, करंट लगने से दोनों की मौत

कैनविज टाइम्स संवाददाता

शाहजहांपुर। थाना जलालाबाद क्षेत्र में रामगंगा नदी किनारे बसे कसारी गांव में शुक्रवार रात घर के कमरे में सो रहे दंपति पर अचानक फर्राटा पंखा गिर गया। जिसमें उतरे करंट की चपेट में आकर दंपति की मौत हो गई।

थाना जलालाबाद क्षेत्र में रामगंगा नदी किनारे बसे कसारी गांव में रहने वाले 40 वर्षीय अमर सिंह के पास मात्र तीन बीघा जमीन है। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनके पांच छोटे-छोटे बच्चे हैं। परिवार का भरण पोषण करने के लिए अमर सिंह अपनी 37 वर्षीय पत्नी कुसुमा देवी और पांचों बच्चों के साथ राजस्थान में एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे। करीब 10 दिन पहले वह अपने परिवार के साथ गांव आए थे। शुक्रवार रात करीब नौ बजे खाना खाने के बाद पति-पत्नी घर में बने कमरे में चले गए, जबकि उनके बच्चे कमरे के सामने पड़े छप्पर के नीचे लेटकर सो गए। रात करीब 10 बजे बिजली आने पर कमरे में रखा फर्राटा पंखा चलने लगा और कुछ देर बाद चारपाई पर सो रहे दंपति पर अचानक पंखा गिर गिया। दंपति की चीख सुनकर उनका 12 वर्षीय बड़ा बेटा कमरे में पहुंचा, तो उसकी मां और पिता चारपाई पर पड़े थे। उसकी चीख पुकार सुनकर पास में ही रह रहीं उसकी ताई सोनी वहां पहुंची, सोनी ने चारपाई पर पड़ी कुसुमा को उठाने का प्रयास किया, तो उसे भी करंट का झटका लगा। जिसके बाद लाइट चली गई। आसपास के लोगों ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने परिजनों की मदद से दंपती को सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई प्रेमचंद्र ने बताया कि उसकी 80 वर्षीय बीमार मां अपने पुत्रों पर ही आश्रित हैं। अमर सिंह के बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है।

एसडीएम प्रभात राय ने बताया कि दंपती की मौत की सूचना पर जांच के लिए क्षेत्रीय लेखपाल को मौके पर भेजा है। अगर दंपती के पास खेती योग्य भूमि होगी तो उनके आश्रित बच्चों को प्रदेश सरकार की कृषक दुर्घटना बीमा योजना से पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद दिलाई जाएगी। फिलहाल, दंपति अपने पीछे बेटे नितिन, उससे छोटा विवेक (10), शोभित (09), बेटी आरुषि (07) और सबसे छोटी बेटी संध्या (05) को रोता बिलखथा छोड़ गए हैं। उनका रो-रोकर बुरा हाल है।

बैंक का बकायेदारों पर शिकंजा, पांच लाख से अधिक के ऋण पर संपत्ति पर लगी लाल झंडी

- 26 शाखा सांडा की बड़ी कार्रवाई, राजस्व टीम और ग्राम प्रधान की मौजूदगी में हुई नोटिस की कार्रवाई

कैनविज टाइम्स संवाददाता

सकरन, लहरपुर, सीतापुर। बैंक ऋण की वसूली को लेकर शाखा सांडा ने बकायेदारों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में तहसील लहरपुर क्षेत्र के ग्राम हरीपुर में लाखों रुपये के ऋण बकायेदार की संपत्ति पर राजस्व एवं बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में लाल झंडी लगाकर वसूली प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया।

जानकारी के अनुसार ग्राम हरीपुर, परगना तंबौर, तहसील लहरपुर निवासी राजेंद्र पुत्र रामनाथ पर बैंक का 5,46,295 रुपये तथा उस पर देय ब्याज बकाया बताया गया है। बकाया राशि का भुगतान लंबे समय तक न होने पर बैंक ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित संपत्ति पर लाल झंडी लगाई।

इस दौरान क्षेत्रीय अमीन ज्ञानेंद्र कुमार, लेखपाल आयुष सिंह, अनिरुद्ध, शाखा प्रबंधक सुरेंद्र कुशवाहा, रिकवरी ऑफिसर किरण कुमार मिश्र तथा ग्राम प्रधान की उपस्थिति में कार्रवाई पूरी कराई गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बैंक ऋण की वसूली के लिए नियमानुसार आगे की कार्रवाई भी की जाएगी यदि निर्धारित अवधि में बकाया जमा नहीं किया गया।

बैंक अधिकारियों ने ऋण लेने वाले सभी उपभोक्ताओं से अपील की कि वे समय पर अपनी किस्तों और बकाया राशि का भुगतान करें, जिससे कठोर वसूली कार्रवाई से बचा जा सके। क्षेत्र में बैंक की इस कार्रवाई के बाद अन्य बकायेदारों में भी हलचल देखी जा रही है।

40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 02 अभियोग पंजीकृत

रायबरेली। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका के आदेशानुसार अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के विरुद्ध जारी प्रवर्तन अभियान के अन्तर्गत निरीक्षक क्षेत्र-1 प्रशांत कुमार मय हमराह द्वारा विभिन्न स्थानों पर दबिश की कार्यवाही की गयी। टीम द्वारा सदर तहसील के थाना-गुरुबक्शगंज अंतर्गत ग्राम-घाटमपुर व बसिंगवा में अवैध कच्ची शराब बनाने के अड्डों/संदिग्ध घरों में दबिश के दौरान जनपद में कुल 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद व 300 किलो लहन बरामद कर लहन को मौके पर नष्ट किया गया 02 अभियोग आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किये गए।

सीडीओ ने कस्तूरबा विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय का किया औचक निरीक्षण

- निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय प्रांगण, कक्षा-कक्ष, रसोई-घर, छात्रावास, खाद्य सामग्री, बर्तन, पीने का पानी समेत बच्चों उपलब्ध होन वाली अन्य सुविधाओं को भी जायजा लिया
- एक सप्ताह में कमियां दूर करने के निर्देश

कैनविज टाइम्स संवाददाता

सीतापुर । मुख्य विकास अधिकारी डॉ दीक्षा जोशी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर द्वारा आज दिनांक 04.07.2026 को प्रातः 10:30 बजे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ऐलिया, जनपद-सीतापुर तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय कचनार, विकास खंड -ऐलिया, जनपद-सीतापुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान विद्यालय प्रांगण, कक्षा-कक्ष, रसोई-घर, छात्रावास, खाद्य सामग्री, बर्तन, पीने का पानी व बच्चों को दी जाने वाली खेलकूद सामग्री एवं औषध सामग्री तथा शौचालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणों उपरांत विद्यालयों को स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर साफ-सफाई रखने हेतु विशेष ध्यान देने तथा लाइटिंग की उचित व्यवस्था एवं पायी गई अन्य कमियों को एक सप्ताह में निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया गया।

विद्यालय के समस्त कार्मिकों को नियमित उपस्थिति होने हेतु आदेशित किया गया। विद्यालय में उपस्थित छात्रो से वार्ता कर खाने की गुणवत्ता एवं उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान करने का आश्वासन दिया गया।

मोहर्रम ड्यूटी में उत्कृष्ट कार्य पर मछरेहटा थाना प्रभारी प्रभात कुमार गुप्ता हुए सम्मानित

कैनविज टाइम्स संवाददाता

सीतापुर। जनपद में मोहर्रम पर्व-2026 के दौरान कानून-व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में सराहनीय योगदान देने पर मछरेहटा थाना प्रभारी प्रभात कुमार गुप्ता को पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल (ऋष्ट) द्वारा प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रशस्ति-पत्र में उल्लेख किया गया है कि मोहर्रम पर्व के अवसर पर जनपद में व्यापक पुलिस व्यवस्था की गई थी। इस दौरान थाना प्रभारी प्रभात कुमार गुप्ता ने अत्यंत निष्ठा, लगन एवं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कानून-व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एसपी ने उनके कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए आशा व्यक्त की कि वे भविष्य में भी इसी प्रकार ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे। साथ ही उनके उज्ज्वल एवं मंगलमय जीवन की कामना भी की। इस सम्मान से मछरेहटा पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। स्थानीय लोगों ने भी थाना प्रभारी को बधाई देते हुए इसे पूरे थाना क्षेत्र के लिए गौरव का विषय बताया।

सीएचसी पुवायां में घपला: स्टॉक रजिस्टर में सिरिंज 'निल', लेकिन मौके पर मिलीं 02 हजार

- कर्मचारियों की तीन दिन आगे तक लगी मिली हाजिरी

कैनविज टाइम्स संवाददाता

शाहजहांपुर । सीएचसी पुवायां में डॉक्टर के पास बैठकर मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा मरीजों की पर्ची लिखने का वीडियो वायरल होने के बाद डीएम के निर्देश पर एसडीएम सदानंद सरोज ने शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया, तो कई खमियां मिली। निरीक्षण के दौरान एसडीएम को सीएचसी अधीक्षक डॉ. नरेंद्रपाल अस्पताल में नहीं मिले। इसके अलावा, कई कर्मचारी भी रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज कर गायब थे। जानकारी करने पर एसडीएम को सभी के बारे में एक ही जवाब मिला, कि सभी फील्ड में हैं। इस दौरान एसडीएम को दवा वितरण कक्ष में फार्मासिस्ट की जगह ट्रेनी दवाइयां बांटता मिला, जबकि महिला विंग स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बंद मिला। यही नहीं, एसडीएम को स्टॉक रजिस्टर में सिरिंज का स्टॉक निल दर्ज मिला, जबकि मौके पर करीब 2,000 सिरिंज रखी मिलीं। वहीं, रजिस्टर में करीब 1 लाख 14 हजार से अधिक सेनेटरी पैड वितरण का रिकॉर्ड दर्ज था, तीन कॉलेजों में 4125 सेनेटरी पैड देने का विवरण दर्ज था, लेकिन उसका स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं मिला। वहीं, पुवायां इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया कि उनके यहां केवल 40 छात्राएं हैं। प्रधानाचार्य ने भी रिकॉर्ड में दर्ज वितरण पर सवाल खड़े कर दिए। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि पल्स पोलियो अभियान में तैनात तीन कर्मचारियों ने उपस्थिति रजिस्टर में तीन दिन आगे तक हस्ताक्षर कर दिए थे। एसडीएम ने बताया कि सिरिंज, सेनेटरी पैड वितरण और फर्जी उपस्थिति सहित सभी मामलों की जांच कराई जाएगी। रिपोर्ट डीएम को भेजी जा रही है। डीएम के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बेहमा हनुमान मंदिर में पांच दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का भक्तिमय समापन

सीतापुर, कैनविज टाइम्स संवाददाता। रामपुर कलां क्षेत्र के बेहमा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में आयोजित पांच दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का समापन शनिवार को श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के बीच संपन्न हुआ। कथा का वाचन प्रेममूर्ति अनुजाचार्य जी महाराज ने अपने ओजस्वी एवं मधुर प्रवचनों के माध्यम से किया। कथा के अंतिम दिन मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा। दूर-दराज के गांवों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण कर धर्मलाभ प्राप्त किया तथा भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में भाव-विभोर हो गए। प्रेममूर्ति अनुजाचार्य जी महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा कि श्रीमद्भागवत कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन को सत्य, सेवा, प्रेम और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला दिव्य ज्ञान है। उन्होंने समाज में आपसी प्रेम, भाईचारे और संस्कारों को बनाए रखने का संदेश देते हुए सभी से धर्म और मानवता की सेवा के लिए आगे आने का आह्वान किया। कथा समापन के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण, जय श्रीराम और राधे-राधे के जयघोष से माहौल गूंज उठा। आयोजन समिति के सदस्यों एवं क्षेत्रवासियों ने श्रद्धालुओं की सेवा में बढ़-चढ़कर सहयोग किया, जिसकी सभी ने सराहना की।

सी ई ऑटो सेल्स हीरो एजेंसी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लगभग 50 लाख रुपये का नुकसान

सीतापुर, कैनविज टाइम्स संवाददाता। थाना रामपुर कलां क्षेत्र के सरैया राजा साहब पहला में स्थित सी ई ऑटो सेल्स हीरो एजेंसी में बीती रात अचानक आग लग जाने से लाखों रुपये का नुकसान हो गया। आग की इस घटना में एजेंसी के महत्वपूर्ण दस्तावेज, कार्यालय में रखे कंप्यूटर सिस्टम तथा अन्य आवश्यक सामान जलकर नष्ट हो गए। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। एजेंसी के मालिक मोहम्मद इरफान हैं, जबकि उनके भतीजे एवं संचालक मोहम्मद शाहनवाज ने बताया कि रात करीब दो बजे उन्हें सूचना मिली कि एजेंसी परिसर में आग लगी हुई है। सूचना मिलते ही वह तत्काल मौके पर पहुंचे और डायल-112 पुलिस तथा फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे आग को और अधिक फैलने से रोका जा सका। हालांकि तब तक कार्यालय में रखा कंप्यूटर सिस्टम, जरूरी दस्तावेज और अन्य सामग्री जलकर राख हो चुकी थी। मोहम्मद शाहनवाज के अनुसार, इस हादसे में करीब 50 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट सामने आया है। राहत की बात यह रही कि घटना के समय एजेंसी में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद क्षेत्र के व्यापारियों एवं शुभचिंतकों ने एजेंसी संचालक और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए जल्द सामान्य स्थिति बहाल होने की कामना की है।

सिंचाई खंड सीतापुर में प्रशासनिक अधिकारी पंकज सिन्हा ने संभाला कार्यभार

सीतापुर, कैनविज टाइम्स संवाददाता। सिंचाई खंड सीतापुर के नवनिर्मित कार्यालय के लोकार्पण के बाद विभाग को नए प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पंकज सिन्हा ने कार्यभार ग्रहण किया । यह पद करीब तीन माह से रिक्त था। पंकज सिन्हा राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष का दायित्व भी निभा रहे हैं। सिंचाई खंड सीतापुर में कार्यभार ग्रहण करने के बाद विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनका मिठाई खिलाकर नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर पंकज सिन्हा ने कहा कि वे पहले भी अपने साथियों के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी पूरी कर्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी के साथ राजकीय दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले वे नलकूप खंड प्रथम में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे, जहां उन्हें अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भरपूर स्नेह और सहयोग मिला। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग से उन्हें हमेशा बेहतर ढंग से कार्य करने का अवसर मिला। इस अवसर पर सिंचाई खंड के प्रधान सहायक आशीष गुप्ता, शिवसागर अवस्थी, पीयूष वर्मा, संजय भारती, मनीष कक्कड़, शहनवाज हुसैन, केदार सिंह विष्ट दिनेश पांडेय, विनोद शर्मा, रमेश राठौर सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

हमीरपुर में बच्ची को जहर खिलाने के बाद मां ने भी खाया जहर

हमीरपुर,कैनविज टाइम्स संवाददाता । उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में लगातार तीन बेटियां पैदा होने के तनाव के चलते शनिवार को मां ने बेटी को जहरीला पदार्थ खिला स्वयं भी खा लिया जिससे दोनों की हालत गंभीर होने के चलते प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। जबकि दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। मौदहा क्षेत्र में शनिवार को उस समय हडकंप मच गया, जब कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बिहरका निवासी श्याम बाबू की पत्नी सुशीला ने पांच साल की मासूम बच्ची निधि को जहरीला पदार्थ खिलाकर स्वयं भी जहरीला पदार्थ खा लिया जिससे दोनों की हालत बिगड़ गई। दोनों की हालत बिगडने पर दोनों को इलाज के लिए कस्बे के सरकारी अस्पताल लाया गया जहाँ से मां और बेटी की हालत नाजुक होने पर प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

नगर अध्यक्ष भाजपा विनीत जायसवाल की शिकायत पर कोटा निलंबित

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लहरपुर, सीतापुर। नगर के मोहल्ला जमा टोला की कोटेदार अफसाना बेगम की सरकारी गल्ले की दुकान को नगर अध्यक्ष भाजपा विनीत जायसवाल की शिकायत पर जिला पूर्ति अधिकारी अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने निलंबित कर दिया। यह कार्यवाही राशन की कालाबाजारी समेत अन्य आरोपों की शिकायतों की जांच में दोषी पाए जाने पर की गई है इस दुकान को नगर की दूसरी दुकान के कोटे की दुकान से संबद्ध कर दिया गया है।

नगर अध्यक्ष विनीत जायसवाल ने शिकायत की थी कि कोटेदार अफसाना बेगम द्वारा कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा से कम राशन दिया जाता है तथा उनके पति अलीम द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है, तथा अलीम द्वारा एक मृत महिला जो दूसरे मोहल्ले की निवासी थी उसके राशन कार्ड पर दूसरे मोहल्ले के एक ही परिवार के 4 यूनिट जुड़वाकर गलत राशन कार्ड बनवाया था। राशन कार्ड धारक रिंकी गप्पू गोद शिवा मिश्रा पंकज संदीप प्रदीप सूरज अर्चना अशर्फीलाल राजकुमार आदि ने आरोप लगाया था कि उन्हें निर्धारित मात्रा से कम राशन दिया जाता है। यही नहीं उनके पति द्वारा यूनिट चढ़ाने के नाम पर वसूली भी की जाती है इन शिकायतों की जांच क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक कविता वर्मा ने 19 जून को की थी। कोटेदार द्वारा निर्धारित मात्रा में राशन न देना अभद्र व्यवहार करना वसूली सहित अनियमिताएं पाई गई थी इसका संज्ञान लेते हुए जिला पूर्ति अधिकारी ने कोटा निलंबित कर दिया क्षेत्रीय निरीक्षक कविता वर्मा ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है कार्ड धारक नजदीक के उचित दर विक्रेता मिसबाहुद्दीन के यहां संबद्ध कर दिए गए हैं।

गंगा में डूबने से युवक की मौत, दोस्त की बची जान

कानपुर । ग्वालटोली थाना क्षेत्र अंतर्गत परमट स्थित कमलेश्वर घाट पर शनिवार दोपहर गंगा स्नान के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई, जबकि उसके साथ नहा रहा दोस्त नाविकों की सतर्कता से बचा लिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान चलाया और करीब डेढ़ घंटे बाद युवक का शव बरामद किया। इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर पड़ताल में जुट गई है। उन्नाव के दही थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव निवासी पंकज रावत (22) अपने दोस्त अनुज कुशवाहा के साथ श्री आनंदेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद कमलेश्वर घाट पर गंगा स्नान करने पहुंचे थे। नहाते समय दोनों गहरे पानी में चले गए और तेज बहाव की चपेट में आ गए। दोनों को डूबता देख घाट पर मौजूद नाविक तुरंत स्टीमर लेकर पहुंचे। नाविकों ने अनुज को लाइफ सेविंग जैकेट की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन पंकज पानी में लापता हो गया। सूचना मिलने पर ग्वालटोली पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों के साथ तलाश अभियान शुरू कराया। काफी प्रयास के बाद पंकज का शव गंगा से बरामद कर लिया गया।

सिर पर छह टांके, जिला अस्पताल रेफर फिर भी न्याय के लिए भटक रहा घायल

कैनविज टाइम्स संवाददाता

- सिधौली पुलिस के कार्य प्रणाली पर उठे सवाल

सीतापुर, सिधौली। सिधौली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मानपर में हुई मारपीट की घटना अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। पीड़ित पक्ष द्वारा दी गई तहरीर में गांव के विमलेश पुत्र सरजू, दिनेश पुत्र सरजू, बिंदेश्वरी पत्नी विमलेश, मधु पुत्री विमलेश और विनीत पुत्र विमलेश सहित अन्य लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने, धारदार हथियार से हमला करने और महिलाओं के आभूषण छीनने का आरोप लगाया गया है।

पीड़ित पक्ष का कहना है कि गांव में आपसी कहासुनी के दौरान विपक्षी पक्ष गाली-गलौज करता हुआ उनके घर में घुस आया और मारपीट शुरू कर दी। बीच-बचाव करने आए पीड़ित के बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। हमले में उसके सिर पर गंभीर चोट आई। सूत्रों के अनुसार घायल के सिर में छह टांके लगे और सिधौली सीएचसी से उसे जिला अस्पताल सीतापुर भेज दिया गया। आरोप है कि घायल हालत में जब पीड़ित न्याय की उम्मीद लेकर सिधौली कोतवाली पहुंचा तो तुरंत कार्रवाई करने के बजाय उसे काफी देर तक थाने में बैठाए रखा गया। सूत्रों की मानें तो इसी दौरान दूसरे पक्ष की ओर से छेड़छाड़ की तहरीर भी दी गई और दोनों पक्षों पर कार्रवाई करने की बात कही जाने लगी।

पीड़ित का आरोप है कि उसकी गंभीर चोटें साफ दिखाई दे रही थीं, मेडिकल भी हो चुका था, फिर भी उसे राहत देने के बजाय दबाव बनाया गया। सूत्रों का यह भी कहना है कि पीड़ित से तहरीर बदलवाने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।अब पूरे मामले पर लोगों की नजर सिधौली पुलिस की अगली कार्रवाई पर है। सवाल यह है कि क्या गंभीर रूप से घायल पीड़ित को उसकी चोटों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्याय मिलेगा, या फिर मामला दोनों पक्षों की शिकायतों में उलझकर रह जाएगा। गरीब और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले इस परिवार को इंसाफ मिलेगा या फिर न्याय के लिए उन्हें बड़े अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसका जवाब अब पुलिस की कार्रवाई ही देगी।

सड़कों पर बेसहारा एवं अनाथ महिलाओं व बच्चों के लिए वरदान बनी जिला प्रशासन की मानवीय मुहिम, उच्च न्यायालय के आदेशों का शतप्रतिशत अनुपालन

कैनविज टाइम्स संवाददाता

सम्भल। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 571/2024 (ज्योति राजपूत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में पारित आदेशों के शत-प्रतिशत अनुपालन के क्रम में जनपद सम्भल में एक विशेष मानवीय अभियान की शुरुआत की गई है। जिलाधिकारी सम्भल अंकित खंडेलवाल के कुशल निर्देशन एवं मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी अवधेश कुमार के प्रभावी मार्गदर्शन में जिला रेस्क्यू टास्क फोर्स द्वारा सड़कों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अत्यंत दयनीय स्थिति में रह रहे बेसहारा, अनाथ महिलाओं तथा बच्चों की पहचान और सुरक्षा हेतु सघन रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे वंचित, निराश्रित महिलाओं एवं बच्चों को चिन्हित कर उन्हें पुनर्वासितकराते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। अभियान के अंतर्गत जिला रेस्क्यू टास्क फोर्स, चाइल्ड हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर की संयुक्त टीमों द्वारा विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में निरंतर रेस्क्यू ड्राइव चलाई जा रही है। इस मानवीय पहल के माध्यम से सड़कों पर जीवन यापन करने को मजबूर बच्चों और बेसहारा महिलाओं को सुरक्षित वातावरण एवं आवश्यक विधिक व चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अभियान की मुख्य विशेषताएं एवं प्रमुख गतिविधियां: माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशों के अनुक्रम में बेसहारा एवं अनाथ महिलाओं व बच्चों के पुनर्वास हेतु जनपद स्तर पर त्वरित कार्रवाई।

जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल एवं मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट द्वारा रेस्क्यू टास्क फोर्स की गतिविधियों की नियमित समीक्षा एवं स्थलीय अनुश्रवण।

चिन्हित की गई महिलाओं को काउंसलिंग हेतु राजकीय महिला शरणालयों/आश्रय गृहों में सुरक्षित भेजने की व्यवस्था। भटके हुए एवं गुमशुदा बच्चों को रेस्क्यू कर विधिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए उनके परिजनों को सकुशल सौंपने का कार्य। चाइल्ड हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर की संयुक्त टीमों द्वारा 24x7 निगरानी और संवेदनशीलता के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन का संचालन।

जिला प्रशासन द्वारा जनसामान्य से भी यह अपील की गई है कि यदि उन्हें जनपद में कहीं भी कोई बेसहारा, अनाथ, गुमशुदा बच्चा या महिला विषम परिस्थितियों में मिले, तो इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन अथवा संबंधित हेल्पलाइन नंबरों 181 अथवा 1098 पर दें, ताकि समय रहते उन्हें आवश्यक संरक्षण और नया जीवन दिया जा सके।

छह मौतों का आरोपी ट्रैक्टर चालक पुलिस की पकड़ से दूर, 15 दिन बाद भी नहीं पकड़ा गया आरोपी

कैनविज टाइम्स संवाददाता

उझानी। पिछले महीने ई-रिक्शा सवार कछला के एक परिवार की छह महिलाओं की मौत होने के मामले में फरार दो ट्रैक्टर चालकों में एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरे फरार आरोपी की तलाश जारी है। वहीं कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार सुबह कासगंज जिले में दबिश दी। पुलिस ने वहां आरोपी ट्रैक्टर चालकों में सहावर थाना क्षेत्र के गांव पंडितनगला निवासी अनूप को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीम उसके संभावित ठिकानों पर गई, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। पूछताछ के बाद पुलिस ने अनूप का मेडिकल कराया। इसके बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि 17 जून को बरेली-मथुरा हाईवे पर हादसा हुआ था। रेस लगा रहे दोनों ट्रैक्टरों की टक्कर से ई- रिक्शा में सवार कछला निवासी एक ही परिवार के सदस्यों में डालचंद की पत्नी राजकुमारी, बेटी नारायणी देवी, पुत्रवधू सरला और गंगाश्री उर्फ आरती के अलावा परिवार की रेवती व प्रेमवती की मौत हो गई थी। हादसे में डालचंद समेत ई-कार्ट चालक और एक अन्य महिला घायल हुई थी। पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर मालिकों के नाम चेसिस नंबर के आधार पर एआरटीओ कार्यालय से जुटाए थे। वहीं, एसपी सिटी अभिषेक कुमार ने बताया कि एक आरोपी को कासगंज से गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे की तलाश की जा रही है,जल्दी आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।

पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

बदायूं कैनविज टाइम्स संवाददाता। थाना सहसवान क्षेत्र के मुन्नालाल चौराहा घास मंडी पर तैनात पुलिसकर्मियों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वही वायरल वीडियो में, मोटरसाइकिल चालक क़े गले में गमछा डाल क़े पीछे गिरने का मामला सामने आया है, वहीं चालक ने बचाव की कोशिश की तो थाना पुलिस ने उसी को थाने लेकर जाकर पीटा आरोप लगाया है, वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महक में में हड़कंप बचा हुआ है, वही एसपी ग्रामीण ने बताया कि जांच कर मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की जाएगी।

10 जुलाई तक दें जितेन्द्र उर्फ ढालू की मृत्यु के सम्बंध में साक्ष्य या बयान

बदायूं कैनविज टाइम्स संवाददाता। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम में अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ ढालू पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम जमैटा, थाना बनियाठेर, जनपद सम्भल, मूल निवासी ग्राम बझेड़ा, थाना धौलाना, जनपद हापुड़ की 01 जुलाई, 2026 को थाना सिविल लाइन, बदायूं क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बहेड़ी के जंगल में हुई पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु के प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच कराए जाने हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट सदर को नामित किया गया है। उप जिला मजिस्ट्रेट ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुए कहा कि इस घटना के संबंध में यदि कोई व्यक्ति, जनसाधारण, सभासद, ग्राम प्रधान अथवा घटना का चशमदीद कोई अन्य व्यक्ति यदि अपना लिखित अथवा मौखिक बयान, जानकारी, फोटोग्राफ, वीडियो अथवा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह 10 जुलाई 2026 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक उप जिलाधिकारी, बदायूं के न्यायालय/कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष अथवा साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

जुलाई सोमवार को होगा सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन

बदायूँ कैनविज टाइम्स संवाददाता। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अरुण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशानुसार 02, 03 एवं 04 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) 2026 थी। इसलिए 04 जुलाई 2026 प्रथम शनिवार को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा होने के कारण सम्पूर्ण समाधान दिवस अब 06 जुलाई 2026 दिन सोमवार को तहसील दातागंज में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तथा अन्य तहसीलों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार सम्बंधित अधिकारियों की अध्यक्षता में आयोजित होगा।

भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरन लाल लोधी का प्रथम बदायूं आगमन आज, जनपद में जगह-जगह स्वागत

बदायूं कैनविज टाइम्स संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरन लाल लोधी का 05 जुलाई 2026 (रविवार) को जनपद बदायूं में प्रथम आगमन होगा। उनके स्वागत एवं अभिनंदन के लिए जनपद भर में विभिन्न स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तथा स्वागत समारोह की तैयारियों को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने पार्टी के विभिन्न पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को अलग-अलग स्थानों पर स्वागत कार्यक्रमों की जिम्मेदारियां सौंपी हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरन लाल लोधी का स्वागत कार्यक्रम प्रातः 08:30 बजे पुठी सराय से प्रारंभ होगा। इसके उपरांत बिनावर में कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वे पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, राष्ट्रीय परिषद सदस्य हर प्रसाद सिंह पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं विधायक प्रेम स्वरूप पाठक, विधान परिषद सदस्य वागीश पाठक, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वर्षा यादव, सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, पूर्व मंत्री भगवान सिंह शाक्य, पूर्व विधायक धर्मेंद्र शाक्य तथा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव के आवास पर स्वागत कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसके पश्चात वे उझानी स्थित बाबूजी कल्याण सिंह चौक पर बाबूजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे तथा आयोजित पार्टी पदाधिकारियों द्वारा स्वागत कार्यक्रम। तत्पश्चात वे केंद्रीय राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा से उनके आवास पर भेंट करेंगे। कछला चौराहा पर कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित भव्य स्वागत एवं अभिनंदन।

साइबर ठगी के शिकार युवक को मिली राहत, पुलिस ने 19,500 रुपये कराए वापस

मीरजापुर । अहरौरा थाना की साइबर सेल ने ऑनलाइन ठगी के शिकार एक व्यक्ति को बड़ी राहत दिलाते हुए उसके खाते से निकाली गई धनराशि में से 19,500 रुपये वापस करा दिए। खाते में रकम लौटने पर पीड़ित ने पुलिस का आभार जताया।
पुलिस के अनुसार, अहरौरा थाना क्षेत्र के मदारपुर निवासी विधानंद पुत्र दशरथ ने 25 मई को साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके खाते से ऑनलाइन माध्यम से 37,500 रुपये की अवैध निकासी हो गई है। लेन-देन की जानकारी न होने पर मामले की शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) एवं क्षेत्राधिकारी (ऑपरेशन) के नेतृत्व में अहरौरा साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू की। तकनीकी जांच और आवश्यक कार्रवाई के बाद एमआरएम पोर्टल के माध्यम से ठगी गई राशि में से 19,500 रुपये पीड़ित के खाते में वापस करा दिए गए। राशि वापस मिलने पर विधानंद ने शनिवार को थाना पहुंचकर पुलिस अधिकारियों और साइबर सेल टीम का धन्यवाद दिया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें साइबर अपराधों से बचाव के उपाय भी बताए और किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या ऑनलाइन लेनदेन से सतर्क रहने की सलाह दी। साथ ही लोगों को भी साइबर ठगी के प्रति जागरूक करने की अपील की। इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष अजय मिश्र, मुख्य आरक्षी नरेंद्र सिंह, महिला आरक्षी महिमा उपाध्याय और आरक्षी अंकित अवस्थी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

14 साल पुराने मामले में फरार वारंटी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा न्यायालय

उरई । अपराधियों की गिरफ्तारी और लंबित वारंटों के निस्तारण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जालौन पुलिस को एक और सफलता मिली है। कैलिया थाना पुलिस ने वर्ष 2012 से लंबित एक मामले में फरार चल रहे वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। उपनिरीक्षक अवनीश कुमार ने शनिवार को अभियुक्त श्याम सुंदर पुत्र धनलाल, निवासी ग्राम पीपरी कला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध मामला दर्ज था। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), जालौन की अदालत में विचाराधीन था और अभियुक्त के खिलाफ वारंट जारी था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए वारंटी अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया, जहां से आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह का कहना है कि फरार वारंटियों और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा तथा कानून से बचने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

फतेहपुर रेलवे स्टेशन का अपर मंडल रेल प्रबंधक ने किया निरीक्षण

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में शनिवार को अपर मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार ने फतेहपुर स्टेशन का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत अमृत स्टेशन पुनर्विकास योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों का गहनता से जायजा लिया ।
निरीक्षण के दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक ने स्टेशन पर उपलब्ध विभिन्न यात्री सुविधाओं, टिकटिंग व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था तथा दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने यात्रियों की सुगम आवाजाही एवं सुविधा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर नव निर्मित 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज सहित अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किए जा रहे अन्य विकास कार्यों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों की प्रगति, निर्माण की गुणवत्ता तथा कार्यस्थल पर संरक्षा मानकों के अनुपालन की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
अपर मंडल रेल प्रबंधक ने स्टेशन पुनर्विकास कार्यों में यात्री सुविधा, सुगम आवागमन, स्वच्छता, संरक्षा तथा दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्यों की नियमित निगरानी करते हुए निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के अवसर पर गति शक्ति यूनिट के अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं संबंधित पर्यवेक्षक उपस्थित रहे।

देवरिया : मेडिकल कॉलेज की निर्माणाधीन परियोजनाओं पर जिलाधिकारी सख्त

एक सप्ताह में कार्य पूरा करने के निर्देश

देवरिया । उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्थाओं को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने सभी लंबित निर्माण कार्यों को एक सप्ताह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए और चेतावनी दी। निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा न होने पर संबंधित संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन ट्रॉमा सेंटर में बिजली, पेयजल, ऑक्सीजन पाइपलाइन सहित सभी आवश्यक सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराकर एक सप्ताह के भीतर हैंडओवर करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ट्रॉमा सेंटर का संचालन हर हाल में शीघ्र शुरू होना चाहिए और अब किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

समीक्षा बैठक में उन्होंने क्रिटिकल केयर यूनिट, नर्सिंग कॉलेज सहित अन्य सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाकर उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को आवश्यक मैनपावर, उपकरण और अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनस्वास्थ्य की दृष्टि से मेडिकल कॉलेज अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान है। इसलिए निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करना और सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। बैठक में मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. रजनी पटेल, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. ए.के. गुप्ता, सीएमएस डॉ. एच.के. मिश्रा, वरिष्ठ कोषाधिकारी अतुल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

इस्लामनगर थाना बना रील का अड्डा, थाने की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

कैनविज टाइम्स संवाददाता

बदायूँ। इस्लामनगर थाना परिसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक परिसर की छत पर चढ़कर रील बनाते और बाइक दौड़ाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवकों ने भौकाल जमाने के लिए वीडियो खुद ही सोशल मीडिया पर वायरल किया। वीडियो सामने आने के बाद थाना परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि थाना परिसर में रील बनाने का मामला कोई नया नहीं है, इससे पहले बिनावर थाने में तैनात महिला सिपाही का रील सोशल मीडिया पर हुआ था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई, वहीं अब इस्लामनगर थाने में प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा रील बनाना सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बड़ा सवाल पैदा करता है, वही प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि थाने पर रील बनाने को लेकर मामला सामने आया है, और कार्यवाही की

जाएगी। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

बदायूं। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जनपद बदायूं में बढ़ई, नाई, दर्जी, कुम्हार, लोहार, सुनार, राजमिस्त्री, हलवाई, मोची एवं धोबी सहित विभिन्न परम्परागत व्यवसायों से जुड़े कारीगरों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।

उपायुक्त उद्योग सचिन जैन ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 25 जुलाई, 2026 तक विभागीय वेबसाइट msme.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित लाभार्थियों को प्रशिक्षण के साथ-साथ निःशुल्क टूलकिट भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो) तथा तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा वह जनपद बदायूं का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदकों को परम्परागत कारीगरी से संबंधित ट्रेड से जुड़े होने के प्रमाण के रूप में ग्राम प्रधान, अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका/नगर निगम के संबंधित वार्ड सदस्य द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत एक परिवार से केवल एक सदस्य ही आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

परिवार का आशय पति, पत्नी एवं अविवाहित बच्चों से है। आवेदक को इस आशय का 10 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसने अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य ने पूर्व में किसी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत टूलकिट अथवा मानदेय का लाभ प्राप्त नहीं किया है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी कार्यदिवस में जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, बदायूं से संपर्क कर सकते हैं।

हाथरस में 26 दिन बाद समाप्त हुई अधिवक्ता, दस्तावेज लेखकों की हड़ताल

हाथरस। उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले के सादाबाद तहसील में पिछले 26 दिनों से जारी दस्तावेज लेखक, अधिवक्ता, टाइपिस्ट, मुंशियों और स्टांप वेंडरों की हड़ताल शनिवार को समाप्त हो गई है। सोमवार से तहसील परिसर में दस्तावेज लेखन और रजिस्ट्री संबंधी सभी कार्य सामान्य रूप से फिर से शुरू हो जाएंगे। हड़ताल उत्तर प्रदेश सरकार के 4 जून को ई-रजिस्ट्री व्यवस्था लागू करने के निर्णय के विरोध में की गई थी। प्रदेश भर के दस्तावेज लेखक, अधिवक्ता, टाइपिस्ट और मुंशी इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। आरोप था कि ई-रजिस्ट्री की नई प्रणाली से हजारों लोगों के सामने रोजगार का संकट पैदा होगा और पारंपरिक दस्तावेज लेखन व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित होगी। दस्तावेज लेखक संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार ने 29 जून को संबंधित आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही, वर्ष 2024 के ई-रजिस्ट्री शासनादेश में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए आईजी स्टांप को एक प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने जारी की मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची, 11 जुलाई तक दें आपत्तियां एवं सुझाव

कैनविज टाइम्स संवाददाता

बदायूं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-25 के अंतर्गत प्रदत्त प्रावधानों तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश राय ने जनपद के संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन कर दिया है। यह आलेख्य सूची 04 जुलाई, 2026 से एक सप्ताह की अवधि के लिए प्रकाशित की गई है। सूची समस्त उपजिलाधिकारी कार्यालयों व एनआईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 23-बदायूं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 112-बिसौली, 113-सहसवान, 114-बिल्सी एवं 115-बदायूं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा 24-आंवला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 116-शेखूपुर एवं 117-दातागंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्रों के समक्ष अंकित मतदान क्षेत्रों के मतदाताओं के समूह हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्रों की आलेख्य सूची प्रकाशित की गई है। उन्होंने जनसामान्य एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की है कि यदि जनपद के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची के संबंध में कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो, तो उसे लिखित रूप में 11 जुलाई 2026 तक जिला निर्वाचन कार्यालय, बदायूं अथवा संबंधित उपजिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।

मुरादाबाद : तीन महीने से नगर निगम का हाउस टैक्स पोर्टल ठप, ऑनलाइन सुविधा बंद

मुरादाबाद । मुरादाबाद नगर निगम का ऑनलाइन हाउस टैक्स पोर्टल पिछले तीन महीने से बंद पड़ा है। अप्रैल से ठप इस व्यवस्था ने हजारों करदाताओं की परेशानी बढ़ा दी है। ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा बंद होने से लोगों को मजबूरन नगर निगम के काउंटरों पर पहुंचकर मैनुअल तरीके से कर जमा करना पड़ रहा है। इससे न केवल लंबी कतारें लग रही हैं, बल्कि लोगों का समय और पैसा भी बर्बाद हो रहा है। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक यह समस्या केवल मुरादाबाद तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में पोर्टल बंद है। इसकी वजह पोर्टल संचालित करने वाली एजेंसी और निगम के बीच सालाना किराये को लेकर बना विवाद बताया जा रहा है। एजेंसी पहले चार लाख रुपये वार्षिक शुल्क पर सेवा दे रही थी, लेकिन किराया बढ़ाने की मांग के चलते ऑनलाइन व्यवस्था बहाल नहीं हो सकी। ऑनलाइन भुगतान बंद होने का असर नगर निगम की राजस्व वसूली पर भी साफ दिखाई दे रहा है।

फर्रुखाबाद: दुष्कर्म के प्रयास से आहत किशोरी ने फांसी लगाई दी जान

एजेंसी

फर्रुखाबाद । उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में कायमगंज थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के प्रयास से आहत किशोरी ने शनिवार दोपहर फांसी लगाकर जान दे दी। यह जानकारी मिलते ही आरोपित पक्ष के परिजन घरों से फरार हो गए। पुलिस घटना की जांच करते हुए अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है।

कायमगंज के ग्राम नरसिंहपुर निवासी अनुराग उर्फ अन्ने जोशी के घर में आज दोपहर 14 वर्षीय एक किशोरी ने फांसी लगाकर जान दे दी। आरोप है कि अन्ने के पड़ोस में कोयल नट का परिवार रहता है। कोयल नट का रिश्तेदार थाना नवाबगंज के ग्राम राज राठौरा निवासी विकास नट काफी समय से मृतक किशोरी से एकतरफा प्यार करता था। आज जब किशोरी खेतों में शौच करने गई थी, तभी आरोपित विकास उसके पीछे गया और खेत में जबरन दुष्कर्म करने

का प्रयास किया। किशोरी ने विकास की हरकतों का विरोध किया तो उसने उसकी पिटाई की। किसी तरह आरोपित के चंगुल से बचकर किशोरी घर पहुंची और परिजनों को पूरी जानकारी दी।

विकास की हरकतों की जानकारी मिलते ही कोयल के परिजन अन्ने के घर पहुंचे और राजीनामा कर माफी मंगवाने के लिए वार्ता करने लगे। इसी दौरान घर पर किशोरी ने पंखे में साड़ी बांध कर फांसी लगा ली। बेटी को फांसी पर लटका देखकर परिवार में हड़कंप मच गया। परिजनों ने उसे फंदे से नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस मामले की जानकारी होते ही कोयल नट के परिवार के पुरुष घर छोड़कर भाग गए।

सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार, सीओ राजेश कुमार द्विवेदी, कोतवाली प्रभारी विनोद शुक्ला फॉरेंसिक टीम एवं स्वाट टीम मौके पर पहुंची। गांव में बवाल की आशंका से पुलिस मृत किशोरी के शव को ले गई और परिजन एवं गांव के लोग पुलिस के पीछे चले गए। विकास के घर पर न मिलने पर पुलिस उसकी मां को कोतवाली ले गई। बताया जा रहा है कि मृतक किशोरी कक्षा 8 पास थी और उसके दो भाई हैं। पिता खेती एवं पंडिताई का काम करते हैं। कोतवाल विनोद कुमार ने बताया के आरोपितों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है।

नगर पालिका बहराइच ने मौनी बाबा आश्रम में शुरू की नि:शुल्क प्रसाधन सुविधा

कैनविज टाइम्स संवाददाता

बहराइच । नगर पालिका परिषद बहराईच के तत्वावधान में मौनी बाबा आश्रम परिसर मे नवनिर्मित प्रसाधन गृह का लोकार्पण नगर पालिका परिषद चैयरमैन प्रतिनिधि श्यामकरन टेकड़ीवाल ने किया।इस अवसर पर क्षेत्रीय श्रद्धालु व आस्थावान जन के अलावा तमाम क्षेत्रीय नागरिक तथा पर्यावरणविद व समाजसेवी उपस्थित रहे।

नगर पालिका परिषद बहराईच के सौजन्य से नवनिर्मित प्रसाधन के उदघाटन अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए नगर पालिका परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि श्यामकरन टेकड़ीवाल ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में बहराईच नगर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत सभी सार्वजनिक जगहों, धार्मिक संस्थाओं व विशेषकर मलिन बस्तियों में नगर पालिका परिषद की ओर से प्रसाधन केंद्र का निर्माण करवाया जा रहा है ताकि लोगो को लगातार नि:शुल्क और स्वच्छ प्रसाधन सुविधाएं मिलती रहे। श्यामकरन टेकड़ीवाल ने लोगो से आवाहन किया कि वे नगर पालिका परिषद द्वारा चलाये जा रहे स्वच्छता अभियान में सहभागी बने तथा जन समस्याओं से अवगत कराते रहे ताकि स्वच्छ्ता का लाभ लोगो को मिल सके।

आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजसेवी प्रेम जालान ने किया इस अवसर पर प्रमुख रूप से सर्वानंद सरस्वती, विकास मतनहेलिया, राकेश चंद्र श्रीवास्तव, नन्हे लाल लोधी, सभासद हर्षित राज श्रीवास्तव व नाथ तिवारी, मनीष रस्तोगी, राहुल दीक्षित, विनय जैन, धर्मेंद्र सिंह, राहुल राय, कमल शेखर, प्रकाश गुप्ता, मगन बिहारी सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे।

महामना मालवीय मिशन ने बनाई प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की रणनीति

कैनविज टाइम्स संवाददाता

बहराइच । महामना मालवीय मिशन-अवध के तत्वावधान में सहयोगी विचारधारा वाले संगठनों के साथ समन्वय बनाकर ग्रामीणांचल इलाको में चलाए जा रहे विष मुक्त खेती नशा मुक्त गांव को गति देने के लिए गांव गांव में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक दवाईयों से होने वाले कुप्रभाव से लोगो को अवगत कराकर परंपरागत खेती हेतु लोगो को जागरूक भी किया जाएगा। अभियान को गति देने के लिए महामना मालवीय मिशन राष्ट्रीय अध्यक्ष इं0 हरीशंकर सिंह ने उद्यान विभाग व कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में विषमुक्त खेती व फल तथा सब्जी उत्पाद क्षेत्र का भ्रमण कर कृषि व उद्यान अधिकारियों से रसायन मुक्त खेती किसानी व फल तथा सब्जी उत्पाद हेतु तकनीकी सलाह मशवरा किया और किसानों को सचेत करने के लिए रणनीति बनाई।अध्यक्ष अवध क्षेत्र संजीव श्रीवास्तव एडवोकेट ने बताया कि पारंपरिक व प्राकृतिक खेती किसानी बागवानी व गौपालन को बढ़ावा देने के लिए गायत्री परिवार, संघ विचार परिवार, किसान परिषद,भारतीय किसान यूनियन व अन्य सामाजिक रचनात्मक कार्य करने वाले संगठनों से समन्वय बनाकर किसानों से संवाद बनाने की प्रभावी कार्य योजना बनाई गई है।उपकृषि निदेशक विनय वर्मा ने उद्यानिक व कृषि परिक्षेत्र का भ्रमण करने के पश्चात बताया कि कीटनाशक दवाइयों व रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से खाद्यान्न पदार्थ अनाज फल व दुध उत्पाद विषैले हो रहे हैं जिनके उपयोग से लोगो को आसाध्य बीमारियों से जूझना पड़ रहा है यदि इनपर प्रभावी अंकुश न लगाया गया तो हालात भयावह होंगे। उप कृषि निदेशक ने बताया कि रासायनिक कीटनाशक दवाइयों से बचाव के लिए विकल्प के तौर पर स्वदेशी संयंत्रों का उत्पादन विभागीय सलाह पर हो रहा है इनके उपयोग से हमारा स्वास्थ्य व धन की बचत होगी उन्होंने लोगो श्री अन्न (मिलेट्स)का उत्पादन व उपभोग करने की सलाह दी ताकि स्वस्थ समाज व स्वस्थ परिवार मिशन सफल हो सके।

कृषि विज्ञान केंद्र नानपारा में वृक्षारोपण सप्ताह पर पौधरोपण किसानों को फलदार पौधे वितरित कर किया जागरूक

कैनविज टाइम्स संवाददाता

नानपारा, बहराइच। वृक्षारोपण सप्ताह के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) नानपारा, बहराइच-द्वितीय में शनिवार को वृक्षारोपण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नानपारा विधायक रामनिवास वर्मा रहे। इस अवसर पर जिला वन अधिकारी सुंदरेश, क्षेत्रीय वनाधिकारी पीयूष गुप्ता तथा कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉ. संदीप कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं वैज्ञानिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए तथा किसानों को फलदार पौधों का वितरण किया गया। वैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने में वृक्षों की भूमिका तथा कृषि वानिकी के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। किसानों से खेतों की मेड़ों एवं खाली स्थानों पर अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनका संरक्षण करने का आह्वान किया गया। जिला वन अधिकारी सुंदरेश ने किसानों को कार्बन क्रेडिट योजना की जानकारी देते हुए बताया कि वृक्षारोपण एवं कृषि वानिकी अपनाकर किसान पर्यावरण संरक्षण के साथ कार्बन संचयन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। साथ ही भविष्य में कार्बन क्रेडिट जैसी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक लाभ मिलने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने पौधों के चयन, रोपण की वैज्ञानिक विधि, उनकी देखभाल तथा कृषि वानिकी आधारित आय वृद्धि के विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी व्याख्यान दिए। कार्यक्रम में डॉ. पी.के. सिंह, श्रीमती रेनू आर्य, उमेश कुमार, सुनील कुमार, संदीप कुमार गौतम सहित कृषि विज्ञान केंद्र के समस्त कर्मचारी, वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रीय किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया।

निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में सैकड़ों मरीजों को मिला लाभ, ताजपुर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने की जांच

कैनविज टाइम्स संवाददाता

नानपारा, बहराइच। प्रेरणा परियोजना के अंतर्गत सहयोजक कैथोलिक डायोसिस लखनऊ एवं नवजीवन हॉस्पिटल नानपारा के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम ताजपुर, नानपारा में नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श, आवश्यक जांच तथा निशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। करीब 130 से अधिक मरीजों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई तथा उन्हें आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गईं। नवजीवन हॉस्पिटल की ओर से डॉ. राजीत राम निषाद, डॉ. रोहित निषाद, डॉ. कुलदीप निषाद, डॉ. सर्वजीत सिंह एवं मनीष गुप्ता ने अपनी सेवाएं प्रदान की। वहीं सहयोजक कैथोलिक डायोसिस लखनऊ की टीम में कोऑर्डिनेटर सिस्टर शालिनी, अमित कुमार वर्मा, रूबीना परवीन, मुस्कान श्रीवास्तव एवं निराश्री देवी ने शिविर के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयोजकों ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसी क्रम में रविवार को पचपेड़वा गांव में तथा 8 जुलाई को ककरी गांव में भी निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां ग्रामीणों को विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जांच एवं दवा वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

काशी धर्म, संस्कृति और संगीत की नगरी ही नहीं, बल्कि पारंपरिक व स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए विश्वभर में रखता है विशेष पहचान : अभिनेत्री भाग्यश्री

एजेंसी

बॉलीवुड अभिनेत्री ने लंका चौराहे पर बनारसी लस्सी का स्वाद चखाकर की सराहना

वाराणसी। बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री इन दिनों काशी प्रवास पर हैं। शनिवार को उन्होंने लंका चौराहे पर स्थित पहलवान लस्सी की दुकान पर पहुंचकर बनारसी लस्सी का स्वाद चखा और काशी के पारंपरिक खानपान की खुलकर सराहना की। फिल्म 'मैने प्यार किया' से लोकप्रिय हुई अभिनेत्री ने भाग्यश्री ने कहा कि बनारस की चाट और लस्सी उन्हें बेहद पसंद है। उन्होंने बताया कि जब भी काशी आने का अवसर मिलता है, वह यहां की चाट और लस्सी का स्वाद लेना नहीं भूलतीं। उनके अनुसार, काशी केवल धर्म, संस्कृति और संगीत की नगरी ही नहीं, बल्कि अपने पारंपरिक और स्वादिष्ट व्यंजनों के कारण भी विश्वभर में विशिष्ट पहचान रखती है। भाग्यश्री के लस्सी की दुकान पर पहुंचते ही उन्हें देखने के लिए प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों से आत्मीयता से बातचीत की और लंका क्षेत्र के अन्य प्रसिद्ध खानपान केंद्रों की भी जानकारी ली। अभिनेत्री का लस्सी का आनंद लेते हुए बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पूर्व शुक्रवार शाम भाग्यश्री ने श्री कालभैरव मंदिर में दर्शन-पूजन कर विधिवत आराधना की। मंदिर परिसर में उन्होंने कुछ समय बिताकर वहां के आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव किया। इसके बाद वह दशाश्वमेध घाट पहुंचीं, जहां उन्होंने मां गंगा का विधिवत पूजन किया और गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित विश्वप्रसिद्ध गंगा आरती में सहभागिता की।

गंगा आरती के उपरांत गंगोत्री सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से सचिव दिनेश शंकर दुबे ने पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और स्मृति-चिह्न भेंट कर अभिनेत्री का स्वागत एवं सम्मान किया। इस अवसर पर उन्हें काशी की प्राचीन धार्मिक परंपराओं, मां गंगा की महिमा तथा विश्वप्रसिद्ध गंगा आरती के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की जानकारी भी दी गई। भाग्यश्री ने मां गंगा के समक्ष देश और विश्व में सुख, शांति तथा समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि काशी का आध्यात्मिक वातावरण, गंगा तट की अलौकिक छटा और दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती का अनुभव उनके जीवन के सबसे अविस्मरणीय अनुभवों में शामिल रहेगा।

बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा स्वीकार : एआरटीओ

कैनविज टाइम्स संवाददाता

गोंडा । जनपद के थाना खोडारे क्षेत्र में एआरटीओ प्रशासन के नेतृत्व में परिवहन विभाग एवं संयुक्त प्रवर्तन टीम द्वारा विशेष अभियान चलाकर स्कूल वाहनों की सघन जांच की गई।अभियान के दौरान सड़क सुरक्षा मानकों एवं परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए कुल तीन स्कूल वाहनों को जब्त कर लिया गया।इसके अतिरिक्त जांच में दो अनफिट (अयोग्य) स्कूल वाहन,एक ऐसा स्कूल वाहन जिस का परमिट समाप्त हो चुका था तथा एक बिना पं जीकरण (रजिस्ट्रेशन) के संचालित स्कूल वाहन भी पकड़ा गया।

विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

जांच के दौरान अधिकारियों ने स्कूल वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र,परमिट,पंजीकरण,बीमा, प्रदूष ण प्रमाणपत्र सहित अन्य आवश्यक अभिलेखों का गहन परीक्षण किया।जिन वाहनों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं,उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की गई।अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा प्रत्येक स्कूल संचालक का दायित्व है कि वह निर्धारित मानकों के अनुरूप सुरक्षित एवं वैध दस्तावेजों वाले वाहनों का ही संचालन कराए।

नियमों का उल्लंघन करने पर नहीं मिलेगी राहत

एआरटीओ प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि परिवहन नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूल वाहनों एवं संबंधित प्रबंधन के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।बिना फिटनेस, बिना वैध परमिट, बिना पंजीकरण अथवा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के स्कूल वाहन संचालित करना कानून का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदारता नहीं बरती जाएगी।सभी विद्यालयों से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों के सभी दस्तावेज समय से अद्यतन रखें और सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन करें।

परिवहन विभाग का अभियान लगातार जारी

परिवहन विभाग ने बताया कि जनपद में स्कूल वाहनों के विरुद्ध यह विशेष अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।अभियान का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं,बल्कि विद्यार्थियों की सुरक्षित एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना है।विभाग ने स्कूल प्रबंधकों, वाहन स्वामियों एवं चालकों से नियमों का पालन करने तथा सभी वैधानिक औपचारिकताओं को समय पर पूरा करने की अपील की है।अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षित परिवहन व्यवस्था ही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मण्डलायुक्त ने कार्यालय में स्कूली बच्चों के साथ किया वृक्षारोपण

कैनविज टाइम्स संवाददाता

मानव जीवन को सुखी, समृद्धि व संतुलित बनाये रखने के लिए वृक्षारोपण है जरूरी- आयुक्त

प्रकृति का संतुलन बनाये रखने हेतु वृक्षों की है अहम भूमिका-आयुक्त

गोंडा । वन महोत्सव''कार्यक्रम के अन्तर्गत मंडला युक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने मंडलायुक्त कार्यालय में स्कूली बच्चों के साथ पीपल पाकड़,बरगद वह अन्य का वृक्ष लगाकर जनपद वासियो को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने हेतु प्रेरित किया।वृक्षारोपण के दौरान मण्डलायुक्त ने कहा कि मानव जीवन को सुखी, समृद्धि व संतुलित बनाये रखने के लिए जरूरी वृक्षारोपण है।वृक्ष लगाओं जीवन को सुरक्षित बनाओं''।वन पृथ्वी पर जीवन के लिए अनिवार्य तत्व हैं, यह प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में पूर्णतया सहायक होते हैं। उन्होने कहा कि पेड़ ऑक्सीजन का स्रोत हैं,वे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के अलावा पेड़ सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड सहित कई हानिकारक गैसों को भी अवशोषित करते हैं और वातावरण से हानिकारक प्रदूषक को भी फिल्टर करते हैं, जिससे हमें ताजा और साफ-सुथरी हवा सांस लेने के लिए मिलती है। स्वस्थ्य जीवन के लिए आज के समय अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की महती आवश्यकता है।उन्होंने कहा कि प्रकृति का संतुलन बनाये रखने हेतु वृक्षों की अहम भूमिका है। इसलिए प्रकृति के संतुलन बनाये रखने में अधिक से अधिक वृक्षों को लगाकर सभी जनपद वासी अपनी सहभागिता निभायें। वृक्ष हमें जीवनदान देने वाली ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिसके बिना हमारा अस्तित्व बस असंभव है। इसके अलावा, पेड़ लगाने के कई अन्य लाभ हैं। वृक्ष हानिकारक गैसों को अवशोषित कर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते है। पक्षियों और जानवरों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं और गर्मी के दिनों में छाया प्रदान करते हैं। वृक्ष लगाने के बाद लोग जैसे अपने बाल-बच्चों को पालन-पोषण कर बड़ा किया जाता है, ठीक उसी तरह से लगाये गये वृक्षों की भी देखभाल किया जाए, ताकि यह वृक्ष सुरक्षित रह सके। आयुक्त ने ये भी कहा कि पेड़ पृथ्वी पर जीवन के लिए अनिवार्य हैं। वृक्ष पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने में सहायक होते है।

इसलिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर इस अभियान में अपनी सहभागिता निभावें।इसके अतिरिक्त मंडलायुक्त ने स्कूली बच्चों को पेन किताब व अन्य सामग्री देकर सम्मानित किया।वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी अनुराग प्रियदर्शी,अपर आयुक्त प्रशासन मीनू राणा, अपर आयुक्त न्यायिक राजेश कुमार यादव एवं संयुक्त विकास आयुक्त राजेश कुमार पाण्डेय एवं अन्य अधिकारीगण/कर्मचारियगण उपस्थित रहे।

शातिर ने साईकिल से उड़ाया रुपयों का बैग

हाथरस। सादाबाद कस्बे के विनोवा नगर में दिनदहाड़े साइकिल पर टंगा एक बैग चोरी हो गया। बैग में 40 हजार नकद, एक मोबाइल फोन और तीन बैंक पासबुक थीं। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जलेसर रोड स्थित विनोवा नगर निवासी विजेंद्र सिंह पिता रनवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि गुरुवार को उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक शाखा से 40 हजार रुपए निकाले थे। घर लौटने के बाद उन्होंने नकदी और अन्य सामान एक बैग में रखकर साइकिल पर टांग दिया। इसके बाद वे घर के अंदर स्थित अपनी दुकान खोलने चले गए। आरोप है कि इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने मौका पाकर साइकिल पर टंगा बैग उतार लिया और फरार हो गया। जब विजेंद्र सिंह वापस बाहर आए, तो बैग गायब मिला। उन्होंने आसपास काफी तलाश की, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिल सका। पीड़ित के अनुसार, इसके अलावा, भारतीय स्टेट बैंक की तीन पासबुक भी बैग में थीं। इनमें एक पासबुक विजेंद्र सिंह की, दूसरी उनकी पत्नी विमलेश कुमारी की और तीसरी उनके पुत्र रोहन सिंह के खाते की थी। प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह ने पुष्टि की कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामले की जांच कर रही है।

बिहार ले जायी जा रही 72 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी, दो तस्कर गिरफ्तार

देवरिया । लार थाना पुलिस ने चेकिंग में एक पिकअप वाहन से 72 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और बीयर पकड़ी है। दो तस्कर गिरफ्तार किए गए। अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) सुनील कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात सुतावर मोड़ के पास चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली। बिकानो के डिब्बों के नीचे छिपाकर रखी गई 72 पेटी अवैध शराब (करीब 722 लीटर) बरामद हुई, जिसे बिहार ले जाया जा रहा था। दो तस्कर सलेमपुर थाना क्षेत्र निवासी गोविंद साहनी और बिट्टू यादव को गिरफ्तार किया गया। वाहन समेत शराब को जब्त कर पुलिस ने तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की।

उप्र के बलरामपुर में दोहरी नागरिकता के आरोप में 25 नेपालियों पर मामला दर्ज

बलरामपुर । उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के जरवा कोतवाली में 25 नेपालियों के विरुद्ध दोहरी नागरिकता के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि फर्जी ढंग से विभिन्न सरकारी दस्तावेज बनवाकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कई महीनों से रह रहे थे। तुलसीपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी अभय कुमार मल्ल ने शनिवार को बताया कि पुलिस उप निरीक्षक शंभु सिंह की तहरीर पर नामजद मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है। नामजद आरोपितों में अब्दुल कादिर सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, अब्दुल अलीम, खुतीजा खातून, अब्दुल वाहिद, करीम सिद्दीकी, समीउल्लाह, अब्दुल रहमान, निसार अहमद, अब्दुल रहीम, जकरुनिशा, जाहिद खातून, हलीमा खातून, रेशमा, कमाल अहमद, जमीला, शाहिद अख्तर, सनाउल्लाह, निसरत, नूरसबा, यासिर अराफात, ओसामा, सनाउल्लाह और अनस सिद्दीकी, फातिमा सिद्दीकी एवं सोनू सहित 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दर्ज मुकदमे के मुताबिक यह लोग नेपाल के निवासी हैं, लेकिन कई भारतीय दस्तावेजों में भी इनका नाम दर्ज है। उल्लेखनीय है कि भारत का संविधान सिर्फ एकल नागरिकता की मान्यता देता है।

इनर व्हील क्लब ऑफ मुरादाबाद एसेंस ने दिया हरित पर्यावरण का संदेश

मुरादाबाद । इनर व्हील क्लब ऑफ मुरादाबाद एसेंस द्वारा शनिवार को निवास सोसाइटी (परंपरा–2) परंपरा इलाइट एवं गौर ग्रेसियस में दो दिवसीय पौधारोपण अभियान का शुभारंभ हुआ। अभियान के तहत आम, अमरुद, जामुन, आड़ू, एवं नीम सहित 200 पौधों का रोपण किया गया। क्लब अध्यक्ष मोना गुप्ता ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में पौधरोपण महत्वपूर्ण कदम है। अभियान में उपाध्यक्ष अंशु गुप्ता, सचिव जूही सिंघल, कोषाध्यक्ष सोनल वाधवा, शिखा गोयल, सारिका खंडेलवाल, अंशु गुप्ता, डॉ. शालू महाजन आदि क्लब की सदस्यों ने पौधरोपण कर लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के माध्यम से हरित एवं स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया गया।

ससुराल से लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत

बल्दीराय/सुलतानपुर। बल्दीराय थाना क्षेत्र के देहली बाजार स्थित पेट्रोल पंप के समीप शनिवार को सड़क किनारे गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले एक युवक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बल्दीराय भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान जगत पाल (30) पुत्र हितलाल, निवासी ग्राम सेमरौना, थाना धनपतगंज, जनपद सुलतानपुर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह अयोध्या जनपद के कुमारगंज क्षेत्र स्थित अपनी ससुराल से बाइक द्वारा अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान देहली बाजार के पास वह सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़ा मिला। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से हुए सड़क हादसे का प्रतीत हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

आगामी 11 जुलाई को होने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक

कैनविज टाइम्स संवाददाता

सुलतानपुर। जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनुराग सक्सेना के निर्देशानुसार पर्यावरण संरक्षण एवं हरित अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संगठन द्वारा जिले में व्यापक पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी क्रम में सुल्तानपुर इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पौधरोपण अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में अभियान की तिथि, स्थान, सहभागिता एवं जनजागरूकता से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में महामंत्री अयोध्या मण्डल नीरज तिवारी, जिलाध्यक्ष रामानन्द मिश्रा, महामंत्री फरीद अहमद अर्शी ब्लाक अध्यक्ष कुड़वार धर्मेंद्र कुमार तिवारी उपाध्यक्ष विजय प्रकाश तिवारी, महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा संगठन मंत्री रामराज पांडेय सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर हो अमहट चौराहा का नामकरण : सुशील त्रिपाठी

सुलतानपुर। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर नगर की पश्चिमी सीमा स्थित अमहट चौराहा का नाम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक किए जाने की मांग उठाई है। इस संबंध में उन्होंने 3 जुलाई को जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित कर जनभावनाओं के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की अपेक्षा की है। भाजपा जिला मीडिया प्रमुख विजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के उपलक्ष्य में 6 जुलाई तक चल रहे विशेष स्मृति पखवाड़े के दौरान यह मांग की गई है। जिलाध्यक्ष ने अपने पत्र में कहा है कि अमहट चौराहा सुलतानपुर नगर का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार और प्रमुख यातायात केंद्र है, जहां प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है।

सार्वजनिक रास्ते पर कथित कब्जे से ग्रामीण परेशान

कैनविज टाइम्स संवाददाता

राजस्व टीम के जाने के बाद भी दबंग ने नहीं हटाया अतिक्रमण

बल्दीराय/सुल्तानपुर। तहसील बल्दीराय क्षेत्र के ग्राम बधौना में सार्वजनिक रास्ते पर कथित अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। गांव निवासी इंद्रदेव पुत्र स्वर्गीय विन्देश्वरी प्रसाद ने उपजिलाधिकारी बल्दीराय को प्रार्थना पत्र देकर ग्राम सभा की भूमि से अतिक्रमण हटवाने की मांग की। उप जिलाधिकारी प्रवीण कुमार ने शिकायत को तुरंत संज्ञान में लेते हुए संबंधित लेखपाल को मौके पर रास्ते से अतिक्रमण हटाए जाने का आदेश दिया लेखपाल मौके पर गए तो दबंग ने अवैध अतिक्रमण हटाने से मना कर दिया। शिकायत के अनुसार, ग्राम सभा की गाटा संख्या 1370 राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज है। आरोप है कि उक्त भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर रास्ते के दोनों ओर लोहे के तार लगा दिए गए हैं, जिससे आमजन का आवागमन बाधित हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस कारण उन्हें दैनिक कार्यों के लिए आने-जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राजस्व विभाग की टीम द्वारा मौके का निरीक्षण किए जाने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर उन्हें धमकियां दी गईं। मामले को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से राजस्व विभाग एवं पुलिस बल की संयुक्त मौजूदगी में अतिक्रमण हटवाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में रास्ता अवरुद्ध होने से स्थिति और गंभीर हो गई है। उनका आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से सार्वजनिक रास्ते को शीघ्र कब्जामुक्त कराकर आवागमन बहाल करने तथा मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

युवती साथ में नही भागी तो प्रेमी ने मुंह दबाकर मार डाला

कैनविज टाइम्स संवाददाता

अमेठी पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर मृतका का मोबाइल फोन किया बरामद

पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करने वाली टीम को पच्चीस हजार रुपये का पुरस्कार दिया

अमेठी,थाना अमेठी पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम ने रणवीर नगर जंगल रामनगर में बीती एक जुलाई को हुई काजल की हत्या का खुलासा करते हुये उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है जिसके कब्जे से मृतका का मोबाइल फोन बरामद किया गया है। थाना क्षेत्र के ग्राम रणवीरनगर मजरे जंगल रामनगर में खेत में बीती एक जुलाई को एक युवती का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। घटना सूचना पर थाना अमेठी पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया तथा मृतका की पहचान काजल पुत्री अमरजीत सिंह उम्र उन्नीस वर्ष के रूप मे हुई थी।मृतका के पिता श्री अमरजीत पुत्र राम बचन सिंह द्वारा थाना अमेठी पर तहरीर देकर सुरजीत सिंह पुत्र अरविन्द सिंह निवासी ग्राम पूरे नेवली पोस्ट रेहुआ लालगंज थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ व उसके कुछ साथी अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था।पुलिस अधीक्षक सरवणन टी. द्वारा घटना के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दस टीमों का गठन कर आवश्यक आदेश-निर्देश दिये गये थे। शनिवार को थाना अमेठी के प्रभारी निरीक्षक श्रीराम पाण्डेय, स्वाट टीम प्रभारी अनूप सिंह एवं सर्विलांस टीम प्रभारी बृजेश सिंह मय हमराह द्वारा सुरजीत पुत्र अरविन्द सिंह निवासी ग्राम पूरे नेवली पोस्ट रेहुआ लालगंज थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से मृतका का एक नोकिया मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस टीम द्वारा की गई पूंछतांछ में उसने बताया कि वह काजल से प्रेम करता था उसे मिलने के लिये उसे उसके घर के बाहर बुलाया था तथा अपने साथ ले जाने के लिये कह रहा था लेकिन वह चलने के लिये तैयार नहीं थी। काजल द्वारा साथ चलने से मना करने पर उसे क्रोध आ गया और उसने काजल का मुंह दबाकर वहीं गिरा दिया था मुंह दबाने से उसकी मृत्यु हो गयी थी फिर उसने शव को मेड़ के किनारे रखकर उसके ऊपर पास में पड़े यूकेलिप्टस की झाड़ झंकाड़ डाल दिया था और वहां से भाग गया था। इस सम्बंध में पुलिस अधीक्षक सरवणन टी ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा पकड़े गये युवक को जेल भेज दिया गया है और घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को पच्चीस हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया है।

पूरनपुर पुलिस का बड़ा खुलासा: दो बाल अपचारी गिरफ्तार, 5 चोरी की बाइक बरामद, कई वारदातों का हुआ पर्दाफाश

पूरनपुर।कोतवाली पूरनपुर पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं के खुलासे में बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की पांच मोटरसाइकिलें बरामद की हैं यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत की शनिवार को प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त पर थी इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मंडी समिति की दीवार के किनारे मकरंदापुर खड़ंजा मार्ग पर दो संदिग्ध युवक पांच मोटरसाइकिलों के साथ खड़े हैं और उन्हें बेचने की फिराक में हैं सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों को घेराबंदी कर पकड़ लिया पूछताछ में दोनों ने अपनी पहचान विवेक पुत्र हरिराम निवासी ग्राम मैना कोट, थाना माधोटांडा, तथा नितिन सक्सेना पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम नजीरगंज दुर्जनपुर कला, थाना सेहरामऊ उत्तरी के रूप में बताई दोनों बाल अपचारियों ने पूछताछ में स्वीकार किया ।

सभासद नादिर रजा बरकाती के पत्र का केंद्रीय मंत्री ने लिया संज्ञान स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम बृजेश पाठक को लिखा पत्र

पूरनपुर कैनविज टाइम्स संवाददाता। क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ईएनटी नाक, कान एवं गला विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए कुछ दिन पूर्व नगर पालिका परिषद पूरनपुर के सभासद नादिर रजा बरकती ने केंद्रीय मंत्री को पत्र भेजा था।केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने सभासद के पत्र को संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को पत्र लिखा है। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने ईएनटी विशेषज्ञ की नियुक्ति के संबंध में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई कराने का अनुरोध किया है।

मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची प्रकाशित

अमेठी कैनविज टाइम्स संवाददाता। अपर जिलाधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ज्योति सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में जनपद के मतदेय स्थलों के सम्भाजन (रैशनलाइजेशन) से संबंधित आलेख्य सूची का प्रकाशन चार जुलाई को कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त सूची जनपद की समस्त तहसीलों, जिला निर्वाचन कार्यालय अमेठी तथा जनपद की आधिकारिक वेबसाइट अमेठी एनआईसी इन पर निःशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी। जनसामान्य निर्धारित स्थानों पर जाकर सूची का अवलोकन कर सकते हैं। अपर जिलाधिकारी ज्योति सिंह ने बताया कि यदि किसी नागरिक, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल अथवा संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को मतदेय स्थलों के सम्भाजन के संबंध में कोई सुझाव, शिकायत अथवा आपत्ति हो तो वे अपनी आपत्तियां एवं सुझाव चार जुलाई से बारह जुलाई तक संबंधित तहसील अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी जिससे मतदाताओं की सुविधा एवं निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक सुगम एवं प्रभावी बनाया जा सके। जिला प्रशासन ने जनपद के नागरिकों से अपील की है कि वे प्रकाशित सूची का अवलोकन कर आवश्यक होने पर निर्धारित अवधि के भीतर अपने सुझाव एवं आपत्तियां अवश्य दर्ज कराएं, ताकि मतदेय स्थलों के अंतिम निर्धारण में जनसहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

पिछूती के प्रधान पति से मारपीट पर पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

अमेठी कैनविज टाइम्स संवाददाता । थाना जगदीशपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत पिछूती के प्रधान पति रानीगंज कस्बे से दुकान बंधकर घर लौट रहे थे कि पहले से ही घात लगाये बैठे लोगों द्वारा उन पर हमला कर दिया गया जिससे वह लहूलुहान हो गये। पुलिस ने प्रधान पति की तहरीर पर एक नामजद और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्जकर मामले की जांच पड़ताल शुरु कर दी है। थाना क्षेत्र के गांव पूरे पंचम मिश्र नसीराबाद मजरे पिछूती निवासी रमेश कुमार मिश्र पुत्र श्री कृष्ण राम मिश्र ने पुलिस को सौंपी गई तहरीर में लिखा है कि वह शुक्रवार की शाम को रानीगंज कस्बे से दुकान बंद करके गांव के सहज राम व सुनील गोस्वामी के साथ अपने घर के लिये जा रहा था। कचनांव मोड़ नहर के पास पहुचा तो रघुवीर सिंह उर्फ भोला पुत्र अमर सिंह निवासी नसीराबाद पिछूती अपने चार अन्य साथियों के साथ लाठी डण्डा व लोहे की राड़ से जान से मारने की नियत से मारना शुरू कर दिये उन लोगो ने हम लोगो के सिर पर वार किये किन्तु हम लोग बचाव मे अपने हाथ से रोके जिस पर उन लोगो का लाठी डण्डा व राड हाथ पे लगा जिससे मेरे वाये हाथ मे व सुनील गोस्वामी के दाहिने हाथ मे व सहजराम के वाये हाथ में कई वार लगातार करने से चोटे आई और फैक्चर हो गया। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग जब दौड़ पड़े तो घटना को अंजाम देने वाले लोग भाग निकले। घायलावस्था में प्रधान पति और उनके दो साथियों को सीएचसी जगदीशपुर ले जाया गया जहां पर चिकित्सकों द्वारा उपचार किया गया। इस सम्बंध में कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र कुमार यादव ने बताया कि प्रधान पति की तहरीर पर एक नामजद और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्जकर लिया गया है।

कांवड़ यात्रा, रक्षाबंधन और त्योहारों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट, डीएम ने जारी किए कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश

कैनविज टाइम्स संवाददाता

पीलीभीत।आगामी कांवड़ यात्रा, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, ईद-ए-मिलाद बारावफात सहित विभिन्न धार्मिक आयोजनों और प्रतियोगी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने पूरे जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानेन्द्र सिंह द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 29 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि विभिन्न माध्यमों से ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि कुछ असामाजिक एवं अराजक तत्व सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, जातीय और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने तथा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं इसी आशंका को देखते हुए एहतियातन यह आदेश लागू किया गया है आदेश के तहत बिना अनुमति किसी भी प्रकार की जनसभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या सार्वजनिक आयोजन नहीं किया जा सकेगा सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध रहेगा हालांकि यह प्रतिबंध सरकारी कार्य से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू नहीं होगा प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर लाठी, डंडा, तलवार, चार इंच से अधिक ब्लेड वाले चाकू, बंदूक, पिस्टल, रिवॉल्वर या अन्य हथियार लेकर चलने और उनके प्रदर्शन पर रोक लगा दी है केवल ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मियों, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सहारे वाले डंडे तथा सिख समुदाय के कृपाण को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है आदेश के अनुसार बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के लाउडस्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और ड्रोन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और न्यायालयों के 100 मीटर के दायरे को शांत क्षेत्र घोषित किया गया है ।

कलयुग में श्रवण कुमार की मिसाल बने मालियाण परिवार के बेटे पिता की सेवा कर रचा इतिहास हो रही चारों तरफ प्रशंसा

कैनविज टाइम्स संवाददाता

देहरादून।लाखामंडल का जनता होटल बना संस्कारों का तीर्थ बेटी भाजपा नेत्री बचना शर्मा बोलीं भाइयों ने सिखाया माता-पिता की सेवा कैसे होती है। जिस युग में बच्चे अपने जन्मदाता को वृद्धाश्रम की राह दिखा रही हैं।उसी कलयुग में लाखामंडल के मालियान परिवार ने पितृ-भक्ति की ऐसा इतिहास लिखा है।कि पूरा जौनसार बावर नतमस्तक है। स्व. पंडित बालक राम शर्मा के 6 पुत्रों ने अपने पिता की अंतिम सांस तक दिन-रात सेवा कर त्रेता युग के श्रवण कुमार को जीवंत कर दिया। मालियाण परिवार के 93 वर्षीय मुखिया लाखामंडल मंदिर पुजारी एवं क्षेत्र के प्रतिष्ठित बुजुर्ग पंडित बालक राम शर्मा कहीं वषों से ?अस्वस्थ व 93 वर्ष की ?वृद्धा ?उम्र होने ?के कारण बिस्तर में चार साल से थे।लेकिन उनके जाने से पहले उनके पुत्रों क्रमश रामप्रसाद शर्मा,केशव राम शर्मा,विनोद शर्मा,सुभाष शर्मा,बाबूराम शर्मा एवं सुरेश शर्मा ने जिस समर्पण से उनकी सेवा की थी। वह आज हर किसी जुबान पर है। बहुओं ने भी ससुर की सेवा में रात-दिन एक कर दिया। न दवा का समय चूका,न भोजन का, न ही कभी पिता के चेहरे पर शिकन आने दी।भाजपा की पूर्व मंडल उपाध्यक्ष एवं आईटी बीपी ? आंतरिक शिकायत समिति ? सदस्य ?एवहै में न्दजौनसार बावर जन कल्याण समिति की अध्यक्ष बचना शर्मा ने ?भावुक होकर बताया पिताजी के जाने का दुःख शब्दों से परे है। लेकिन आज भी हमारा पुरा परिवार पिताजी के दिऐ संस्कारों पर ही चल रहा है।मेरे भाइयों और भाभियों ने उनकी जो सेवा की उस पर मुझे गर्व है। बचपन में पिताजी ने हमें यही संस्कार दिए थे। कि माता-पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। हम आज भी उन्हीं संस्कारों पर चल रहे हैं। मेरे भाइयों ने पूरे समाज के सामने मिसाल पेश की है। कि वृद्ध माता-पिता की सेवा कैसे की जाती है। आज की पीढ़ी को इनसे सीख लेनी चाहिए। ग्रामीण बताते हैं कि स्व. पंडित बालक राम शर्मा का घर 'जनता होटल' के नाम से प्रसिद्ध है। पौराणिक महादेव का शिव मंदिर लाखामंडल के दर्शन को देश-विदेश से आने वाला कोई भी श्रद्धालु, यात्री या साधु-संत यदि मालियाण परिवार के दरवाजे पर पहुंच जाए तो वह भूखा-प्यासा नहीं लौटता। स्व. पंडित बालक राम शर्मा ने अपने जीवनकाल में हमेशा दुखियों असहायों और जरूरतमंदों की मदद की। वही परंपरा उनके बच्चे आज भी निभा रहे हैं।

गौरीगंज के पूर्व विधायक दादा तेजभान सिंह के निधन से गम में डूबी अमेठी

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और राज्यमंत्री के साथ ही विधायक ने शोक जताया

कैनविज टाइम्स संवाददाता

अमेठी,विधानसभा क्षेत्र गौरीगंज के पूर्व विधायक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता दादा तेजभान सिंह का शनिवार को लखनऊ के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। उनके निधन की सूचना मिलते ही जनपद में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी,क्षेत्रीय सांसद, राज्यमंत्री,विधायक, ब्लाक प्रमुख के साथ ही अन्य तमाम जनप्रतिनिधियों और सम्भ्रांत नागरिकों ने शोक संवेदना व्यक्त किया है। बताते चलें कि गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के गांव अचलपुर में सामान्य कृषक परिवार में जन्मे दादा तेजभान सिंह युवावस्था में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और बाद में जनसंघ तथा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। बीते वर्ष 1977 में जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में गौरीगंज विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। इसके बाद वर्ष 1991, 1993 और 1996 में भाजपा के टिकट पर गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।अपने मिलनसार स्वभाव, सरल व्यक्तित्व और पारिवारिक सम्बंधों के कारण वह क्षेत्र की जनता के बीच ''दादा'' के नाम से जाने जाते थे। भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से उनके अच्छे सम्बंध भी रहे। बताया जाता है कि दादा तेजभान सिंह को वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने के बावजूद उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई बगावती रुख नही अपनाया और संगठन के प्रति अपनी निष्ठा बनाये रखी। वह जनपद अमेठी की राजनीति के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते रहे उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूर्णनीय क्षति मानी जा रही है। पूर्व विधायक दादा तेजभान सिंह के निधन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, डॉ संजय सिंह, राज्यमंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह, सांसद किशोरी लाल शर्मा, गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा के जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला, सीएमओ डॉ अंशुमान सिंह,आशीष शुक्ला, विजय विक्रम सिंह,दीपक सिंह, चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी, ब्लाक प्रमुख कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, उमेश प्रताप सिंह, आकर्ष शुक्ला, राजेश विक्रम सिंह,अंकित पासी, केशव सिंह, गोविंद सिंह चौहान,मनीष पाठक, धर्मेश मिश्रा, मनीष सिंह बाबूपुर, सोनू यज्ञसैनी,चंद्र मौलि सिंह, विषुव मिश्रा सहित अन्य तमाम जनप्रतिनिधियों ने नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया है।

जुलाई माह के अंत तक दालमंडी चौड़ीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा

वाराणसी। वाराणसी में दालमंडी चौड़ीकरण अभियान में मस्जिदों पर चल रहे हथौड़े की आवाज के बीच लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के.के. सिंह ने कहा कि जुलाई माह के अंत तक दालमंडी चौड़ीकरण में चिन्हित मकानों मस्जिदों को जमींदोज करने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद मलबा हटाने के साथ ही निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा। एक मस्जिद को और तोड़े जाने के लिए वार्ता हुई है। बहुत जल्द ही उस पर भी हथौड़ा चलेगा। दालमंडी में ध्वस्तीकरण अभियान में मुख्य भूमिका निभाने वाले के.के.सिंह ने कहा कि दालमंडी में ध्वस्तीकरण अभियान के बाद एक सुगम रास्ता निकलेगा। जिससे काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने के लिए सरलता हो जाएगी।

वही, दूसरी ओर शनिवार को दालमंडी में मस्जिदों पर हथौड़ा चलाने के काम में और तेजी लाई गई। हथौड़े की आवाज से पूरी दालमंडी की गली शोरगुल से गूंज उठी। दालमंडी में मस्जिदों के बाहर फैला मलबा को भी हटाने का काम भी चलता रहा। दालमंडी में पहली बार देखा गया कि बड़े अधिकारी एक जगह खड़े होकर ध्वस्तीकरण को देखते हुए मिले।

कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर रहेगा विशेष फोकस

पीलीभीत।श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में गांधी सभागार में अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, पेयजल, सफाई और बिजली सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए जिलाधिकारी ने अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखने, धार्मिक स्थलों के आसपास साफ-सफाई, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए साथ ही कांवड़ मार्गों को गड्ढामुक्त करने, ढीले बिजली के तार ठीक कराने, एंबुलेंस और चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा यात्रा मार्ग पर मीट की दुकानें बंद रखने के निर्देश भी दिए उन्होंने मंडी परिसर में कांवड़ यात्रियों के लिए पेयजल, शौचालय और खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था कराने, पेड़ों की टहनियों की छंटाई कराने तथा पीलीभीत, पूरनपुर और बीसलपुर में निराश्रित गोवंशों को पकड़कर गौशालाओं में भेजने के निर्देश दिए पुलिस अधीक्षक ने डीजे संचालकों के साथ बैठक आयोजित करने और कांवड़ मार्गों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, डीएफओ, सभी उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे हैं।

रमई माइनर की क्षतिग्रस्त पुलिया दुर्घटना को दे रही दावत

तिलोई अमेठी कैनविज टाइम्स संवाददाता। तहसील तिलोई मुख्यालय से पीढ़ी मार्ग पर सफर तय करने वाले राहगीर जरा संभलकर चलें क्योंकि इस मार्ग की क्षतिग्रस्त पुलिया मौत को दावत दे रही हैं और जिम्मेदार अधिकारी शायद किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे है।क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही साथ नागरिकों ने आला अधिकारियों से रमई माइनर की क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत कराये जाने की सिफारिश की है।तहसील तिलोई मुख्यालय से पीढ़ी मार्ग पर लालगंज चौराहा के पास स्थित रमई माइनर की पुलिया एक लम्बे से टूटी हुई है जिस पर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी की नजर तक नही पड़ती है जिसके कारण राहगीर आये दिन दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं।ग्रामीणों की मानें तो पुलिया टूटने के कारण आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।इस मार्ग पर चलने वाले राहगीरों को पुलिया क्षतिग्रस्त होने की जानकारी नही मिल पाती जिससे वाहन माइनर में कूद जाता है। प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार तिवारी ने आला अधिकारियों से क्षतिग्रस्त पुलिया मरम्मत किये जाने की सिफारिश की है।

गैंगवार प्रकरण में अंकित मिश्रा को जमानत

सुल्तानपुर कैनविज टाइम्स संवाददाता। बहुचर्चित गैंगवार एवं फायरिंग प्रकरण में आरोपी अंकित मिश्रा को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1 ने जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ उपाध्याय ने प्रभावी ढंग से पैरवी करते हुए अदालत के समक्ष पक्ष रखा कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है, घटना में उसे गोली नहीं लगी और न ही उसके आपराधिक इतिहास का कोई ठोस रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने ?50,000 के निजी मुचलके एवं दो जमानतदारों पर अंकित मिश्रा की जमानत मंजूर कर ली। अधिवक्ता सिद्धार्थ उपाध्याय की प्रभावी पैरवी इस मामले में अहम साबित हुई।

6 से 20 जुलाई तक मिलेगा मुफ्त राशन, अंत्योदय कार्डधारकों को तीन माह की चीनी भी होगी वितरित

पीलीभीत।जिला पूर्ति अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि जनपद के सभी राशन कार्डधारकों को 6 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से आवश्यक खाद्यान्न वितरित किया जाएगा वितरण का समय सुबह 8 बजे से 12 बजे तथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है अंत्योदय कार्डधारकों को 21 किलो गेहूं और 14 किलो चावल निःशुल्क मिलेगा। साथ ही अप्रैल, मई और जून माह की कुल 3 किलो चीनी एक साथ 18 रुपये प्रति किलो की दर से वितरित की जाएगी वहीं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल निःशुल्क दिया जाएगा जिन लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है या ई-पॉस मशीन अंगूठा अथवा आंखों की पहचान स्वीकार नहीं कर रही है, वे 20 जुलाई को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकेंगे जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी कार्डधारकों से राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी जल्द से जल्द कराने की भी अपील की है।

सम्पादकीय

इथेनॉल का मोल

खाड़ी युद्ध के चलते उपजे ईंधन संकट ने भारत समेत पूरी दुनिया को सबक दिए हैं कि देश की ऊर्ज़ा जरूरतों को पूरा करने के लिये नये विकल्प तलाशे जाएं। भारत जैसे देश के लिये तो यह बड़ी चुनौती है क्योंकि हम पूरी तरह कच्चे तेल व गैस के लिये विदेशी संसाधनों पर ही निर्भर हैं। जिससे संकटपूर्ण स्थितियों में न केवल महंगाई बढ़ती है बल्कि हमारी दुर्लभ विदेशी मुद्रा भी दांव पर लगती है। ऐसे ही संकट से जूझने के लिये देश ने इथेनॉल के विकल्प पर गंभीरता से विचार किया। देश में पहले ही सामान्य पेट्रोल में बीस फीसदी इथेनॉल मिलाया जा रहा है। देश में विदेशी मुद्रा की बचत व आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। हाल ही में फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिये ज्यादा इथेनॉल वाले ई-85 फ्यूल उपलब्ध कराया गया। लेकिन अभी भी उपभोक्ताओं और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बीच कई मुद्दों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। दरअसल,ये वाहन ई-85 यानी 85 फीसदी इथेनॉल और 15 फीसदी पेट्रोल तथा ई-100 यानी शुद्ध इथेनॉल वाले मिश्रण पर चलने के लिये डिजाइन किये गए हैं। जबकि पेट्रोल से चलने वाली सामान्य गाड़ियां ई-20 यानी बीस फीसदी इथेनॉल और 80 फीसदी पेट्रोल के अनुकूल होती हैं। दरअसल, चुनिंदा आउटलेट्स पर ई-85 उपलब्ध कराने का निर्णय आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के मकसद से लिया गया है। यह एक हकीकत है कि आज भी देश का नब्बे फीसदी कच्चा तेल आयातित किया जा रहा है। दुनियाभर में गाहे-बगाहे पैदा होने वाले भू-राजनीतिक संकटों ने बार-बार देश के ऊर्ज़ा इकोसिस्टम की खामियों को ही उजागर किया है। इसमें दो राय नहीं है कि फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिये इथेनॉल को मुख्य ईंधन के रूप से बढ़ावा देने का मकसद ऊर्ज़ा जरूरतों में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में बढ़ना है। वहीं दूसरी ओर इसके उपयोग से हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी ला सकते हैं। निश्चय ही वाहनों में इथेनॉल को बढ़ावा देना देश में आयातित कच्चे तेल के दबाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। लेकिन इस बदलाव को सिरे चढ़ाने के लिए बहुत सोच-समझकर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे लोगों की आशंकाएं दूर हो सकें। जरूरत लोगों का भरोसा हासिल करने की है। भारत में इथेनॉल मिले तेल के उपयोग ने इससे होने वाले तमाम फायदों को साबित किया है। इससे काफी विदेशी मुद्रा की बचत भी हुई है। साथ ही देश में इथेनॉल का सशक्त उद्योग विकसित हुआ है। यदि बाजार में इथेनॉल पर लोगों का भरोसा बढ़ता है और इसकी मांग बढ़ती है तो इससे किसानों को कमाई के नये अवसर मिल सकते हैं। इथेनॉल की ज्यादा मांग होने पर गन्ने और मक्का का बाजार विस्तार लेगा। वहीं दूसरी ओर ई-85 की कीमत पारंपरिक पेट्रोल के मुकाबले कम रखने के फैसले से, उन उपभोक्ताओं को फायदा हो सकता है, जिनके पास इसके अनुकूल गाड़ियां है। भले ही इस फ्यूल की ईंधन दक्षता कम हो, लेकिन यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को संबल देगा। बहरहाल, इस उम्मीद के साथ ही, हमें हकीकत का भी ध्यान रखना है। दरअसल, ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों ने इंजन की क्षमता, जंग लगने, ईंधन सिस्टम पर प्रभाव और इसकी दीर्घकालिक क्षमता को लेकर चिंताएं जतायी हैं। निस्संदेह, इन मुद्दों को सीधे खारिज करने के बजाय इन पर गंभीर रूप से मंथन करना चाहिए। अगर इन मुद्दों का निराकरण नहीं होता है तो भ्रम व संशय की स्थिति बनी रहेगी। जिसे अविलंब दूर करने की भी जरूरत है। इस वैकल्पिक ईंधन की सहज उपलब्धता के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर व गाड़ियों को इसके अनुरूप बनाना, वैकल्पिक ईंधन की गुणवत्ता के मानकों का निर्धारण तथा इससे जुड़े तकनीकी प्रशिक्षण में सुधार किया जाना चाहिए। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि बॉयोफ्यूल इतनी जल्दी फॉसिल फ्यूल का विकल्प नहीं बन सकता। इस बाबत पर्याप्त तैयारी, पारदर्शिता और सभी हितधारकों का सहयोग लेना जरूरी है। इस मामले में जल्दबाजी करने से बचा जाना चाहिए। यदि हम सजगता व सतर्कता से आगे बढ़ते हैं तो ई-85 एक सफल मॉडल बन सकता है। अन्यथा हम एक अच्छा मौका चूक सकते हैं।

मजबूत लोकतंत्र के लिये दागी नेताओं से मुक्ति जरूरी

आए दिन संसद और विधानसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि से आने के बावजूद चुने गए जनप्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता तो जताई जाती है, मगर उसके हल को लेकर कोई ठोस पहल नहीं होती। संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता है और इस संबंध में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसी संदर्भ में भाजपा सरकार फिर से एक सौ तीसवें संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारी में है, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को पाँच साल से ज्यादा सजा के प्रावधान वाले गंभीर अपराधों के लिए गिरफ्तार किए जाने और लगातार तीस दिनों तक हिरासत में रखे जाने पर पद से हटाने का प्रस्ताव है। अगर विधेयक की जांच के बाद संयुक्त संसदीय समिति इसे अपनी मंजूरी दे देती है, तो संसद के मानसून सत्र में इस पर बहस की संभावना है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष अगस्त में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में यह विधेयक पेश किया था। हालांकि विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई कई आपत्तियों के बाद इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था, लेकिन कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी दलों ने अपनी चिंताओं को नजरअंदाज किए जाने की आशंका के मद्देनजर समिति का बहिष्कार कर दिया था। निश्चित ही संसद और विधानसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जनप्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है।

भारतीय लोकतंत्र ने स्वतंत्रता के बाद अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति होने के साथ-साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य के साथ देश आर्थिक, तकनीकी और वैश्विक नेतृत्व की नई ऊंचाइयों को छूने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। किंतु यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी अर्थव्यवस्था, सैन्य क्षमता अथवा तकनीकी विकास में नहीं, बल्कि उसकी राजनीति और शासन व्यवस्था की नैतिकता में निहित होती है। यदि लोकतंत्र की आत्मा को जीवित रखना है तो राजनीति को अपराध, भ्रष्टाचार और स्वार्थ की गिरफ्त से मुक्त करना ही होगा। आजादी के बाद से लगभग हर सरकार ने भ्रष्टाचार-मुक्त शासन, पारदर्शी प्रशासन और स्वच्छ राजनीति का वादा किया। अनेक आयोग बने, कानून बने और चुनाव सुधारों की चर्चाएं भी हुईं, लेकिन जब भी कोई ठोस एवं प्रभावी सुधार लागू करने का प्रयास हुआ, राजनीतिक दलों ने अपने-अपने हितों के अनुसार उसका समर्थन अथवा विरोध किया। परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक शुचिता का प्रश्न आज भी अधूरा है। विडंबना यह है कि अब तक कोई ऐसा खाका सामने नहीं आ सका है, जिससे सिर्फ स्वच्छ छवि के लोगों को ही जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिले। यह और बड़ी विडम्बना है कि जिस विषय पर पूरे राष्ट्र की सहमति होनी चाहिए, वही विषय राजनीतिक टकराव का माध्यम बन जाता है। आए दिन संसद और विधानसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि से आने के बावजूद चुने गए जनप्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता तो जताई जाती है, मगर उसके हल को लेकर कोई ठोस पहल नहीं होती। संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता है और इस संबंध में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसी संदर्भ में भाजपा सरकार फिर से एक सौ तीसवें संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारी में है, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को पाँच साल से ज्यादा सजा के प्रावधान वाले गंभीर अपराधों के लिए गिरफ्तार किए जाने और लगातार तीस दिनों तक हिरासत में रखे जाने पर पद से हटाने का प्रस्ताव है। अगर विधेयक की जांच के बाद संयुक्त संसदीय समिति इसे अपनी मंजूरी दे देती है, तो संसद के मानसून सत्र में इस पर बहस की संभावना है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष अगस्त में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में यह विधेयक पेश किया था। हालांकि विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई कई आपत्तियों के बाद इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था, लेकिन कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी दलों ने अपनी चिंताओं को नजरअंदाज किए जाने की आशंका के मद्देनजर समिति का बहिष्कार कर दिया था। निश्चित ही संसद और विधानसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जनप्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। यदि कोई जनप्रतिनिधि हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद अथवा संगठित अपराध जैसे गंभीर मामलों में लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में है, तो क्या वह जनता का प्रतिनिधित्व करने का नैतिक अधिकार बनाए रखता है? यह प्रश्न केवल कानूनी नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नैतिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हालांकि इस प्रकार के कानून पर कई संवैधानिक प्रश्न भी उठते हैं। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को तब तक निर्दोष मानता है जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए। केवल आरोप के आधार पर किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को पद से हटाना राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार भी बन सकता है। विपक्षी दलों की यह आशंका पूरी तरह निराधार नहीं कही जा सकती कि यदि पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं होंगे तो सत्ता में बैठी सरकारें विरोधियों के विरुद्ध जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर सकती हैं। इसलिए किसी भी नए कानून में प्राकृतिक न्याय, न्यायिक समीक्षा और निष्पक्ष जांच की सुदृढ़ व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। लेकिन इन आशंकाओं के कारण सुधार की पूरी प्रक्रिया को रोक देना भी उचित नहीं होगा। लोकतंत्र में सुधार का अर्थ किसी दल को लाभ या हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि जनता के विश्वास को मजबूत करना है। यदि कानून संतुलित, पारदर्शी और न्यायसंगत हो तो वह लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि अधिक विश्वसनीय बनाता है। भारत की राजनीति में अनेक ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, जिन्होंने लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाए। बिहार में लालू प्रसाद यादव से लेकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तथा उनके कुछ मंत्रियों तक, विभिन्न राजनीतिक दलों के अनेक नेता ऐसे रहे हैं जो गंभीर आरोपों अथवा जेल में रहने के बावजूद सत्ता पर बने रहने का प्रयास करते रहे। यह किसी एक दल का प्रश्न नहीं है, लगभग सभी बड़े राजनीतिक दल समय-समय पर इस आलोचना के घेरे में रहे हैं। जेल से सरकार चलाने अथवा संवैधानिक पद पर बने रहने की मानसिकता लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल नहीं कही जा सकती। यह सही है कि कानून अपना कार्य करेगा और न्यायालय अंतिम निर्णय देगा, किंतु सार्वजनिक जीवन केवल कानूनी वैधता से नहीं चलता, उसका आधार नैतिक वैधता भी होती है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि केवल अधिकारों का नहीं, बल्कि आदर्शों का भी प्रतीक होता है। यदि उसके ऊपर गंभीर आरोप हों और वह फिर भी पद से चिपका रहे, तो जनता का लोकतांत्रिक विश्वास कमजोर पड़ता है। राजनीति में पद त्यागना पराजय नहीं, बल्कि नैतिक साहस का परिचायक होता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उसमें आर्थिक प्रगति के साथ सुशासन, डिजिटल पारदर्शिता, भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन और जनभागीदारी पर विशेष बल दिया गया है। विकसित भारत केवल ऊंची इमारतों, एक्सप्रेस-वे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तेज आर्थिक विकास से नहीं बनेगा, वह तभी बनेगा जब शासन चलाने वाले व्यक्तियों की विश्वसनीयता भी उतनी ही मजबूत होगी। विश्वगुरु बनने की आकांक्षा रखने वाले राष्ट्र की राजनीति भी विश्व के लिए आदर्श बननी चाहिए। आज आवश्यकता केवल कानून बदलने की नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृति बदलने की भी है। राजनीतिक दलों को चुनावी टिकट देते समय उम्मीदवार के चरित्र, सार्वजनिक जीवन, सामाजिक सेवा और नैतिक छवि को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय कई बार राजनीतिक दलों से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने का कारण सार्वजनिक करने को कह चुका है, किंतु व्यवहार में इसमें अपेक्षित परिवर्तन दिखाई नहीं देता। यदि राजनीतिक दल स्वयं आत्मानुशासन नहीं अपनाएंगे, तो केवल कानून से समस्या का समाधान संभव नहीं होगा। इसके साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में भी व्यापक सुधार अपेक्षित हैं। जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों का वर्षों तक लंबित रहना लोकतंत्र के लिए घातक है। विशेष न्यायालयों द्वारा समयबद्ध सुनवाई, निष्पक्ष जांच और शीघ्र निर्णय की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि न निर्दोष व्यक्ति वर्षों तक संदेह के घेरे में रहे और न दोषी व्यक्ति कानून की तकनीकी जटिलताओं का लाभ उठाकर जनता का प्रतिनिधित्व करता रहे। लोकतंत्र की सफलता केवल संविधान से नहीं, बल्कि राजनीतिक चरित्र से सुनिश्चित होती है। जब तक राजनीति में नैतिकता, सेवा, त्याग और उत्तरदायित्व की भावना नहीं आएगी, तब तक भ्रष्टाचार और अपराध का दुष्चक्र पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, किंतु राष्ट्रीय हित से जुड़े सुधारों का विरोध केवल राजनीतिक लाभ-हानि के आधार पर नहीं होना चाहिए। यदि किसी प्रस्ताव में कमियां हैं तो उन्हें सुधारने के सुझाव दिए जाएं, लेकिन सुधार की दिशा को अवरुद्ध करना लोकतांत्रिक परिपक्वता का परिचायक नहीं माना जा सकता। आज भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक ओर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्वगुरु भारत का स्वप्न है, तो दूसरी ओर राजनीति की विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करने की चुनौती भी है। इन दोनों लक्ष्यों को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। आर्थिक विकास और नैतिक विकास समानांतर चलेंगे तभी राष्ट्र सशक्त बनेगा। समय की पुकार है कि सत्ता और विपक्ष दोनों दल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर लोकतंत्र की पवित्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। देश की राजनीति को आपराधिक छवि के लोगों से मुक्त करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए जो कानून बने, उसमें अपराधों की प्रकृति स्पष्ट किए जाने से लेकर ऐसे सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है, ताकि महज बदले या किसी सरकार को अस्थिर करने की मंशा से इसका दुरुपयोग न हो सके। – **ललित गर्ग**

लोककला से लोकसमृद्धि तकः बिहार के सांस्कृतिक पुनर्ज़ागरण की नई कहानी

डॉ. मीना कुमारी

बिहार की पहचान केवल नालंदा, वैशाली और बोधगया तक सीमित नहीं है। यह राज्य अपनी जीवंत लोक कलाओं, लोकगीतों और पारंपरिक शिल्प के कारण भी विश्व पटल पर विशिष्ट स्थान रखता है। मधुबनी चित्रकला, मंजूषा कला, सिक्की शिल्प, सुजनी कढ़ाई, बिदेसिया और जट-जटिन जैसी विधाएं बिहार की सांस्कृतिक आत्मा हैं। किंतु लंबे समय तक इन कलाओं के सृजक कलाकार सम्मान से अधिक संघर्ष का जीवन जीते रहे। उनके सामने बाजार का अभाव, पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन और संस्थागत समर्थन का संकट था। पिछले कुछ वर्षों में यह परिदृश्य बदलने लगा है। केंद्र की विरासत से विकास की नीति और बिहार सरकार के सांस्कृतिक संरक्षण एवं कौशल संवर्धन के प्रयासों ने लोक कलाकारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में उल्लेखनीय आधार तैयार किया है। आज पहली बार लोककला को केवल सांस्कृतिक धरोहर नहीं बल्कि क्रिएटिव इकोनॉमी यानी रचनात्मक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में देखा जा रहा है। इसी सोच के अनुरूप भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए अलग नीति आधारित पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक उद्योगों को रोजगार, नवाचार और वैश्विक बाजार से जोड़ना है। इस परिवर्तन की सबसे बड़ी पहचान प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है। परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों को पहचान, कौशल उन्नयन, आधुनिक औजार, आसान ऋण, डिजिटल भुगतान और विपणन सहायता देने वाली यह योजना पहली बार शिल्पकार को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि उद्यमी के रूप में स्थापित करती है। बिहार में इसके परिणाम उल्लेखनीय रहे हैं। सरकारी आँकड़ों के अनुसार राज्य में 1.62 लाख से अधिक पारंपरिक कारीगर पंजीकृत हुए, 1.05 लाख से अधिक को प्रशिक्षण मिला, लगभग 19 हजार लाभार्थियों को 160 करोड़ रुपये से अधिक का रियायती ऋण मिला तथा हजारों आधुनिक टूल किट वितरित किए गए। लाभार्थियों में बड़ी संख्या अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं की है। यह परिवर्तन केवल एक योजना का परिणाम नहीं है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) जैसी पहल ने जिलों की विशिष्ट कला और उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान देने का नया अवसर दिया है। बिहार के हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पाद अब स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रह गए हैं बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार से जोड़ने की रणनीति विकसित की जा रही है। बिहार सरकार ने भी इस दिशा में समानांतर प्रयास किए हैं। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा आयोजित बिहार दिवस, राज्य स्तरीय लोक महोत्सव, जिला स्तरीय सांस्कृतिक आयोजन, कलाकार सम्मान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने लोक कलाकारों को मंच उपलब्ध कराया है। पटना का बिहार संग्रहालय तथा विभिन्न सांस्कृतिक संस्थान राज्य की लोक परंपराओं को नई पीढ़ी और पर्यटकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार संरक्षण की पारंपरिक सोच से आगे बढ़कर संस्कृति को विकास के संसाधन के रूप में देख रही है। मधुबनी चित्रकला इसका सबसे प्रेरक उदाहरण है। जीआई (ज्योग्राफिकल इंडिकेशन) टैग मिलने के बाद इस कला की वैश्विक पहचान और मजबूत हुई है। मिथिलांचल की हजारों महिला कलाकार आज स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से देश-विदेश के बाजारों तक पहुंच रही हैं। यह केवल कला का विस्तार नहीं बल्कि महिला उद्यमिता और ग्रामीण आत्मनिर्भरता का भी सशक्त मॉडल है। आज विश्व स्तर पर भी यही दृष्टिकोण विकसित हो रहा है। रचनात्मक उद्योगों को रोजगार, समावेशी विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। भारत ने भी जी-20 के बाद संस्कृति को विकास की केंद्रीय धुरी के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस पहल की है। निःस्संदेह, चुनौतियाँ अभी भी हैं। सभी कलाकारों का डिजिटल डेटाबेस तैयार होना बाकी है। विपणन क्षमता को और मजबूत करना होगा। डिज़ाइन नवाचार, निर्यात, ई-कॉमर्स, पर्यटन और बौद्धिक संपदा संरक्षण के क्षेत्र में अभी व्यापक संभावनाएँ हैं। किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि आज नीति की दिशा पहले की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट और दूरदर्शी दिखाई देती है। आगे की रणनीति भी स्पष्ट होनी चाहिए- लोक कलाकारों का राज्यव्यापी डिजिटल रजिस्टर, सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट, विश्वविद्यालयों में लोककला अध्ययन, ई-कॉमर्स आधारित विपणन, निर्यात प्रोत्साहन और युवाओं के लिए कौशल कार्यक्रम। यदि इन पहलों को वर्तमान योजनाओं के साथ जोड़ा जाए तो बिहार की लोक कलाएं लाखों परिवारों की आय का स्थायी आधार बन सकती हैं।

सेहत मंत्र

गर्मी और बारिश के मौसम में जरूर करें सफ़ेद प्याज का सेवन, सेहत को मिलेंगे गजब के लाभ

गर्मियों और बारिश के मौसम में संक्रमण का खतरा अधिक होता है। खासतौर पर जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है या जिनकी डेस्क जॉब होती है उन्हें अक्सर आंखों में थकान, पेट में गैस और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत रहती है। ऐसे में सफ़ेद प्याज का सेवन इन सभी समस्याओं को दूर करने में फायदेमंद साबित हो सकता है। खासतौर पर गर्मियों और बारिश के मौसम में सफ़ेद प्याज का सेवन जरूर करना चाहिए। इसमें एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी एलर्जिक गुण मौजूद होते हैं। सफ़ेद प्याज में विटामिन ए विटामिन बी आयरन फोलिक ऑपरेशन जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। गर्मी और बारिश के मौसम में सफ़ेद प्याज का सेवन करने से कई बीमारियों से बचाव होता है। सफ़ेद प्याज में पोटैशियम की भरपूर मात्रा मौजूद होती है। इसके सेवन से शरीर ठंडा रहता है और गर्मी में लू लगने से बचाव होता है। सफ़ेद प्याज खाने से शरीर की इम्युनिटी मजबूत होती है और संक्रमण से बचाव होता है। सफ़ेद प्याज खाने से जोड़ों के दर्द की समस्या से राहत मिलती है। इसमें फोलेट और विटामिन बी6 की प्रचुर मात्रा होती है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। इसलिए जिन लोगों की डेस्क जॉब होती है उन्हें गर्मी और बारिश के मौसम में सफ़ेद प्याज का सेवन करना चाहिए। सफ़ेद प्याज का सेवन करने से आंखों को भी फायदा होता है। खासतौर पर कंप्यूटर पर काम करने वाले लोगों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। सफ़ेद प्याज खाने से आंखों में थकान, भारीपन और पानी आने की समस्या दूर होती है। जिन लोगों को ज्यादा थकान महसूस होती है उन्हें सफ़ेद प्याज का सेवन करना चाहिए। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है जो शरीर में ब्लड सरकुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है। इससे शरीर में ऊर्ज़ा का स्तर बढ़ता है। सफ़ेद प्याज का सेवन करने से पेट संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, जिससे पेट में गैस और पेट फूलने की समस्या दूर होती है।

धर्म मंत्र

वास्तु दोषों के प्रभाव को कम करती है भगवान गणेश की प्रतिमा

अपना घर बनाना हर किसी का सपना होता है, और घर बनाते समय तमाम सावधानियां भी प्रत्येक मनुष्य रखता ही है। बावजूद इसके, अगर आपको लगता है कि आप के बने हुए भवन में वास्तु-दोष है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वास्तु शास्त्र में भगवान गणेश की प्रतिमा से कई सारे वास्तु-दोष निवारण की विधियां बताई गई हैं। आप उनका सटीक प्रयोग कर अपने घर में मौजूद वास्तु दोष से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप के भवन में नकारात्मकता ज्यादा है और सुख-समृद्धि में कमी हो रही है तो आप अपने मुख्य द्वार पर भगवान गणेश का बंदनवार लगाकर अपने इस कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। वैसे भी घर का मुख्य द्वार साफ सुथरा और स्वच्छ रहे तो इससे नकारात्मक शक्तियां ही दूर होती हैं। बावजूद इसके भगवान गणेश का बंदनवार लगाने से सकारात्मक शक्तियों को घर में प्रवेश करने का रास्ता मिलता है। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से आपके व्यवसाय में लगातार घाटा हो रहा है और आपकी कंपनी तथा फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें गिरावट आती जा रही है तो आपको इसके निवारण के लिए भगवान गणेश की प्रतिमा का चुनाव करना चाहिए। इसके लिए आप गणेश जी के प्रतिरूप 'स्वास्तिक' को ताम्र-पत्र में या फिर पूजा की थाली में स्थापित करने और नियमित रूप से इसकी पूजा करें। देखते - देखते आपके गिरे हुए व्यवसाय में वृद्धि आएगी और आप उन्नति करेंगे।

पर्यटन

हिमाचल प्रदेश में स्थित मैक्लोडगंज, जिसकी प्राकृतिक खूबसूरती किसी जन्नत से कम नहीं

जब बात आती है कहीं घूमने-फिरने के चुनाव करने की तो हम ऐसी-ऐसी जगहों का चयन करना ज्यादा पसंद करते हैं, जहां खूबसूरती के साथ हसीन वादियों का मजा उठाने को मिल सके। इसी के साथ ही हम उन जगहों पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं जो किसी जन्नत से कम न लगे। वहीं, अगर बात करें भारत में मौजूद जगहों की तो ये कई भौगोलिक विविधताओं से भरी हुई है। यहां के खान-पान, बोली, रहन-सहन, सभ्यता, पहनावा एवं संस्कृति और संस्कार पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल देती है। भारत की जगह ऐतिहासिक महलों, कुदरती नजारों और प्रकृति की दिल जीत लेने वाली सुंदरताओं से घिरी हुई है। भारत को एक बहुत ही खूबसूरत देश माना जाता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित मैक्लोडगंज। जिसकी प्राकृतिक खूबसूरती किसी जन्नत से कम नहीं । मैकलॉडगंज, हिमाचल प्रदेशः हिमाचल प्रदेश में कई जगह ऐसी-ऐसी हैं जहां की खूबसूरती अपने आप में ही काफी फ़ेमस है। इन्हीं में से एक है हिमाचल प्रदेश में स्थित मैक्लोडगंज। जिसकी प्राकृतिक खूबसूरती किसी जन्नत से कम नहीं है। यहां जाने के बाद दिल खुश हो जा सकता है। सर्दियों में तो यहां के नजारे देखने को बनते हैं। चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ की चादर देखने को मिलती है। तवांगः अरुणाचल प्रदेश की बहुत खूबसूरत जगहों में से एक तवांग है। इस जगह को कुदरत ने काफी खूबसूरती से सजाया है। दुनियाभर में ये जगह अपनी खूबसूरती के साथ-साथ बौद्ध मठों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहां पर अध्यात्म का अनुभव हो सकता है। यहां की खूबसूरती अपनी तरफ आकर्षित करती है। जम्मू-कश्मीरः जम्मू-कश्मीर अपनी हरियाली और खूबसूरत नजारों के लिए काफी फ़ेमस है। ये जगह भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। यहां की प्राकृतिक खूबसूरती काफी अलग है। यहां की खूबसूरती को श्रीनगर की 'डल झील' ओर ज्यादा बढ़ा देती है। यहां घूमने में भी अपना ही एक अलग मजा है।

'आग से पहले तैयारी',अलीगंज हादसे से सबक: बाराबंकी बना 'फायर सेफ सिटी'

विकास तिवारी

बाराबंकी। लखनऊ के अलीगंज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग के बाद योगी सरकार ने प्रदेश भर में फायर सेफ्टी पर शिकंजा कसा है। इसी क्रम में डीएम बाराबंकी ईशान प्रताप सिंह ने शहर की कमर्शियल इमारतों की जांच के निर्देश दिए हैं।

लेकिन नगर पालिका नवाबगंज ने 'आदेश का इंतजार' नहीं किया और अधिशासी अधिकारी संजय शुक्ला वह प्रथम पुरुष बन गए जो देखकर सीख लेते हैं। बिना विलंब शहर को आग से सुरक्षित करने की मुहिम छेड़ दी।

कहते हैं कि जब मैं यहां आया तो पता चला कि मुख्य बाजार में आग की 2 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में 1 करोड़ का माल जल गया, क्योंकि रास्ता एक था और अग्निशामक यंत्र नहीं थे। कल्पना साड़ी सेंटर में भी आग बेसमेंट तक फैल गई थी। उस समय दमकल को पानी भर-भरकर लाना पड़ा था।

8 से 24: तिगुना हुआ सुरक्षा कवच

पहले शहर में सिर्फ 7 अंडरग्राउंड + 1 ओपन = कुल 8 हाइड्रेंट थे। हमारे प्रतिनिधि शुभम अवस्थी से साक्षात्कार में ईओ श्री शुक्ला ने बताया कि वॉटर पंप बढ़ाने के साथ-साथ हाइड्रेंट की संख्या 24 कर दी है। अब फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए हर जोन में तुरंत पानी उपलब्ध होगा।

ईओ संजय शुक्ला की पहल 8 से बढ़कर हुई तिगुनी संख्या

''डीएम की जांच जारी, पालिका पहले से तैयार''

जबकि जिला प्रशासन अब कमर्शियल बिल्डिंग्स की फायर एनओसी जांच रहा है, नवाबगंज नगर पालिका जमीन पर पहले से मोर्चा संभाल चुकी है।

''बाराबंकी अब आग से नही डरेगा''

ईओ संजय शुक्ला ने बताया कि मुख्य बाजार में पहले 2 बड़ी आग लग चुकी हैं। तब पानी की कमी से दमकलकर्मी जूझे थे। इसलिए उन्होंने शहर में हाइड्रेंट की संख्या 8 से बढ़ाकर 24 कर दी। अब पीरबटावन, कटरा, मखदूमपुर, लखपेड़ा बाग, आनंद बिहार, नेहरू नगर, नबीगंज समेत हर बड़े इलाके में हाइड्रेंट मौजूद हैं।

डीएम जांच करा रहे हैं, पालिका बुझाने को तैयार है।

बाराबंकी में फायर सेफ्टी मजबूत: शहर में 24 हाइड्रेंट तैनात

प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में बाराबंकी के जिलाधिकारी ने शहर की कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी के इंतजामों की जांच के निर्देश दिए हैं। इस सरकारी कार्रवाई से पहले ही नगर पालिका परिषद नवाबगंज ने शहर में आग बुझाने की आधारभूत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजय शुक्ला ने व्यक्तिगत रुचि लेकर शहर में फायर हाइड्रेंट की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि कराई है।

पहले की स्थिति और समस्याएं

अधिशासी अधिकारी संजय शुक्ला के अनुसार, जब उन्होंने नवाबगंज नगर पालिका का कार्यभार ग्रहण किया, तो उस समय शहर में आग बुझाने के लिए कुल 8 हाइड्रेंट उपलब्ध थे। इसमें 7 अंडरग्राउंड हाइड्रेंट और 1 ओपन हाइड्रेंट शामिल था।

दो दर्जन हाइड्रेंट का नया नेटवर्क

घटनाओं से सबक लेते हुए ईओ संजय शुक्ला ने शहर में हाइड्रेंट की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया। नगर पालिका द्वारा जब शहर में वॉटर पंपों की संख्या बढ़ाई गई, तो उनके साथ-साथ नए हाइड्रेंट भी स्थापित कराए गए।

वर्तमान में बाराबंकी शहर में फायर ब्रिगेड को पानी उपलब्ध कराने के लिए कुल 24 हाइड्रेंट कार्यरत हैं। इस प्रकार पूर्व में उपलब्ध 8 हाइड्रेंट की तुलना में संख्या तीन गुना बढ़ गई है।

''इन अंचल में लगे हाइड्रेंट ''

नए हाइड्रेंट शहर के विभिन्न हिस्सों को कवर करते हैं। पुराने शहर के वार्डों में पीरबटावन उत्तरी क्षेत्र में बालदा रोड और टंडन की फुलवारी पर हाइड्रेंट लगाए गए हैं।

कटरा बारादरी, जेबरा पार्क के पास मखदूमपुर, आजादनगर, दशहरा बाग, जलालपुर और लखपेड़ा बाग में भी हाइड्रेंट स्थापित किए गए हैं। लखपेड़ा बाग में लगे हाइड्रेंट से आसपास का पूरा इलाका कवर हो जाता है।

नए शहर की बात करें तो आनंद बिहार में दो हाइड्रेंट, नेहरू नगर में एक और अस्सी फुटा रोड पर हाइड्रेंट लगाया गया है। अस्सी फुटा रोड का हाइड्रेंट नबीगंज क्षेत्र को भी पानी उपलब्ध कराता है।

नल बन गए 'राजनेता', वादा तेरा वादा.. पानी एक बूंद नहीं!

कैनविज टाइम्स संवाददाता

निंदूरा बाराबंकी। डबल इंजन सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना निंदूरा विकासखंड की कई ग्राम पंचायतों में दम तोड़ती नजर आ रही है। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद ग्राम पंचायत मोहसंड और बसारा समेत कई गांवों में ढाई वर्ष बाद भी पानी की टंकियां अधूरी पड़ी हैं। हालत यह है कि गांवों में नल तो लग गए, लेकिन उनमें पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंची। ग्रामीण तंज कस रहे हैं–''नल भी नेताओं जैसे हो गए हैं, वादे बहुत करते हैं, लेकिन पानी नहीं देते।''

2005 की टंकी बनी शोपीस, नई भी अधूरी

मोहसंड में वर्ष 2005 में बनी पानी की टंकी का उद्घाटन तो बड़े उत्साह से हुआ था, लेकिन ग्रामीणों का दावा है कि केवल एक रात कुछ जगहों पर पानी आया, उसके बाद आज तक टोटियों से पानी नहीं निकला। लाखों रुपये की वह योजना शोपीस बनकर रह गई।

इसी उम्मीद में वर्ष 2023 में नई टंकी का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन ढाई साल बाद भी परियोजना अधूरी है। अब ग्रामीणों को डर है कि कहीं यह टंकी भी पिछली योजना की तरह सिर्फ दिखावा बनकर न रह जाए।

करोड़ों खर्च, सड़कें खुदीं... फिर भी जलापूर्ति नहीं

निर्माण स्थल पर सोलर पैनल लगाए गए, जनरेटर रखे गए और गांवों में पाइपलाइन भी बिछा दी गई। लेकिन कई स्थानों पर पाइप खुले पड़े हैं और कनेक्शन तक नहीं हुए। इससे राहगीर और बच्चे गिरकर घायल हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जब समय पर योजना पूरी नहीं करनी थी तो आखिर गांव की सड़कें और इंटरलॉकिंग क्यों खोदी गई?

ढाई साल से अधूरी जल जीवन मिशन की परियोजनाएं, पानी में बहाएं करोड़ों,प्यासी 25 हजार आबादी

2005 की टंकी बनी शोपीस, 2023 की नई टंकी भी अधूरी; 2027 चुनाव से पहले सरकार की साख पर उठे सवाल.?

25 हजार लोगों के सामने पेयजल संकट

मोहसंड ग्राम पंचायत के लगभग 22 गांवों की करीब 25 हजार आबादी इस योजना के पूरा होने का इंतजार कर रही है। क्षेत्र में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है और हैंडपंपों के पानी का टीडीएस भी अधिक बताया जा रहा है। गर्मी के दिनों में पेयजल संकट और गहरा जाता है, लेकिन जल जीवन मिशन की अधूरी परियोजनाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं।

काम की रफ्तार कछुए जैसी

ग्रामीणों के अनुसार मोहसंड और बसारा दोनों जगह निर्माण कार्य बार-बार शुरू होकर बंद हो जाता है। कई दिनों से कार्यस्थलों पर न मजदूर दिखाई दे रहे हैं और न कोई निर्माण गतिविधि चल रही है। इससे परियोजना के जल्द पूरे होने की उम्मीदें भी धूमिल हो गई हैं।

चुनाव से पहले सरकार के लिए चुनौती

वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जल जीवन मिशन की अधूरी परियोजनाएं सरकार और प्रशासन के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती हैं। सरकार हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन निंदूरा क्षेत्र में लोग आज भी नलों से पानी आने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में विकास के दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक माना जा रहा है। जेई ने माना–फंड की कमी से हुई देरी जल जीवन मिशन के जूनियर इंजीनियर ऋषभ विश्वकर्मा के अनुसार निंदूरा विकासखंड की 73 ग्राम पंचायतों में से 18 स्थानों पर टंकियों का कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि फंड की कमी के कारण कार्य प्रभावित हुआ। बसारा में सड़क चौड़ीकरण के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जबकि मोहसंड में भी धनाभाव के चलते काम रुका था। उनका कहना है कि बसारा में 15 दिनों के भीतर कार्य दोबारा शुरू कराया जाएगा और मोहसंड में शेष निर्माण भी जल्द पूरा कराया जाएगा।

सबसे बड़ा सवाल

करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं, पाइपलाइन बिछ चुकी है, टंकियां खड़ी हैं... लेकिन आखिर ग्रामीणों के घरों के नलों से पानी कब निकलेगा? यही सवाल अब पूरे क्षेत्र की जनता प्रशासन और जिम्मेदार विभाग से पूछ रही है।

सफाई का आश्वासन समाजसेवी का अनशन समाप्त

मसौली बाराबंकी कैनविज टाइम्स संवाददाता। ग्राम पंचायत अनूपगंज में नाला सफाई की मांग को लेकर अर्धनग्न होकर अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल पर बैठे समाजसेवी अताउर्रहमान अंसारी ने प्रशासन के आश्वासन के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। फ़ैज़ानुल उलूम जूनियर हाई स्कूल से पुतनहिया तालाब तक जाने वाले नाले की लंबे समय से सफाई न होने के कारण जलभराव और गंदगी की समस्या बनी हुई थी। सोशल मीडिया पर मामला सामने आने के बाद ग्राम विकास अधिकारी पवन कुमार मौके पर पहुंचे और शीघ्र सफाई कराने का भरोसा दिया। इसके बाद उन्होंने खजूर खिलाकर और पानी पिलाकर समाजसेवी का अनशन समाप्त कराया।

115 के बंटवारे में खूनी संघर्ष, चार घायल

मसौली बाराबंकी कैनविज टाइम्स संवाददाता। सफदरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम कंधईपुरवा में जामुन बेचकर मिले 115 रुपये के बंटवारे को लेकर दो पक्षों में विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। लाठी–डंडों से हुई मारपीट में दो महिलाओं समेत चार लोग घायल हो गए। घायलों में शहजादे आलम का सिर फट गया, जबकि साइमा गंभीर रूप से घायल हुईं। शबाना और जावेद को भी चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। हल्का प्रभारी ऋषभ सिंह चंदेल ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

मंगनी से तीन दिन पहले प्रेमी संग फरार हुई युवती, नकदी–जेवर ले जाने का आरोप

निंदूरा बाराबंकी कैनविज टाइम्स संवाददाता। कुर्सी थाना क्षेत्र में मंगनी से तीन दिन पहले एक युवती के अपने प्रेमी के साथ फरार होने का मामला सामने आया है। युवती के पिता का आरोप है कि अमरसंडा निवासी युवक उनकी पुत्री को बहला–फुसलाकर ले गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि युवती घर से 70 हजार रुपये की नकदी और कीमती जेवरात भी साथ ले गई। आगामी 7 जुलाई को उसकी मंगनी तय थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष कृष्णकांत सिंह ने बताया कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

वाहन चेकिंग के दौरान एआरटीओ सुशील मिश्रा की बिगड़ी तबीयत मचा हड़कंप

पीलीभीत कैनविज टाइम्स संवाददाता। शहर के गौहनिया चौराहे पर शनिवार शाम वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एआरटीओ प्रवर्तन सुशील मिश्रा की अचानक तबीयत बिगड़ गई चक्कर आने से वह सड़क पर गिर पड़े, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लग गई मौके पर मौजूद कर्मचारियों और ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर सिर पर पट्टी की अस्पताल प्रशासन के अनुसार उनकी हालत स्थिर है और निगरानी में रखी गई है डॉक्टरों के मुताबिक, चक्कर आने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर अत्यधिक गर्मी, डिहाइड्रेशन या ब्लड प्रेशर में उतार–चढ़ाव को इसकी संभावित वजह माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: पीलीभीत में 296 जोड़े सात फ़ेरों के बंधन में बंधे, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने दिया आशीर्वाद

पीलीभीत।नवीन मंडी समिति परिसर में शनिवार को समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विधानसभा बीसलपुर क्षेत्र के 296 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया कुल 330में पंजीकृत जोड़ों में से 296 जोड़े, जिनमें 51 अल्पसंख्यक जोड़े भी शामिल रहे ।

कोटवा आश्रम में सत्संग में उमड़ा जनसैलाब, पूज्य देवेंद्र मोहन ''भईया जी'' ने दिया नशा मुक्ति का संदेश

कैनविज टाइम्स संवाददाता

बाराबंकी । कोटवा सडक स्थित दिव्यानंद स्पिरिचुअल फाउंडेशन में शनिवार को वार्षिक सत्संग का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र सहित आसपास के जिलों से हजारों श्रद्धालु पहुंचे।

सत्संग में परम संत स्वामी दिव्यानंद महाराज के उत्तराधिकारी देवेंद्र मोहन भैया जी ने प्रवचन करते हुए कहा कि आज मनुष्य स्वार्थवश मंदिर जाता है। इच्छा पूरी न होने पर वह आस्था से विमुख हो जाता है और धर्म परिवर्तन तक कर लेता है। यह उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि भक्ति श्रद्धा और समर्पण का विषय है, स्वार्थ का नहीं। त'मानव सेवा ही प्रभु भक्ति है'त के सिद्धांत पर जीवन जीने से ही समाज का कल्याण संभव है। स्वामी जी ने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान करते हुए कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों को बर्बाद कर देता है। संस्कारों से जुड़कर ही जीवन सार्थक बनता है।

इस दौरान सत्संगियों ने भजन-कीर्तन कर गुरु का सुमिरन किया। कार्यक्रम में सालिकराम, नरेंद्र यादव, जय सिंह, दिलीप कुमार, मान सिंह, अयोध्या प्रसाद, सुरेश चंद्र शुक्ला, धनंजय मिश्रा, शत्रोहन सिंह, ब्रजेंद्र मोहन, दीपक यादव, लावेश बघेल, विशाल यादव, नरेंद्र गुप्ता,कलराज यादव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

ड्यूटी से लौट रहे बिजली विभाग के कर्मी की सड़क हादसे में मौत, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मारी टक्कर

पूरनपुर।ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे बिजली विभाग के एक निजी कर्मी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई शुक्रवार रात राजीव नगर के पास तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी गंभीर रूप से घायल कर्मी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया जानकारी के अनुसार, पूरनपुर क्षेत्र के ग्राम दूधिया खुर्द निवासी 25 वर्षीय अरविंद बिजली विभाग में बिल रीडिंग का कार्य करते थे शुक्रवार रात करीब नौ बजे वह ड्यूटी समाप्त कर बाइक से घर लौट रहे थे इसी दौरान राजीव नगर के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी टक्कर इतनी भीषण थी ।

युवती की हत्या के आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली

कैनविज टाइम्स संवाददाता

गोंडा । नगर कोतवाली क्षेत्र के माधवपुर चकत्ता गां व में युवती की हत्या के मामले में नामजद आरोपी संजय गौतम शुक्रवार शाम पुलिस मुठभेड़ में घाय ल हो गया।पुलिस के अनुसार, माधवपुर चकत्ता निवासी आरोपी संजय गौतम के दाहिने पैर में गो ली लगी है।उसे पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पता ल में भर्ती कराया गया है।एसपी विनीत जायसवा ल ने बताया कि पोर्टरगंज के पास पुलिस ने आरो पी संजय गौतम की घेराबंदी की तो उसने फायरिं ग शुरू कर दी।जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया।उसके आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है।इससे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती की गला दबाकर हत्या की पुष्टि हो चुकी थी। रिपो र्ट मिलने के बाद मृतका के भाई की तहरीर पर आ रोपी संजय गौतम के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट द र्ज कर तलाश शुरू कर दी गई थी।नगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में खेत के पास गड्ढे में मिले बीस वर्षीय युवती के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई है।रिपोर्ट के अनुसार युवती की गला दबाकर हत्या की गई थी।पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर एक नामजद

आरोपी के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, युवती बृहस्पतिवार सुबह साढ़े सात बजे घर से शौच के लिए निकली थी। काफी देर तक नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।बाद में ग्रामीणों ने गांव के बाहर खेत के समीप एक गड्ढे में उसका शव पड़ा होने की सूचना दी। युवती के गले पर चोट के निशान भी मिले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि के बाद मृतका के भाई की तहरीर पर संजय गौत म के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। तह रीर में आरोप लगाया गया है कि आरोपी अक्सर उसकी बहन का पीछा करता था और कई बार रास्ते में रोकने का प्रयास भी कर चुका था।आरोप है कि उसी ने युवती की हत्या की है।जांच के दौरा न पुलिस को युवती के घर से करीब 100 मीटर दूर एक मड़हे में आरोपी की बाइक खड़ी मिली। उसका मोबाइल फोन भी बंद बताया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने जनपद में की सार्वजनिक सुनवाई

कैनविज टाइम्स संवाददाता

बाराबंकी।उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित लोकसभागार में स्थानीय ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के समकालीन एवं अनुभवजन्य अध्ययन के उद्देश्य से सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई।

सार्वजनिक सुनवाई की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने की। इस अवसर पर आयोग के सदस्य बृजेश कुमार (सेवानिवृत्त डीएनजे), संतोष कुमार विश्वकर्मा (सेवानिवृत्त एडीजे), डॉ. अरविन्द कुमार चौरसिया (सेवानिवृत्त आईएएस) एवं

एस.पी. सिंह (सेवानिवृत्त आईएएस) उपस्थित रहे।

स्थानीय ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं पिछड़ेपन पर आयोग ने आमजन और विभिन्न पक्षों के सुझाव सुने

सुनवाई के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं संबंधित पक्षों ने स्थानीय ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं राजनीतिक पिछड़ेपन से संबंधित अपने सुझाव, अभिमत एवं तथ्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए। आयोग ने सभी पक्षों को गंभीरतापूर्वक सुना तथा प्राप्त सुझावों एवं तथ्यों का परीक्षण कर उन्हें अपनी संस्तुतियों में समुचित रूप से सम्मिलित किए जाने का आश्वासन दिया। आयोग के

अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गठित आयोग का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन का निष्पक्ष, तथ्यपरक एवं अनुभवजन्य अध्ययन करना है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न मंडलों में सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जा रही है, ताकि सभी संबंधित पक्षों के विचारों, सुझावों एवं तथ्यों के आधार पर आयोग अपनी संस्तुतियां तैयार कर सके।

सार्वजनिक सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित लोकसभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया प्रतिनिधियों को सुनवाई की कार्यवाही, आयोग के अध्ययन तथा आगामी कार्ययोजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अन्ना सुदन, जिला विकास अधिकारी भूषण कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

मेस्सी के विश्व कप कैरियर में अब 20 गोल इस बार 'गोल्डन बूट' की दौड़ में आगे

एजेंसी

मियामी गार्डन्स। लियोनेल मेस्सी का गोल करने का सिलसिला जारी है और वह इतनी सहजता से गोल करते हैं कि यह आसान सा लगता है। इसके साथ ही अर्जेंटीना की लगातार दूसरा विश्व कप जीतने की उम्मीदें भी कायम है हालांकि केप वर्दे ने एकबारगी उसके लिये खतरे की घंटी बजा दी थी। विश्व कप में अपने प्रदर्शन से फुटबॉलप्रेमियों का दिल जीतने वाले केप वर्दे को अतिरिक्त समय में 3 . 2 से हराकर अर्जेंटीना ने अंतिम 16 में जगह बनाई। मेस्सी का विश्व कप में लगातार गोल करने का सिलसिला 2022 में मिली खिताबी जीत से चला आ रहा है। उन्होंने मैच के बाद कहा ,'' हमने अच्छा प्रदर्शन किया और जहां गलतियां हुई हैं, उन्हें सुधारना होगा। मेस्सी ने केप वर्दे के खिलाफ 29वें मिनट में विश्व कप के अपने कैरियर का 20वां गोल किया। वह विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में 20 गोल के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं जबकि फ्रांस के काइलियान एमबाप्पे उनसे दो गोल पीछे हैं। इस साल टूर्नामेंट में उनका यह सातवां गोल था और 'गोल्डन बूट' की दौड़ में एमबाप्पे उनसे एक गोल पीछे हैं। पिछले आठ विश्व कप मैचों में मेस्सी 12 गोल कर चुके हैं। मेस्सी के साथ अर्जेंटीना और इंटर मियामी के लिये खेलने वाले रौद्रिगो डि पॉल ने कहा ,'' मेरे लिये उसकी दोस्ती सबसे अहम चीज है और मैं खुशकिस्मत हूं कि इन पलों में उसके साथ मैदान पर हूं। मेस्सी ने मार्तिनेज के पास पर केप वर्दे के स्टार गोलकीपर वोजिन्हा को छकाते हुए यह गोल दागा। मेस्सी और एमबाप्पे के अलावा नॉर्वे के एर्लिंग हालैंड और इंग्लैंड के हैरी केन भी पांच पांच गोल करके विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने के गोल्डन बूट पुरस्कार की दौड़ में हैं। फ्रांस के उस्मान डेम्बेले, स्पेन के मिकेल ओयारजाबाल , ब्राजील के विनिशियस जूनियर और सेनेगल के इस्माइला सार ने चार चार गोल किये हैं। सार दौड़ से बाहर हैं क्योंकि सेनेगल बाहर हो चुकी है। नॉर्वे, इंग्लैंड और फ्रांस अंतिम 16 में हैं। केप वर्दे को हराकर अर्जेंटीना भी वहां पहुंच चुका है। मेस्सी ने कभी गोल्डन बूट नहीं जीता। विश्व कप 2022 में सात गोल करके वह एमबाप्पे से एक गोल पीछे रह गए थे जबकि 2014 में चार गोल करके संयुक्त तीसरे स्थान पर थे। अगर टूर्नामेंट के बाद शीर्ष पर टाई रहता है तो फीफा पहले टाइब्रेकर के रूप में यह देखेगा कि कितने गोल में मदद की है और दूसरा टाइब्रेकर यह होगा कि मैदान पर किसने कम समय बिताया है। एमबाप्पे गोल में सहायता के मामले में मेस्सी से 2-0 से आगे हैं।

शतरंज महासंघ ने पूर्व विश्व चैम्पियन क्रामनिक को निलंबित किया

एजेंसी

बिलिंग्स। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (फिडे) ने पूर्व विश्व चैम्पियन ब्लादीमिर क्रामनिक को कम से कम एक साल के लिये निलंबित कर दिया है जिन्होंने डेनियल नारोदित्स्की समेत साथी खिलाड़ियों पर धोखेबाजी के आरोप लगाये थे जो साबित नहीं हुए। नारोदित्स्की का पिछले साल 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। क्रामनिक ने उन पर धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए इसे सोशल मीडिया पर भी साझा किया था। अमेरिकी ग्रैंडमास्टर नारोदित्सकी ने शिक्षाप्रद यूट्यूब वीडियो और लाइवस्ट्रीम के जरिये खेल के आनलाइन दौर को लाने में मदद की थी। उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया था। क्रामनिक ने एपी को भेजे ईमेल में कहा कि वह इस निलंबन को चुनौती देंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा ,'' मुझे पूरा विश्वास है कि यह अवैध फैसला बदला जायेगा। मैं न्याय और खासकर अपनी प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं को आखिर तक आगे बढ़ाने का इरादा रखता हूं। शतरंज महासंघ ने कहा कि क्रामनिक ने बिना पर्याप्त सबूतों के सार्वजनिक रूप से धोखाधड़ी का आरोप लगाया जो 'साइबर बुलिंग' के खिलाफ उनके नियमों का उल्लंघन है। महासंघ ने कहा कि धोखाधड़ी से निपटना उनकी प्राथमिकताओं में से एक है लेकिन आरोपों पर उनकी प्रक्रियाओं के जरिए ही कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें उचित सबूतों का समर्थन मिलना चाहिए। नारोदित्स्की ने कहा था कि क्रामनिक के आरोपों का उन पर काफी असर पड़ा है। उन्होंने कहा ,'' क्रामनिक के आरोपों के बाद से मुझे लगने लगा है कि अगर मैं अच्छा खेला तो लोगों को गलत ही लगेगा। इसका मुझ पर काफी असर पड़ा है।

फीफा विश्व कप से बाहर होकर भी हीरो बना केप वर्डे, संघर्ष और साहस की लिखी अविस्मरणीय गाथा

एजेंसी

मियामी। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में हार के बावजूद केप वर्डे ने दुनिया को यह संदेश दिया कि जज़्बा और आत्मविश्वास के दम पर छोटे देश भी फुटबॉल की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकते हैं। महज पांच लाख से कुछ अधिक आबादी वाले अफ्रीका के पश्चिमी तट के छोटे द्वीपीय देश केप वर्डे ने विश्व चैंपियन अर्जेंटीना को अतिरिक्त समय तक कड़ी टक्कर दी। आखिरकार 111वें मिनट में डिने बोर्गेस के आत्मघाती गोल की बदौलत अर्जेंटीना ने 3-2 से जीत दर्ज की। मैच के बाद केप वर्डे के डिफेंडर पिको लोप्स ने कहा कि उनकी टीम ने दुनिया को दिखा दिया है कि छोटे देशों के लिए भी कुछ असंभव नहीं है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, ''हम यह दिखाना चाहते थे कि छोटे देश भी बड़े सपने देख सकते हैं। अगर दिल बड़ा हो और विश्वास मजबूत हो, तो कुछ भी संभव है। उम्मीद है कि हमारी टीम ने केप वर्डे के युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया होगा। हमने साबित किया है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ भी मुकाबला किया जा सकता है। 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिन्हा विश्व कप के सबसे चर्चित खिलाड़ियों में शामिल रहे। स्पेन के खिलाफ पहले मैच में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की संख्या करीब 50 हजार से बढ़कर 1.9 करोड़ से अधिक हो गई। उन्होंने कहा, ''विश्व कप में खेलना हमारे पूरे देश का सपना था। हम अगले दौर में पहुंचना चाहते थे, लेकिन हमें अपने प्रदर्शन पर गर्व है। हमने विश्व चैंपियन के खिलाफ पूरी ताकत से मुकाबला किया और सिर ऊंचा रखकर मैदान से लौट रहे हैं। लियोनेल मेसी के शानदार गोल से पिछड़ने के बाद भी केप वर्डे ने हार नहीं मानी। डेरॉय डुआर्टे ने दूसरे हाफ में बराबरी का गोल कर मैच को अतिरिक्त समय तक पहुंचाया।

विश्व कप, एशियाई खेलों से पहले लय में लौटी भारतीय हॉकी टीम, यूरोप में दमदार प्रदर्शन से बढ़ा आत्मविश्वास

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एफआईएच प्रो लीग 2025-26 का समापन शानदार प्रदर्शन के साथ किया। टीम ने यूरोपीय चरण में मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी और पेरिस ओलंपिक 2024 की स्वर्ण पदक विजेता नीदरलैंड को हराया, जबकि दुनिया की तीसरे नंबर की टीम इंग्लैंड के खिलाफ दोनों मुकाबलों में कड़ी टक्कर दी। इन प्रदर्शनों ने यह संकेत दिया कि भारतीय टीम विश्व कप और एशियाई खेलों जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले सही समय पर अपनी सर्वश्रेष्ठ लय हासिल कर रही है। भारतीय टीम का यह सफर तीन अलग-अलग चरणों में आगे बढ़ा। राउरकेला में खेले गए घरेलू चरण में भारत को बेल्जियम और अर्जेंटीना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद टीम ने अपनी कमजोरियों पर काम किया और होबार्ट चरण में सुधार के स्पष्ट संकेत दिए। होबार्ट में भारत ने शुरुआत स्पेन के खिलाफ 0-2 की हार से की, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-2 और स्पेन के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला। हालांकि दोनों मुकाबलों के शूटआउट में भारत को हार मिली। अंतिम मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-1 की बराबरी के बाद शूटआउट 3-1 से जीतकर आत्मविश्वास हासिल किया। होबार्ट चरण में भारतीय रक्षा पंक्ति ने खासा प्रभाव छोड़ा। चार मुकाबलों में टीम ने केवल छह गोल खाए, जिनमें तीन पेनल्टी कॉर्नर और तीन फील्ड गोल शामिल थे। वहीं आक्रमण में भी सुधार देखने को मिला, जहां टीम ने दो फील्ड गोल और दो पेनल्टी कॉर्नर गोल किए। जून में यूरोप चरण शुरू होने तक भारतीय टीम का प्रदर्शन लगातार बेहतर होता गया। रॉटरडैम में भारत ने जर्मनी को 3-1 और नीदरलैंड को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट के सबसे यादगार नतीजे दर्ज किए। दुनिया की दो मजबूत रक्षात्मक टीमों के खिलाफ भारत ने चार मैचों में नौ गोल किए, जिनमें पांच फील्ड गोल और चार पेनल्टी कॉर्नर शामिल रहे। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि भारतीय टीम अब केवल पेनल्टी कॉर्नर पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुले खेल में भी लगातार मौके बनाकर गोल करने में सफल हो रही है। लंदन चरण में भी भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए चारों मुकाबलों में भारत निर्धारित समय में अपराजित रहा। टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ दोनों मैच जीते, जिनमें एक मुकाबले में 7-1 की बड़ी जीत दर्ज की। इंग्लैंड के खिलाफ दोनों मैच ड्रॉ रहे, जिनमें से एक शूटआउट भारत ने अपने नाम किया। लंदन चरण में भारत ने चार मैचों में कुल 13 गोल किए। इनमें सात फील्ड गोल, पांच पेनल्टी कॉर्नर और एक पेनल्टी स्ट्रोक से आया। वहीं रक्षा पंक्ति ने केवल छह गोल खाए, जिनमें सिर्फ एक फील्ड गोल था। यूरोपीय चरण में भारत के लिए सबसे अधिक चार-चार गोल दिलप्रीत सिंह और जुगराज सिंह ने किए। अभिषेक, सुखजीत सिंह और नीलकांत शर्मा ने तीन-तीन गोल किए। कई खिलाड़ियों का गोल करना इस बात का संकेत है कि टीम का आक्रमण अब पहले से अधिक संतुलित और मजबूत हो चुका है।

संक्षिप्त समाचार

फीफा विश्व कप 2026: मेक्सिको-इंग्लैंड प्री-क्वार्टर फाइनल तय समय पर

मेक्सिको सिटी। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में रविवार को मेक्सिको और इंग्लैंड के बीच होने वाला मुकाबला तय समय पर ही खेला जाएगा। द न्यूयार्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मेक्सिको सिटी में दोपहर बाद गरज-चमक के साथ भारी बारिश और संभावित बाढ़ की आशंका के चलते मैच का समय पहले करने पर विचार किया गया था, लेकिन अंततः फीफा ने निर्धारित समय पर ही मुकाबला कराने का फैसला किया। फीफा मौसम और संभावित जलभराव की स्थिति को देखते हुए मैच का समय बदलने पर विचार कर रहा था। हालांकि, बाद में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। फीफा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस मैच के समय में कोई बदलाव दर्ज नहीं है। मेक्सिको के मुख्य कोच जावियर एग्विरे ने संभावित बदलाव का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने मेक्सिको के रेडियो स्टेशन 'रेडियो फॉर्मूला' से बातचीत में कहा, ''यह पेट पर लात मारने जैसा है। हमें अपनी पूरी योजना बदलनी पड़ती। छह घंटे की तैयारी बेकार हो जाती। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। फीफा जो फैसला करेगा, हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन न मैं और न ही मेरे खिलाड़ी इससे खुश हैं। यदि समय बदला जाता तो इसका असर इंग्लैंड की तैयारियों पर भी पड़ता। इंग्लैंड की टीम शुक्रवार देर रात मेक्सिको पहुंचेगी और शनिवार को यूनाम पुमास प्रशिक्षण केंद्र में अभ्यास करेगी। ऐसे में खिलाड़ियों को मेक्सिको सिटी की ऊंचाई के अनुरूप खुद को ढालने के लिए और भी कम समय मिलता। गौरतलब है कि एज़्टेका स्टेडियम समुद्र तल से करीब 2,200 मीटर (7,300 फीट) की ऊंचाई पर स्थित है। खेल विज्ञान विशेषज्ञों के अनुसार, इतनी ऊंचाई पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को पर्याप्त समय तक अनुकूलन की आवश्यकता होती है। यह मुकाबला विश्व कप 2026 के दौरान मेक्सिको सिटी में आयोजित होने वाला पांचवां और अंतिम मैच होगा।

फोर्टिस हेल्थकेयर ने कटक में 300 बिस्तर वाले अस्पताल के लिए डियोन ग्रुप के साथ किया समझौता

नयी दिल्ली। फोर्टिस हेल्थकेयर ने ओडिशा के कटक में 300 बिस्तर वाले नये अस्पताल के लिए डियोन ग्रुप के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत अस्पताल का निर्माण डियोन ग्रुप करेगा जबकि परिचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी फोर्टिस हेल्थकेयर की होगी। कंपनी ने बताया कि कटक के त्रिशूलिया में डियोन रिवरसाइड टाउनशिप में बनने वाले इस नये अस्पताल की लागत लगभग 600 करोड़ रुपये है और इसके तीन से साढ़े तीन साल में पूरा होने की संभावना है। फोर्टिस हेल्थकेयर के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) आशुतोष रघुवंशी ने कहा, ''तीन सौ बिस्तर वाला अत्याधुनिक अस्पताल कटक, भुवनेश्वर और आस-पास के इलाकों के मरीजों के लिए आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा विकास से जुड़े डियोन ग्रुप के प्रवर्तक मनोज साहू ने कहा, ''यह सहयोग३ राज्य के लिए आधुनिक स्वास्थ्य ढांचागत सुविधाएं बनाने के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने और मरीजों को घर के पास अच्छी स्वास्थ सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगी।

आर्थिक और वित्तीय वार्ता में भारत और फ्रांस ने महत्वपूर्ण खनिजों तथा निवेश पर चर्चा की

नयी दिल्ली। भारत और फ्रांस ने महत्वपूर्ण खनिजों, निवेश और वित्तीय संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। यह सहमति फ्रांस के एक्स-एन-प्रोविंस में आयोजित भारत-फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता के दौरान बनी, जिसकी सह-अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके फ्रांसीसी समकक्ष रोलां लेस्क्योर ने की। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'चूंकि विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के व्यापक ढांचे के भीतर भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक संबंध और गहरे हो रहे हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, द्विपक्षीय सहयोग और परिणामोन्मुख समाधानों पर उच्चस्तरीय चर्चा को फिर से शुरू करना आवश्यक हो गया था। बयान के अनुसार, सीतारमण और फ्रांस के अर्थव्यवस्था, वित्त, औद्योगिक, ऊर्जा और डिजिटल संप्रभुता मंत्री, रोलां लेस्क्योर ने फ्रांसीसी जी7 अध्यक्षता के साथ भारत के जुड़ाव के संदर्भ में, जी20 और पेरिस क्लब सहित बहुपक्षीय आर्थिक मंचों में दोनों देशों के रुख में बेहतर तालमेल बिठाने पर चर्चा की।

सरकार ने प्याज की खरीद कीमत 13 फीसदी बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल किया

एजेंसी

नई दिल्ली। सरकार ने प्याज की खरीद कीमत 13 फीसदी बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। इससे प्याज किसानों को बेहतर रिटर्न मिलेगा और बफर खरीद मजबूत होगी। नई दरें 4 जुलाई से प्रभावी हो गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शनिवार को जारी बयान में बताया कि केंद्र सरकार ने 'प्राइस स्टेबलाइजेशन बफर' (कीमतों को स्थिर रखने के लिए बनाए गए स्टॉक) के लिए प्याज की खरीद कीमत 13 फीसदी बढ़ा दी है, जो 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। ये नई खरीद कीमत 4 जुलाई से प्रभावी हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार के 'प्राइस स्टेबलाइजेशन बफर' के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफ़ेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) के जरिए प्याज की खरीद का काम चल रहा है। प्याज खरीद की ये नई कीमत प्याज किसानों को बेहतर आमदनी दिलाएगी और बफर स्टॉक बनाने की कोशिशों में भी मदद करेगी। वहीं, कृषि और किसान कल्याण विभाग के 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, प्याज का उत्पादन 307.37 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) रहने का अनुमान है, जो 2024-25 में हुए 307.67 एलएमटी के उत्पादन के लगभग बराबर है। मंत्रालय ने कहा कि प्याज उत्पादन के इन अनुमानों को देखते हुए इस समय प्याज की कुल उपलब्धता चिंता का विषय नहीं है। हालांकि, कीमतों में सामान्य मौसमी उतार-चढ़ाव के कारण थोड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। वहीं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में स्टॉक का स्तर पर्याप्त है। फिलहाल, प्याज के भंडार में किसी भी तरह की कमी के कोई संकेत नहीं हैं।

भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता हुआ लागू, सीमा-पार निवेश को मिलेगा बढ़ावा

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता (बीआईए) शनिवार से प्रभावी हो गया है। भारत और इजराइल की सरकार ने 8 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में बीआईए पर हस्ताक्षर किए थे। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में बताया कि भारत और इजराइल की सरकार के बीच 8 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश समझौता 4 जुलाई से लागू हो गया है। बीआईए से सीमा पार निवेश में वृद्धि होने और भारत और इज़राइल के बीच आर्थिक साझेदारी के और गहरा होने की उम्मीद है। मंत्रालय ने कहा कि बीआईए द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित और पूर्वानुमानित निवेश वातावरण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस ऐतिहासिक समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सुरक्षित निवेश का माहौल बनाना और सीमा-पार निवेश को बढ़ावा देना है, जिससे द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और गहरी होगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि बीआईए निवेश और निवेशकों के निवेशों की सुरक्षा में मजबूत है, साथ ही साथ वैध सार्वजनिक नीति के उद्देश्यों के अनुरूप संप्रभु नीतिगत स्थान बनाए रखने के लिए पर्याप्त लचीला भी है। यह अंतरराष्ट्रीय निवेश कानून के आधुनिक सिद्धांतों और विकसित होते न्यायशास्त्र को दर्शाता है। भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता की पूरी प्रति वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने खिलौना उद्योग से निर्यात को 10 गुना बढ़ाने का किया आह्वान

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को भारतीय खिलौना निर्माताओं से अगले चार वर्षों में खिलौनों के निर्यात को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत-पेरू के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए चल रही वार्ता के जल्द संपन्न होने की संभावना नहीं है। हालांकि, वाणिज्य मंत्री ने भारत-कनाडा एफटीए के संबंध में सकारात्मक संकेत दिए। पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल बी2बी एक्सपो को संबोधित करते हुए यह बात कही। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भारतीय खिलौना उद्योग से अगले चार वर्षों में खिलौनों के निर्यात को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य तय करने का आह्वान किया। उन्होंने अपने संबोधन में खिलौना उद्योग को आश्वासन दिया कि सरकार गुणवत्ता मानकों (क्यूसीओ) को वापस नहीं लेगी। पीयूष गोयल ने पूरे भारत में खिलौना निर्माण क्लस्टर्स के लिए आधुनिक टेस्टिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। वाणिज्य मंत्री ने 17वें 'टॉय बिज इंटरनेशनल बी2बी एक्सपो 2026' में खिलौना आयात करने वाले देश से निर्यातक बनने तक के भारत के सफर का ज़िक्र करते हुए कहा कि यह सेक्टर और भी तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है क्योंकि हाल ही में संपन्न मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से नए बाजार खुलेंगे। उन्होंने खिलौना उद्योग से कहा कि वे क्वालिटी, सुरक्षा और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को प्राथमिकता दें, ताकि वैश्विक खिलौना निर्माण और निर्यात हब के तौर पर भारत की स्थिति और मजबूत हो सके। गोयल ने यहां आयोजित 17वें 'टॉय बिज इंटरनेशनल बी2बी एक्सपो' से इतर संवाददाताओं से कहा, ''कुछ चिंताएं हैं, कई ऐसे उत्पाद हैं, जहां हम उन्हें बाजार पहुंच की अनुमति नहीं दे सकते। मुझे नहीं लगता कि पेरू के साथ एफटीए बहुत जल्द होने जा रहा है।'' हालांकि, उन्होंने भारत-कनाडा एफटीए के संबंध में सकारात्मक संकेत दिए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि कुछ उत्पादों में बाजार पहुंच संबंधी चिंताओं के कारण भारत-पेरू मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए चल रही बातचीत के जल्द संपन्न होने की संभावना नहीं है। दूसरी ओर भारत-कनाडा एफटीए के संबंध में मंत्री ने बताया कि भारतीय अधिकारियों का एक दल बातचीत के अगले दौर के लिए सोमवार को कनाडा जाएगा। गोयल ने कहा, 'कनाडा के साथ एफटीए वार्ता अच्छी प्रगति पर है। हमारी टीम अगले दौर की बातचीत के लिए सोमवार को जा रही है। हमारी कोशिश है कि हम अगले छह महीनों में इसे अंतिम रूप दे दें। केंद्रीय मंत्री ने यह बताया कि वह 13 जुलाई को विदेश मंत्री एस. जयशंकर और सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ ब्रसेल्स जाएंगे, जहां वे 'भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद' (टीटीसी) की बैठक में हिस्सा लेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत और पेरू के बीच प्रस्तावित एफटीए के लिए बातचीत साल 2017 में शुरू हुई थी। वैश्विक खिलौना बाजार लगभग 120 अरब डॉलर का है लेकिन इसमें भारत की हिस्सेदारी अभी मात्र 0.2 से 0.3 फीसदी है। हालांकि, पिछले चार वर्षों में खिलौनों के निर्यात में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है।

एथनॉल जैसी वैकल्पिक व्यवस्था से ईंधन आयात पर कम होगी निर्भरता : गडकरी

एजेंसी

नयी दिल्ली। पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण के सरकार के कार्यक्रम की कतिपय हलकों में हो रही आलोचना के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वाहनों के लिए ऐसे ईंधन का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा है कि इससे तेल आयात में भारी बचत हो सकती है और वैकल्पिक ईंधनों पर चलने वाले वाहन उपलब्ध हैं।

श्री गड़करी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के व्यापक उपयोग से पेट्रोलियम ईंधन आयात पर होने वाले खर्च का एक बड़ा हिस्सा बचाया जा सकता है और बायो ईंधन के लिए कच्चे माल का उत्पादन करने वाले किसानों और विनिर्माण श्रृंखला से जुड़े सभी हितधारकों को बड़ा लाभ हो सकता है। वह शुक्रवार को चार्टर्ड अकाउंटेंटों (सीए) के एक उप-क्षेत्रीय सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार एथनॉल, मेथनॉल, बायोडीजल, जैसे वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देकर पेट्रोलियम ईंधन के आयात पर देश की निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रही है। मक्का से एथनॉल उत्पादन बढ़ने से किसानों को भी बड़ा आर्थिक लाभ मिल रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि वैकल्पिक ऊर्जा एथनॉल, मिथनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन अब देश के बाजार में उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तेजी से प्रगति कर रहा है और अमेरिका तथा चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। उन्होंने देश को पहले स्थान पर ले जाने के सपने और संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार ऑटोमोबाइल क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ इस लक्ष्य के लिए काम कर रही है। इसी उद्देश्य से सरकार ने वैकल्पिक ईंधनों और नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ रहे हैं और हमारी इसी मेहनत का परिणाम है कि भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक स्कूटरों का निर्यात भी हो रहा है। श्री गडकरी ने कहा कि हाइड्रोजन और अन्य स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकियों के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाएं तैयार करनी होंगी, ताकि तकनीक गांवों तक पहुंचे और ग्रामीणों की आय बढ़े। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दो दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनकी मुलाकात हुई थी। इस दौरान उन्हें बताया गया कि बदरीनाथ और गंगोत्री तक बेहतर सड़क संपर्क बनने के कारण तीर्थयात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तथा जल, जंगल और जमीन पर आधारित आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि आएगी। किसी भी क्षेत्र में ईमानदारी, विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा और पारदर्शिता के साथ किया गया कार्य निश्चित रूप से सफलता दिलाता है। श्री गडकरी ने कहा कि देश की लॉजिस्टिक्स लागत कम करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर तथा आईआईटी मद्रास की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की लॉजिस्टिक्स लागत में लगभग छह प्रतिशत की कमी आई है।

उन्होंने कहा कि पहले भारत की लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मुकाबले लगभग 16 प्रतिशत थी, जबकि अमेरिका और यूरोपीय देशों में यह लगभग 12 प्रतिशत तथा चीन में आठ से नौ प्रतिशत है।

ममता की फटकार के बाद चंद्रिमा ने बंगाल प्रमुख का पद छोड़ा

बागी गुट के तृणमूल भवन पर कब्जे के लिए ठहराया था जिम्मेदार

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी की करीबी और बंगाल टीएमसी अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने शनिवार को अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी द्वारा फोन पर दी गई फटकार के बाद उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। उनका आरोप है कि उन्हें कोलकाता स्थित तृणमूल भवन पर ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट के कब्जे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। शुक्रवार को बागी गुट के तृणमूल भवन पहुंचने के बाद भट्टाचार्य वहां से चली गईं, जिसके बाद बागी नेताओं ने बैठक कर मुख्य गेट के ताले बदल दिए और वहीं से पार्टी संचालन का ऐलान किया।

चंद्रिका भट्टाचार्य ने कहा कि मुझे बहुत बुरा लगा जब ममता बनर्जी मुझे फोन करके कहा कि मैंने पार्टी का कार्यालय बागी गुट को सौंप दिया है, जबकि मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा कैसे किया। साफ है कि मेरी वफादारी और भरोसे पर सवाल उठाए गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जब वे बुनियादी जुड़ाव वाली बातें ही खत्म हो गईं, तो मेरे लिए पार्टी में बने रहने या उसमें लौटने का कोई कारण नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह बागी गुट में शामिल होंगी, तो भट्टाचार्य ने कहा कि जिंदगी में इससे ज्यादा बहुत कुछ है। मैंने अभी यह तय नहीं किया है कि मैं आगे क्या रास्ता चुनूंगी। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विभिन्न बैंकों में मौजूद टीएमसी और उससे जुड़े संगठनों के खातों के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के तौर पर और चुनाव आयोग के समक्ष पार्टी के कामकाज को संभालने के लिए ममता बनर्जी की अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भी अपनी भूमिका छोड़ दी है। इस घटनाक्रम के कुछ ही देर बाद चंद्रिमा भट्टाचार्य को राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के चैंबर में बागी गुट के नेताओं के साथ बैठक करते देखा गया। विधानसभा गेट पर विपक्ष के उप-नेता और बागी गुट के प्रमुख सदस्य संदीपन साहा ने भट्टाचार्य का स्वागत किया। भट्टाचार्य ने यह कदम उनके बेटे सौरव बसु के बागी गुट में शामिल होने और उसकी बैठकों में भाग लेने के कुछ हफ्ते बाद उठाया है। ज्ञात हो कि, भट्टाचार्य को तीन जून को ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में वरिष्ठ नेता सुब्रत बख्शी की जगह राज्य अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने कहा कि मैं इस घटनाक्रम पर विस्तार से टिप्पणी नहीं करूंगा। हालांकि, मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब ममता बनर्जी ने उन्हें सरकार में अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंपी थी, तब भट्टाचार्य के आत्मसम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंची।

इंडिया गठबंधन के साथ मानसून सत्र में विभिन्न मुद्दों पर है सरकार से जवाब मांगने की तैयारी : कांग्रेस

एजेंसी

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि संसद के मानसून सत्र में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, चीन और अमेरिका से जुड़े व्यापारिक मुद्दों, परिसीमन, एक राष्ट्र-एक चुनाव, भ्रष्टाचार के आरोपों तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज सहित विभिन्न जनहित के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शनिवार को यहां एक बयान में कहा कि पार्टी सिर्फ मानसून सत्र की रणनीति पर ही काम नहीं कर रही है बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में भी जुटी है। राज्यों में संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी है और कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के अलावा इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ संसद के भीतर सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को केवल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से ही नहीं, बल्कि भाजपा और चुनाव आयोग के गठजोड़ से भी मुकाबला करना पड़ रहा है। उन्होंने एसआईआर तथा चुनाव संबंधी अन्य प्रक्रियाओं को लेकर द्रमुक और आम आदमी पार्टी सहित विपक्ष के 24 दलों तथा निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल के लिखे संयुक्त पत्र का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है और बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। यदि चुनाव परिणाम पहले से तय होने की धारणा बन जाए तो लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि उच्चतम न्यायालय चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से काम करने का निर्देश देगा।

श्री रमेश ने कहा कि सरकार मानसून सत्र में परिसीमन विधेयक और 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' संबंधी प्रस्ताव फिर ला सकती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा दो-तिहाई बहुमत हासिल कर संविधान में बदलाव करना चाहती है तथा सामाजिक न्याय और आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उनका कहना था कि संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक अब महज औपचारिकता बनकर रह गई है क्योंकि उसमें विपक्ष की बातें सुनी तो जाती हैं लेकिन संसद का वास्तविक एजेंडा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कार्यालय तय करता है। सरकार की विदेश नीति पर श्री रमेश ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान हमारे सुरक्षा बलों ने असाधारण सफलता हासिल की लेकिन भारत की कूटनीति को बड़ा झटका लगा है।

सरकार ने प्याज का खरीद मूल्य 250 रुपये बढ़ा कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल किया

एजेंसी

नयी दिल्ली। केंद्र ने मूल्य स्थिरीकरण योजना के तहत प्याज का सरकारी क्रय मूल्य 13 प्रतिशत (250 रुपये) बढ़ा कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है जो शनिवार से ही प्रभावी हो गया है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश में प्याज की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति सामान्य है पर वर्षा में देरी से प्याज की रोपाई महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ इलाकों में धीमी चल रही है। इससे खास कर प्याज की बड़े स्तर पर खेती करने वाले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों के किसानों को बेहतर मुनाफा मिलेगा और मूल्य स्थिरीकरण बफर-स्टॉक के लिए खरीदारी बढ़ेगी। सरकार प्याज जैसी कुछ फसलों के दामों पर तेज उतार-चढ़ाव के दौर में किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए मूल्य स्थिरीकरण योजना के तहत बफर स्टॉक रखती है। सरकार यह खरीद नाफ़ेड (नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फ़ेडरेशन) और एनसीसीएफ (भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड) के माध्यम से प्याज की खरीद कराती है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार प्याज का खरीद मूल्य 13 प्रतिशत बढ़ा कर 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से 2,125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। संशोधित खरीद मूल्य 4 जुलाई प्रभावी हो गया है। मंत्रालय ने कहा है कि इस निर्णय से प्याज किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी समर्थन मिलेगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, प्याज का उत्पादन 307.37 लाख टन (एलएमटी) होने का अनुमान है, जो वर्ष 2024-25 के 307.67 लाख टन उत्पादन के लगभग बराबर है। उत्पादन अनुमानों को देखते हुए, फिलहाल प्याज की कुल उपलब्धता चिंता का विषय नहीं है, हालांकि कीमतों में सामान्य मौसमी उतार-चढ़ाव के अनुरूप मामूली वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्याज का भंडार पर्याप्त है। फिलहाल, भंडारित प्याज की कमी के कोई संकेत नहीं हैं। अखिल भारतीय स्तर पर मंडियों में प्याज की दैनिक आवक 50,000 टन से अधिक बनी हुई है1 महाराष्ट्र में यह आवक 30,000 टन से अधिक है, और औसत खुदरा मूल्य लगभग 18 रुपये प्रति किलोग्राम है।

बेहतर गुणवत्ता वाला स्टॉक भंडार में बना हुआ है और मंदी के दौर में इसके जारी होने की उम्मीद है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपये प्रति किलोग्राम है। मानसून के आगमन में देरी और कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा के कारण व्यापारियों के एक वर्ग द्वारा सट्टेबाजी के आधार पर खरीदारी की जा रही है, हालांकि प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों में मौजूदा कीमतों पर कोई खास मांग नहीं है। उपभोक्ता बाजारों में सकारात्मक माहौल के बावजूद, नासिक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों जैसे उत्पादन केंद्रों में सट्टेबाजी की गतिविधियां देखी जा रही हैं, जो मजबूत वास्तविक मांग के बजाय भविष्य में बाजार में सुधार की उम्मीदों पर आधारित हैं।

खिलौनों की उच्चस्तरीय जांच, मानक परीक्षण सुविधा स्थापित करके सरकार करेगी उद्योगों की मदद : गोयल

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना उद्योग को आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी मदद के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), नेशनल टेस्ट हाउस तथा अन्य सरकारी एवं अर्ध-सरकारी प्रयोगशालाओं के माध्यम से देशभर के खिलौना विनिर्माण क्लस्टरों में आधुनिक परीक्षण सुविधाएँ स्थापित करेगी। श्री गोयल ने उद्योग जगत से अनुरोध किया कि वे आवश्यक परीक्षण उपकरणों की सूची उपलब्ध कराएँ, ताकि देश में उच्चस्तरीय परीक्षण सुविधाएं स्थापित और संचालित की जा सकें तथा देश में बने खिलौने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए सर्वोच्च गुणवत्ता मानकों को पूरा कर सकें। वाणिज्य मंत्री शनिवार को राजधानी में खिलौना विनिर्मातओं के संघ - टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टाई) की 17वीं टॉय बिज़ इंटरनेशनल बी2बी प्रदर्शनी के दौरान आयोजित एक सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की ओर से निरंतर नीतिगत सहायता और उद्योग द्वारा किए गए नवाचारों के कारण भारतीय खिलौना उद्योग ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछले चार वर्षों में खिलौनों के निर्यात में 239 प्रतिशत वृद्धि और आयात में 32 प्रतिशत की कमी का उल्लेख करते हुए वाणिज्य मंत्री ने इस उद्योग से इस गति को बनाए रखते हुए आगामी वर्षों में दस गुना वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पहले भारतीय खिलौना बाजार का केवल 12 प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादों से पूरा होता था, जबकि आज लगभग 18,000 करोड़ रुपये के बाजार में आयात घटकर केवल 2,500S3,000 करोड़ रुपये रह गया है और शेष मांग भारतीय निर्माता पूरी कर रहे हैं। उन्होंने गुणवत्ता में हुए सुधार की सराहना करते हुए उद्योग को निरंतर सुधार जारी रखने का संदेश दिया। टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया से उन्होंने नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का आग्रह करते हुए कहा कि वर्तमान में उसके लगभग 1,200 सदस्य हैं, जबकि देश में लगभग 21,000 खिलौना निर्माता कार्यरत हैं। उन्होंने सभी निर्माताओं को एक साझा मंच पर लाने की अपील की। श्री गोयल ने उत्पादों की गुणवत्ता, सामग्री, फिनिशिंग और निर्माण मानकों में निरंतर सुधार पर बल दिया। इसी संदर्भ में उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले पेंट, बेहतर फिनिशिंग, सुरक्षित किनारों और टिकाऊ उत्पादों की आवश्यकता बताते हुए उद्योग से आवश्यक परीक्षण उपकरणों की सूची तैयार करने का आग्रह किया। उन्होंने बैच-वार टिकाऊपन, पेंट गुणवत्ता, फिनिशिंग तथा बैटरी चालित और इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के परीक्षण की व्यवस्था विकसित करने का सुझाव दिया, जिससे प्रमाणित उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के माध्यम से भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान बना सकें। उन्होंने कहा कि 'मेक इन इंडिया' के 11 वर्षों में खिलौना उद्योग को व्यापक सहयोग मिला है। वर्ष 2020 में शुरू की गई राष्ट्रीय खिलौना कार्ययोजनाने उद्योग के विकास के लिए स्पष्ट रोडमैप प्रदान किया। उन्होंने बताया कि देशभर में 50 से अधिक खिलौना क्लस्टर स्थापित किए जा चुके हैं तथा लगभग 21,000 एमएसएमई इकाइयाँ इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। इस प्रदर्शनी में 400 से अधिक 'मेड इन इंडिया' खिलौना ब्रांड, 15,000 से अधिक व्यापारिक आगंतुक, 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि तथा खिलौना उद्योग से जुड़े विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया।

पेज एक का शेष

टेलीग्राम पायरेसी...

'मेटा' के खिलाफ की गई नियामकीय कार्रवाई के बाद जारी किया गया है। सरकार ने बुधवार को भारत में व्हाट्सएप के विवादस्पद 'यूजरनेम फीचर' को लेकर मेटा को नोटिस दिया था। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को इंटरनेट कंपनी मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। यह कदम मेटा के मंच इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण सामग्री को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों के आरोपों के बाद उठाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने टेलीग्राम और एक अन्य संदेश सेवा ऐप 'सिग्नल' को उनके मौजूदा 'यूजरनेम फीचर' को लेकर नोटिस जारी किए हैं। इस बीच, सूत्रों ने बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निर्माताओं, ओटीटी मंचों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए टेलीग्राम के शिकायत निवारण तंत्र का विवरण भी मांगा है। उन्होंने कहा कि टेलीग्राम को याद दिलाया गया है कि एक मध्यस्थ के रूप में उसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत समुचित सावधानी बरतना आवश्यक है। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा, ''सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाली सामग्री लगातार उपलब्ध रहने, नियमों के पालन से बचने के प्रयास या अधूरा जवाब दिए जाने पर लागू कानूनी ढांचे के तहत आगे जांच और कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारी ने कहा कि यह कदम भारत में सामग्री बनाने वालों से जुड़ी अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी मंचों, निर्माताओं और वितरकों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है।

शासकीय भूमि से जुड़ा...

क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा और मामलों के अनावश्यक लंबित रहने की संभावना भी कम होगी। व्यवस्थित सूचीकरण और नियमित सुनवाई से न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुचारु एवं परिणामकारी बनेगी। सामूहिक निर्णय प्रणाली अपनाए जाने से न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथ ही विभिन्न प्रकार के समान मामलों में एकरूप निर्णय आने से भविष्य में अनावश्यक विवादों और कानूनी असमंजस की स्थिति भी कम होगी। योगी सरकार पहले ही राजस्व प्रशासन में व्यापक सुधारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल कर चुकी है। डिजिटल भू-अभिलेख, ऑनलाइन नामांतरण एवं अन्य राजस्व सेवाएं, आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भूमि पैमाइश, पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया तथा सरकारी भूमि की सुरक्षा जैसे कदमों ने राजस्व व्यवस्था को अधिक उत्तरदायी बनाया है। अब तीन सदस्यीय विशेष पीठ का गठन इसी सुधार श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी है। विशेषज्ञतापूर्ण सामूहिक निर्णय व्यवस्था से न केवल न्याय वितरण प्रणाली अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनेगी, बल्कि प्रदेश में राजस्व न्याय व्यवस्था के आधुनिकीकरण को भी नई गति मिलेगी।

'संकट की...

120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई और आयात के रास्ते भी बाधित हो गए। दुनिया के अनेक देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40 से 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई तथा कई देशों में ईंधन की राशनिंग करनी पड़ी लेकिन भारत में एक दिन के लिए भी ऐसी स्थिति नहीं आई। मोदी ने कहा कि अप्रैल से जून के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को अकेले 75 हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा, जो एक नई रिफाइनरी बनाने की लागत के बराबर है लेकिन सरकार ने यह बोझ जनता पर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 10 रुपये उत्पाद शुल्क भी कम किया ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट के समय भारत की कूटनीतिक ताकत और दूसरे देशों के साथ मजबूत संबंध बहुत काम आए। उन्होंने कहा कि संकट शुरू होने से पहले भारत केवल 25-26 देशों से ऊर्जा आयात करता था लेकिन युद्ध के दौरान यह संख्या बढ़कर 40 से अधिक देशों तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि उसके लिए राष्ट्रहित और नागरिकों का हित सर्वोपरि है। उन्होंने देशवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कठिन समय में 140 करोड़ भारतीय मजबूती से देश के साथ खड़े रहे और अफवाह, डर तथा भ्रम फैलाने वालों की कोशिशों को नाकाम किया। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत को असफल होते देखना चाहते थे और ऐसी भविष्यवाणियां कर रहे थे, वे आज निराश होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के कई विकसित देशों में नई रिफाइनरियां नहीं बन रही हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में पिछले 50 वर्षों में कोई नई रिफाइनरी नहीं बनी, यूरोप की रिफाइनिंग क्षमता लगातार घट रही है, जबकि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनिंग क्षमता वाला देश बन चुका है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में वर्ष 2018 से 2023 के दौरान कांग्रेस सरकार के समय पचपदरा रिफाइनरी का काम लगभग ठप पड़ा रहा लेकिन भाजपा सरकार ने परियोजना को गति दी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकारें केवल शिलान्यास करके परियोजनाओं को नहीं छोड़तीं बल्कि दिन-रात काम करके उन्हें पूरा भी करती हैं। दो महीने पहले यहां हुई दुर्घटना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके बावजूद परियोजना का पूरा होना परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी और अप्रत्याशित क्यों न हो, नया भारत न अपने संकल्पों से पीछे हटता है और न अपनी रफ्तार कम करता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान उन्हें 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत खेजड़ी का पौधा लगाने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में खेजड़ी का विशेष महत्व है और बढ़ते रेगिस्तान को रोकने में इसकी अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि भारत को विकास की नई ऊंचाइयों को भी छूना है और पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित करना है। मोदी ने कहा कि राजस्थान और हरियाणा सरकारों के बीच हाल ही में हुए समझौते के बाद हथिनीकुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से शेखावाटी क्षेत्र तक पानी पहुंचाया जाएगा। इससे सीकर, चूरू, झुंझुनूं और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 79,450 करोड़ रुपये से अधिक लागत की देश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल परियोजना राष्ट्र को समर्पित करना प्रमुख रहा। 9 एमएमटीपीए क्षमता वाली यह परियोजना देश की ऊर्जा सुरक्षा, पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास को नई गति देगी। इसके अलावा उन्होंने 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला रखी। 41 किलोमीटर लंबे उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर में 36 स्टेशन होंगे, जिससे जयपुर के औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों के बीच सार्वजनिक परिवहन और सुदृढ़ होगा। प्रधानमंत्री ने चूरू-सादुलपुर तथा चूरू-रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं, जोधपुर रिंग रोड के चार लेन खंड, बीकानेर की 1,000 मेगावाट और 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं तथा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी विद्युत पारेषण परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए।

विकसित भारत के...

पर है, ताकि वर्ष 2027 में भाजपा लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना सके।

भारत-इजराइल...

की उम्मीद है। वर्तमान में भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश करीब 80 करोड़ डॉलर है। इस समझौते में निवेश को जब्ती से बचाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सुचारू हस्तांतरण एवं नुकसान की भरपाई के प्रावधान भी शामिल हैं। साथ ही, यह नियामक अधिकारों और निवेशक संरक्षण के बीच संतुलन भी रखा गया है।

'स्वदेशी रक्षा...

विकसित भारत की मजबूत नींव रख रही है और चौथे कार्यकाल में विश्व एक विकसित भारत के उदय का साक्षी बनेगा। रक्षा मंत्री ने पिछले 12 वर्षों में देश में परिवर्तन के प्रमुख पहलुओं के बारे में कहा कि जब 2014 में 'मेक-इन-इंडिया' योजना शुरू हुई तब कुछ लोगों ने इसे असफल बताया था लेकिन इस योजना ने सफलता के नए मानक स्थापित किए और यह आज भी जारी है। उन्होंने कहा, ''भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा में एक परिवर्तनकारी बदलाव आया है। पहले जहां विश्व हमारी बात पर ध्यान नहीं देता था, वहीं आज वह वैश्विक मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण को ध्यान से सुनता है।'' उन्होंने कहा कि 2021 में शुरू किये गये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पर शुरुआती संदेह के बावजूद, 'प्लग-एंड-प्ले' बुनियादी ढांचा मॉडल पर आधारित सेमीकंडक्टर पार्कों की स्थापना के कारण देश ने पिछले साल अपने स्वयं के सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन किया। श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में वार्षिक रक्षा उत्पादन सर्वकालिक उच्च स्तर 1.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह वित्त वर्ष 2014-15 के आंकड़े से तीन गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। यह वित्त वर्ष 2013-14 के 686 करोड़ रुपये से लगभग 57 गुना अधिक है और मेक-इन-इंडिया पहलों में विश्व के विश्वास को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने भारत के विनिर्माण और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि के बारे में बताते हुए मोबाइल विनिर्माण, ऑटोमोबाइल निर्यात, स्वदेशी लोकोमोटिव उत्पादन और मेक-इन-इंडिया के तहत डिजिटल अवसंरचना के विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने स्वदेशी रूप से विकसित मेक-इन-इंडिया 5जी तकनीक के देशव्यापी तीव्र विस्तार की भी बात की और कहा कि 6जी के विकास की दिशा में प्रयास जारी हैं। श्री सिंह ने कहा कि 2014 से पहले, कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में भ्रष्टाचार और गबन को व्यापक रूप से अपरिहार्य माना जाता था जिसके कारण लाभ लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता था। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जन धन, आधार और मोबाइल के त्रिमूर्ति 'जेएएम त्रिमूर्ति' के माध्यम से इस चुनौती का समाधान किया है। रक्षा मंत्री ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयास सरकार के उन मुद्दों को हल करने के दृढ़ संकल्प के ज्वलंत उदाहरण हैं जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। उन्होंने कहा, ''भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम बन गया है। पिछले 12 वर्षों में, स्टार्ट-अप की संख्या 500 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गयी है और यूनिकॉर्न की संख्या चार से बढ़कर 125 हो गयी है।'' श्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की संस्कृति उसकी पहचान, एकता और राष्ट्रीय चेतना की नींव है और सभ्यता, संस्कृति तथा विरासत के संरक्षण के साथ-साथ समग्र विकास को भी आगे बढ़ाया गया है। रक्षा मंत्री ने आज के दौर में मीडिया की भूमिका को 'संचार की प्रचुरता' के युग में पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि चुनौती सूचना की कमी नहीं बल्कि उसकी सटीकता और विश्वसनीयता है। उन्होंने बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी प्रौद्योगिकी प्रगति से 'पत्रकारिता' भी प्रभावित हुई है लेकिन ये मानवीय रचनात्मकता और बुद्धि को पीछे नहीं छोड़ पायेंगी। उन्होंने कहा, ''पत्रकारिता की भविष्य की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह एआई की क्षमताओं और मानवीय सहानुभूति के बीच कितना अच्छा संतुलन और तालमेल स्थापित कर पाती है। जहां एआई पत्रकारिता को तेज और अधिक सटीक बनाएगा, वहीं भावनात्मक बुद्धिमत्ता यह सुनिश्चित करेगी कि यह मानवीय और विश्वसनीय बनी रहे।'' श्री कहा कि पत्रकारिता की असली ताकत सिर्फ सूचना के प्रसार में नहीं बल्कि समाज को सही दिशा में मार्गदर्शन करने, सच्चाई को सामने लाने और लोकतंत्र को मजबूत करने में निहित है। उन्होंने कहा कि गलत सूचना समाज और रक्षा बलों के मनोबल पर गंभीर प्रभाव डालती है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में सबसे पहले खबर देना महत्वपूर्ण हो सकता है लेकिन सही खबरें देना उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ''विशेषकर जब विषय रक्षा बलों, राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वालों के सम्मान से संबंधित हो, तो हर शब्द राष्ट्रीय जिम्मेदारी बन जाता है। मीडिया को हमेशा सटीकता, निष्पक्षता और तटस्थता को बनाये रखना चाहिए।

23 आतंकियों की...

वित्तीय नेटवर्क, आवाजाही, भर्ती तंत्र और आतंक से जुड़ी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही यह राष्ट्रविरोधी और आतंकी गतिविधियों के खिलाफ कड़ा संदेश देगा।''

मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का लोकार्पण व मुनक नहर का किया निरीक्षण

कैनविज टाइम्स संवाददाता

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र एवं पीतमपुरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के साथ-साथ अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पार्कों के सौंदर्यीकरण, आधुनिक जल निकासी व्यवस्था, सीवरेज प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं, सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत पीतमपुरा स्थित बीडी-एफडी पार्क में विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों के लोकार्पण से की। इस अवसर पर पार्क में लगाए गए 93 नए इलेक्ट्रिक पोल एवं आधुनिक लाइट व्यवस्था का भी शुभारंभ किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग क्षेत्र में वर्षा जल निकासी एवं सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा तैयार की गई विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें डीटी मॉल से सीए ब्लॉक तक दोनों ओर प्रीकास्ट ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण, सीए ब्लॉक से शालीमार विलेज चौक अंडरपास, आरयूबी से जीटी करनाल रोड (आजादपुर मंडी गेट) और शालीमार चौक से डीए ब्लॉक तक आधुनिक जल निकासी प्रणाली का निर्माण शामिल है। साथ ही शालीमार गांव, सहीपुर गांव और आसपास के क्षेत्रों में वर्षों से चली आ रही सीवरेज समस्या के स्थायी समाधान के लिए अतिरिक्त सीवेज पंपिंग स्टेशन तथा उससे संबंधित डिलीवरी लाइन का भी लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों को जलभराव एवं सीवरेज संबंधी समस्याओं से स्थायी राहत दिलाने के लिए आधुनिक और दीर्घकालिक अवसंरचना विकसित कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मॉनसून के दौरान नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी परियोजनाओं का प्रभावी संचालन एवं नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। इसके बाद उन्होंने एनपी ब्लॉक डिस्पेंसरी का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं, दवाइयों की उपलब्धता, चिकित्सा उपकरणों और नागरिक सुविधाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इसके बाद सिंघलपुर स्थित मुनक नहर का निरीक्षण किया और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों से जल प्रवाह, नहर के रखरखाव, सफाई व्यवस्था तथा जल प्रबंधन से संबंधित कार्यों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि नहरों एवं जल स्रोतों के संरक्षण और उनकी नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए, जिससे जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय संतुलन दोनों को सुदृढ़ बनाया जा सके। उन्होंने डीएसईयू कस्तूरबा, पीतमपुरा परिसर का निरीक्षण किया और संस्थान में उपलब्ध शैक्षणिक एवं तकनीकी सुविधाओं, प्रशिक्षण अवसंरचना तथा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार युवाओं को रोजगारोन्मुख और आधुनिक तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर निवेश कर रही है, जिससे उन्हें उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें।

दरबार साहिब में मुख्यमंत्री की फोटो वाले पहचान पत्र पहन कर पहुंचे श्रद्धालुओं को रोका

कैनविज टाइम्स संवाददाता

चंडीगढ़। अमृतसर स्थित दरबार साहिब में शनिवार को उस समय विवाद हो गया जब पंजाब के कई शहरों से श्रद्धालु पंजाब के मुख्यमंत्री की फोटो वाले पहचान पत्र गले में पहनकर यहां पहुंचे। श्रद्धालुओं को सेवादारों व टास्क फोर्स ने रोक लिया। सेवादारों का तर्क था कि श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंथ दोखी घोषित किया जा चुका है इसलिए उनकी तस्वीर वाले पहचान पत्र पहनकर गुरु घर में प्रवेश नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद सेवादारों ने श्रद्धालुओं के गले से पहचान पत्र उतरवा दिए। वहीं, तीर्थयात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने कहा कि ये पहचान पत्र उन्हें सरकारी व्यवस्था के तहत दिए गए थे। उनका कहना था कि उनका उद्देश्य केवल श्रीहरमंदिर साहिब में माथा टेकना और दर्शन करना था। अकाल तख्त साहिब ने 15 जून को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंथ दोषी (दोखी) और गुरु विरोधी घोषित किया। गोल्डन टेंपल में

सेवादारों ने गले से उतरवाए पहचान पत्र

मौजूद सेवादारों ने इन पहचान पत्रों पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंथ दोखी घोषित किया जा चुका है इसलिए उनकी तस्वीर वाले पहचान पत्र पहनकर गुरु घर में प्रवेश नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद सेवादारों ने श्रद्धालुओं के गले से पहचान पत्र उतरवा दिए। सिख कौम की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त साहिब ने 15 जून को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंथ दोषी (दोखी) और गुरु विरोधी घोषित किया। यह फैसला अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने अमृतसर में गोल्डन टेंपल परिसर स्थित अकाल तख्त सचिवालय की फसील (प्राचीर) से सुनाया। इस फैसले के पीछे भगवंत मान की कथित शराब वाली वायरल वीडियो का हवाला दिया गया।

संक्षिप्त समाचार

मशरूम उत्पादन इकाइयां लगाने के लिए 80 हजार रुपये तक की रियायत दे रही पंजाब सरकार

चंडीगढ़। पंजाब सरकार फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के प्रयासों के तहत 'राज्य योजना' के अंतर्गत मशरूम उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए अधिकतम 80,000 रुपये तक की रियायत दे रही है। बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि किसान लगभग दो लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक छोटी मशरूम उत्पादन इकाई स्थापित कर सकते हैं। इस योजना के तहत, बागवानी विभाग पात्र लाभार्थियों को 40 प्रतिशत की रियायत प्रदान करता है, और इसकी अधिकतम सीमा 80,000 रुपये तय की गई है। उन्होंने कहा कि मशरूम की खेती के लिए तुलनात्मक रूप से कम भूमि और पानी की आवश्यकता होती है, जबकि कम निवेश में इससे आकर्षक मुनाफा मिलता है। भगत ने बताया कि एक छोटी मशरूम उत्पादन इकाई को लगभग 1,800 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है। इससे छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी इस योजना का लाभ उठाना संभव हो सकेगा। योजना की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि यह इकाई लगाने के इच्छुक किसान 'राज्य योजना' के तहत आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग किसानों को मशरूम की खेती सफलतापूर्वक शुरू करने में मदद करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सभी आवश्यक सहायता भी प्रदान करता है।

पांच साल तक जमे 52 अधिकारियों का स्थानांतरण 19 अधिकारियों को मिली पदोन्नति

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने वित्त एवं लेखा विभाग में व्यापक फ़ेरबदल करते पांच वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत 52 अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है। इनमें 23 डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स और 29 वरिष्ठ लेखाधिकारी शामिल हैं। इसके साथ ही विभाग में कार्यकुशल अधिकारियों को जिम्मेदारी का दायरा बढ़ाते हुए 19 वरिष्ठ लेखा अधिकारियों (सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर) को पदोन्नत कर डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स बनाया गया है। यह जानकारी शनिवार को एक विज्ञप्ति के जरिए दी गई। नई व्यवस्था के अनुसार दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत 19 वरिष्ठ लेखा अधिकारियों को उनकी बेहतर सेवाओं के लिए डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स के पद पर प्रोन्नत किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशानुसार यह तबादले और नियुक्तियां पूर्ण रूप से प्रशासनिक आवश्यकताओं और व्यवस्था में ईमानदारी व पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई हैं। सरकार ने कार्यप्रणाली को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए 23 डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स और 29 सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर्स को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और सुशासन के उच्चतम मानकों पर खरा उतरे। उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था में किसी भी स्तर पर शिथिलता, लापरवाही या भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। वित्त एवं लेखा विभाग में किया गया यह व्यापक प्रशासनिक फ़ेरबदल इसी सोच का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कार्य संस्कृति को अधिक उत्तरदायी, परिणामोन्मुख और जनहित केंद्रित बनाना है। इसी क्रम में सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापन स्थलों पर कार्यभार ग्रहण कर जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस-एसएसबी का संयुक्त गश्ती अभियान, संदिग्ध गतिविधियों पर रखी गई कड़ी नजर

पश्चिम चम्पारण (बगहा)। भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा को लेकर गोबरहिया थाना पुलिस ने थानाध्यक्ष के नेतृत्व में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों के साथ संयुक्त गश्ती अभियान चलाया। अभियान के दौरान सीमा क्षेत्र में आने-जाने वाले लोगों एवं वाहनों की सघन जांच की गई तथा संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी गई। संयुक्त गश्ती के दौरान पुलिस एवं एसएसबी की टीम ने सीमा से सटे संवेदनशील इलाकों का भ्रमण किया और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस अथवा एसएसबी को देने की अपील की। पुलिस अधीक्षक बगहा ने बताया कि भारत-नेपाल सीमा पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने, तस्करी तथा अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से समय-समय पर इस प्रकार के संयुक्त गश्ती अभियान चलाए जाते हैं। आगे भी सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस और एसएसबी द्वारा नियमित रूप से संयुक्त अभियान जारी रहेगा।

पेपर लीक और भर्ती घोटालों के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

हरिद्वार। देशभर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक, भर्ती घोटालों और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर जिला महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमन गर्ग और स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मुरली मनोहर ने कहा कि देश की शिक्षा और भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां इसके विपरीत दिखाई दे रही हैं। उन्होंने मांग की कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अजय गिरी और रचना शर्मा ने कहा कि लाखों अभ्यर्थी वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक, भर्ती में देरी और नकल जैसे मामलों के कारण उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इससे युवाओं में निराशा और असंतोष बढ़ रहा है। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष संतोष चौहान और प्रदेश महासचिव वरुण बालियान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा प्रणाली उपलब्ध कराने में विफल रही है। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंजू मिश्र, महानगर कांग्रेस महासचिव राजीव भार्गव, एससी-एसटी कांग्रेस जिलाध्यक्ष तीर्थ पाल रवि, पार्षद हिमांशु गुप्ता,पार्षद नौमान अंसारी ने चेतावनी दी कि यदि युवाओं के भविष्य से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर जल्द प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को और तेज करेगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस नलिनी दीक्षित, सुमन अग्रवाल, पार्षद महावीर वशिष्ठ, बीपीएस तेजियान, विजय प्रजापति, उज्ज्वल वालिया, हिमांशु राजपूत, मोहित अरियाल, रितेश पांडेय, नंदन शाह, गौरव गोस्वामी, नागेश रावत, मनोज अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बिहार ने रिकॉर्ड 9,155 मेगावाट पीक बिजली मांग का किया सफल प्रबंधन

कैनविज टाइम्स संवाददाता

पटना। बिहार ने विद्युत क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए बीते 3 जुलाई को रात्रि 10:58 बजे राज्य के इतिहास की सर्वाधिक 9,155 मेगावाट पीक बिजली मांग का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया।

रिकॉर्ड मांग के बावजूद पूरे राज्य में उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलती रही। यह उपलब्धि राज्य सरकार द्वारा ट्रांसमिशन एवं वितरण अवसंरचना को मजबूत करने, ग्रिड क्षमता बढ़ाने तथा आधुनिक तकनीकों के उपयोग का प्रत्यक्ष परिणाम है। राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ औद्योगिक, शहरी एवं कृषि क्षेत्रों में भी बिजली की मांग तेजी से बढ़ी है। नए उद्योगों की स्थापना, शहरों का विस्तार, वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि तथा कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए विद्युत आधारित संसाधनों के बढ़ते उपयोग के कारण बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्युत सुविधाओं के व्यापक विस्तार और जीवन स्तर में सुधार से घरेलू उपभोग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इन सभी क्षेत्रों की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत अवसंरचना का निरंतर विस्तार एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिससे प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। बिहार में बिजली की मांग लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। एक दशक पहले जहां राज्य की अधिकतम मांग लगभग 1,800 मेगावाट थी, वहीं अब यह बढ़कर 9,100 मेगावाट से अधिक हो चुकी है। पहले वर्ष में एक बार दर्ज होने वाली उच्चतम मांग अब नियमित रूप से कई बार पार हो रही है। इसके बावजूद विद्युत प्रणाली बिना किसी बड़े व्यवधान के लगातार मांग का सफल प्रबंधन कर रही है, जो राज्य की मजबूत होती बिजली व्यवस्था का स्पष्ट संकेत है। राज्य में ट्रांसमिशन लाइन, ग्रिड उपकेंद्र, पावर ट्रांसफॉर्मर तथा वितरण नेटवर्क की क्षमता में निरंतर वृद्धि की गई है। आधुनिक रियल-टाइम मॉनिटरिंग, प्रभावी लोड मैनेजमेंट और सतत तकनीकी निगरानी के माध्यम से उच्चतम मांग के समय भी ग्रिड की स्थिरता बनाए रखी जा रही है। यही कारण है कि बढ़ती बिजली खपत के बावजूद उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध हो रही है। ऊर्जा विभाग एवं विद्युत कंपनियों द्वारा पूरे विद्युत तंत्र की चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है। संभावित तकनीकी चुनौतियों का पूर्व आकलन कर आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जाती है। वहीं उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 1912 हेल्पलाइन तथा राज्य भर में संचालित फ्यूज कॉल सेंटर निरंतर सक्रिय है, जहां प्राप्त शिकायतों का त्वरित पंजीकरण एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने कहा कि राज्य में बढ़ती बिजली की मांग तेजी से हो रहे चहुंमुखी विकास का परिचायक है। बिहार बिजली के क्षेत्र में पूरे देश को नई दिशा दिखा रहा है। सरकार लोगों को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसी प्रतिबद्धता के अनुपालन में ऊर्जा विभाग लगातार प्रयासरत है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए ऊर्जा परिवार के सभी सदस्यों को मैं हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। ऊर्जा विभाग के सचिव सह सीएमडी अजय यादव (भा.प्र.से.) ने कहा कि राज्य में बिजली की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए ट्रांसमिशन एवं वितरण नेटवर्क का लगातार विस्तार और आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों पर आधारित ग्रिड प्रबंधन, क्षमता वृद्धि तथा रियल-टाइम मॉनिटरिंग के कारण बिहार लगातार रिकॉर्ड पीक डिमांड का सफलतापूर्वक प्रबंधन कर रहा है। साथ ही उपभोक्ताओं को त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शिकायत निवारण तंत्र को भी और अधिक सशक्त बनाया गया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री की विवादित वीडियो पर एसजीपीसी ने बुलाया पंथक सम्मेलन

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कथित विवादित वीडियो को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 05 जुलाई को दरबार साहिब परिसर स्थित मंजी साहिब में पंथक एकत्र आयोजित करने का ऐलान किया है। एसजीपीसी के मुख्य सचिव कुलवंत सिंह मनन ने शनिवार को बताया कि यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा। एसजीपीसी के अनुसार, इस पंथक एकत्र में विभिन्न धार्मिक और पंथक संगठनों की भागीदारी रहेगी। इनमें टकसालें, निहंग सिंह जत्थेबंदियां, कार सेवा संस्थाएं, निर्मला संप्रदाय, सिंह सभाएं और अन्य सिख संगठन शामिल होंगे। कुलवंत सिंह मनन ने कहा कि हाल ही में सामने आई मुख्यमंत्री भगवंत मान की विवादित वीडियो को लेकर सिख समाज में गहरा रोष है। इसी विषय पर विचार-विमर्श करने और आगे की रणनीति तय करने के उद्देश्य से यह पंथक एकत्र बुलाया गया है। एसजीपीसी ने यह भी जानकारी दी कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संगत की सुविधा के लिए जगह-जगह छबीलों की व्यवस्था, तीन मंचों का निर्माण और वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है।

धामी सरकार के पांच वर्ष पूर्ण होने पर हरिद्वार में सेवा पखवाड़े का शुभारंभ

कैनविज टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के सफल पांच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शनिवार को ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में सेवा, सुशासन एवं समर्पण सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने पिछले पांच वर्षों में जनहित, पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने समान नागरिक संहिता (यूसीसी), नकल विरोधी कानून, सशक्त भू-कानून, राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन तथा जी-20 शिखर

सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन उपलब्धियों ने उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। सरकार सेवा, सुशासन और समर्पण की भावना के साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अब तक 33 हजार से अधिक युवाओं को विभिन्न विभागों में नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना है। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बढ़कर 2.76 लाख रुपये से अधिक हो गई है। हरिद्वार जनपद में सड़क, पेयजल, सीवरेज, जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि जगजीतपुर मेडिकल कॉलेज के प्रारंभ होने से क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में हरिद्वार की मेयर किरण जैसल, रुड़की नगर निगम की मेयर अनीता अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा, राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल, ओमप्रकाश जमदग्नि, नितिन गौतम, आदेश सैनी तथा संजय अरोड़ा ने भी धामी सरकार के पांच वर्षों की उपलब्धियों और विकास कार्यों पर अपने विचार व्यक्त किए।

हर्ष फायरिंग मामले में विधायक राजू सिंह को 4 साल कैद की सजा

कैनविज टाइम्स संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 31 दिसंबर 2018 को नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित समारोह में हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत के मामले में बिहार के विधायक राजू सिंह को चार साल की कैद की सजा सुनाई है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने राजू सिंह पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की ये राशि मृतक महिला के पति को दी जाएगी। तीन जुलाई को सुनवाई के दौरान प्रोबेशन अधिकारी ने बताया था कि राजू सिंह के खिलाफ बिहार में हत्या का एक मामला लंबित है जिसमें वो जमानत पर हैं। सुनवाई के दौरान राजू सिंह की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें कम सजा दी जाए। इसके पहले उन्हें किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है और इस मामले में दो महीने जेल में गुजार चुके हैं। उन्होंने कहा कि राजू सिंह छह बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। कोर्ट ने 6 जून को राजू सिंह को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने इस मामले में राजू सिंह की पत्नी रेणु सिंह, राणा राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। कोर्ट ने राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (खंड दो) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी करार दिया था। कोर्ट ने 23 नवंबर 2023 को इस मामले में सभी आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किया था। कोर्ट ने राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (खंड दो) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत, जबकि राजू सिंह की पत्नी रेणु, राणा राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह पर साक्ष्य मिटाने का आरोप तय किया था।

देहरादून को 219 करोड़ की 51 विकास परियोजनाओं की सौगात

कैनविज टाइम्स संवाददाता

ऋषिकेश। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ऋषिकेश के आईडीपीएल ग्राउंड में 'सेवा, सुशासन एवं समर्पणः जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' (सेवा पखवाड़ा) के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर देहरादून जनपद की 219 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।

राज्यपाल गुरमीत ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के रूप में पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर बधाई देते हुए कहा कि यह जनता के विश्वास और विकास की निरंतरता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी), नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और भू-कानून जैसे निर्णय राज्य में सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। केदारनाथ-बदरीनाथ पुनर्विकास, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, जी-20 बैठकों और राष्ट्रीय खेलों जैसे आयोजनों ने उत्तराखंड को विकास और निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार के पांच वर्ष जनसेवा, सुशासन और समर्पण को समर्पित रहे हैं तथा वर्ष 2035 तक उत्तराखंड को विकसित एवं श्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, कृषि और स्वरोजगार के क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई स्टार्टअप नीति, एक जनपद-दो उत्पाद, होमस्टे और सौर स्वरोजगार जैसी योजनाओं से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। लखपति दीदी योजना के तहत 2.65 लाख से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं, जबकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी गई है। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़े के दौरान अधिकारी जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। 'सेवा पखवाड़ा' के तहत शनिवार को आईडीपीएल ग्राउंड में बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया, जिसमें 20 हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया। शिविर के माध्यम से विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ 3,500 से अधिक लोगों को उपलब्ध कराया गया। शिविर में देहरादून, हरिद्वार और टिहरी जनपद के विभिन्न विभागों ने संयुक्त रूप से सेवाएं प्रदान कीं। विभिन्न विभागों के स्टॉलों पर नागरिकों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ मौके पर ही पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया और कई समस्याओं का निस्तारण भी किया गया।

जीवन के अंतिम चरण के मरीजों के लिए सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड गठित

सीवान। जीवन के अंतिम चरण (एंड ऑफ लाइफ केयर) से जुड़े मामलों में चिकित्सकीय निर्णय को अधिक पारदर्शी और विशेषज्ञों की राय पर आधारित बनाने के लिए सिविल सर्जन डॉ. श्रीनिवास प्रसाद ने पांच सदस्यीय सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। यह बोर्ड आवश्यकता पड़ने पर मरीजों के उपचार जारी रखने अथवा वापस लेने जैसे मामलों पर चिकित्सकीय परीक्षण कर अपनी अनुशंसा देगा। सीवान के सिविल सर्जन डॉ. श्रीनिवास प्रसाद ने स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के निर्देश एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। इस संबंध में आदेश जारी कर विभिन्न विशेषज्ञताओं के चिकित्सकों को बोर्ड का सदस्य नामित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, बोर्ड में सदर अस्पताल के जनरल सर्जन डॉ. राजीव कुमार रंजन, मूर्छक डॉ. सदा कमर, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. राघवेंद्र वाजपेई, महाराजगंज अनुमंडलीय अस्पताल के हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉ शैलेश कुमार तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पचरुखी के फिजिशियन डॉ. निखिल कुमार को सदस्य बनाया गया है।

चेयरमैन एवं प्रधान सम्पादक - राकेश कुमार पाण्डेय कार्यकारी सम्पादक* - अरशद सईद खान स्टेट हेड - संदीप मिश्रा

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश कुमार पाण्डेय द्वारा सरस्वती प्रिंटर्स वाटर वर्क्स रोड ऐशबाग, लखनऊ से मुद्रित एवं सी-46, कृष टॉवर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, पिन-226010 से प्रकाशित। * इस अंक में प्रकाशित सभी समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी।

समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय क्षेत्र के ही अधीन होंगे। फोन नं। 0522-4249333 फैक्स नं.- 4249333 e-mail : info@kanwhizztimes.com RNI NO - UPHIN/2012/42063